

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर लेकिन मध्यम गति से बढ़ रही है, जिसमें तेजी से विकसित हो रहे राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्यों के बीच देशों में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। वित्तीय बाजार अवस्फीति की धीमी गति और टैरिफ के संभावित प्रभाव से चिंतित हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। भारत में, उच्च आवृत्ति संकेतक 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान आर्थिक गतिविधि की गति में क्रमिक वृद्धि की ओर इशारा करते हैं, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2025-26 घरेलू आय और खपत को बढ़ावा देने के उपायों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके राजकोषीय समेकन और विकास उद्देश्यों को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित करता है। जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट थी।

परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्यों के बीच स्थिर वृद्धि प्रदर्शित कर रही है, जिनमें से दोनों ने 2025 के दौरान अब तक नीतिगत चर्चा में प्रमुख भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के अपने जनवरी 2025 के अपडेट में अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2025 में 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो 2024 में 3.2 प्रतिशत के करीब है, लेकिन 21वीं सदी के पहले दो दशकों के दौरान देखी गई 3.7 प्रतिशत की औसत से कम है। विकास परिदृश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं - संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में

सुदृढ़ विकास से अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में कमजोरी की भरपाई होने की उम्मीद है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए, 2025 में विकास मोटे तौर पर 2024 के बराबर होने की उम्मीद है। हालांकि, वैश्विक विकास और व्यापार परिदृश्य को उभरते अमेरिकी टैरिफ से अधोगामी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिसका समय और परिमाण अत्यधिक अनिश्चित है। अमेरिकी व्यापार नीति अनिश्चितता 2019 के अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध के दौरान देखे गए स्तरों तक बढ़ गई है और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों और विखंडन से वैश्विक व्यापार पैटर्न में अल्पकालिक व्यवधान के बजाय दीर्घकालिक बदलाव हो सकता है, और उपभोक्ता एवं व्यावसायिक लागतों पर ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ सकता है।¹

वैश्विक वित्तीय बाजार संकट में हैं, हर आने वाली सूचना के कारण तेज उतार-चढ़ाव हो रहा है। अमेरिकी प्रशासन में बदलाव और कॉरपोरेट आय में सुधार के बाद अमेरिकी इक्विटी बाजारों में तेजी आई।² हालांकि, डीपसीक³ द्वारा आर1 के लॉन्च ने ऐसे आघात उत्पन्न किए कि एक ही दिन (27 जनवरी, 2025) में इक्विटी मूल्य से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो गया। सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में दोतरफा उतार-चढ़ाव जारी है। टैरिफ घोषणाओं के बाद अमेरिकी डॉलर सूचकांक में उछाल आया, जिससे उभरते बाजारों से पूंजी का बहिर्वाह हुआ और मुद्रा दबाव में तेजी आई। अधिक अनुकूल बाहरी वातावरण को बढ़ावा देने, व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने, संरचनात्मक बाधाओं को कम करने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए ठोस नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता होगी ताकि कम आय वाले कई देशों के 2050 तक मध्यम आय की स्थिति तक नहीं पहुंच पाने के जोखिम से बचा जा सके।⁴

वैश्विक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) 2024 में घटकर 5.7 प्रतिशत (एक साल पहले की तुलना में 100 बीपीएस

* यह आलेख रेखा मिश्र, जी.वी. नथनएल, रजनी दहिया, दुर्गा जी, अर्पिता अग्रवाल, हर्षिता केशन, रमेश गुप्ता, हरेंद्र बेहरा, नीलिमा केएम, सत्यार्थ सिंह, एलिस सेबेस्टियन, ऐडम अभिम्नू यादव, हर्षिता यादव, सिद्धार्थ आर्य, सत्येन्द्र कुमार, अर्चना दिलीप, अगमनी साहा, दिव्यारका चौले, श्रुतमा रे, शिवम, खुशी सिन्हा, कार्तिकेय भार्गव, युवराज कश्यप, निखिल प्रकाश कोसे, आशीष खोबरागड़े, दिलप्रीत शर्मा और अवंनीश कुमार द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ विश्व आर्थिक मंच, मुख्य अर्थशास्त्रियों का परिदृश्य, जनवरी 2025; पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, "ट्रम्प के धमकी भरे टैरिफ से अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और चीन की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होने का अनुमान है", 17 फरवरी, 2025; फाइनेंशियल टाइम्स, "ट्रम्प टैरिफ का खतरा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ाता है, आईएमएफ ने चेतावनी दी", 11 जनवरी, 2025।

² अमेरिकी बेंचमार्क एसएंडपी 500 इंडेक्स 10-25 जनवरी, 2025 के दौरान 5.0 प्रतिशत बढ़ा।

³ आर1, एक बड़ा भाषा मॉडल (एलएलएम) है, जिसे डीपसीक, एक चीनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कंपनी द्वारा मौजूदा एलएलएम की तुलना में बहुत कम कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करके बहुत कम लागत पर विकसित किया गया है।

⁴ वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ, विश्व बैंक, जनवरी 2025।

कम) हो गई।⁵ ईई के मामले में गिरावट अधिक स्पष्ट थी, हालांकि हाल के प्रकाशनों ने प्रमुख ईई में मुद्रास्फीति में वृद्धि दिखाई है, जिसमें सेवा मुद्रास्फीति सुदृढ़ सिद्ध हुई है। मुद्रास्फीति और विकास के अलग-अलग परिणाम मौद्रिक नीति क्रियाओं में भी परिलक्षित होते हैं - अमेरिका दरों को स्थिर रखता है, यूके और यूरो क्षेत्र कटौती का विकल्प चुनता है, और जापान अपनी दर बढ़ाता है। मुद्रा और वित्तीय बाजारों पर व्यापार संघर्षों का संभावित प्रभाव नीति निर्माताओं के सामने आने वाले विकल्पों को और भी उलझा देता है।

इस चुनौतीपूर्ण और तेजी से अनिश्चित वैश्विक वातावरण में, प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है।⁶ उच्च आवृत्ति संकेतक दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था 2024-25 की पहली छमाही में देखी गई गिरावट से दूसरी छमाही के दौरान वृद्धि में सुधार की राह पर है। औद्योगिक गतिविधि में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है, जैसा कि जनवरी में क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में परिलक्षित होता है। ट्रैक्टर की बिक्री में वृद्धि, और ईंधन की खपत में तेजी, तथा हवाई यात्री यातायात में निरंतर वृद्धि भी समग्र गति में सुधार की ओर इशारा करती है। कृषि आय में वृद्धि के कारण ग्रामीण मांग में तेजी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों की बिक्री 2024-25 की तीसरी तिमाही में 9.9 प्रतिशत बढ़ी।⁷ रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उद्यम सर्वेक्षण इस आकलन की पुष्टि करते हैं (अनुलग्नक 1)। सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों ने शुरुआती परिणामों के अनुसार तीसरी तिमाही के दौरान बिक्री वृद्धि में तेजी दर्ज की। क्रमिक आधार पर, परिचालन लाभ मार्जिन भी बेहतर बिक्री वृद्धि के अनुरूप अधिक रहा है। निजी क्षेत्र के निवेश इरादे स्थिर रहे, बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 2024-25 की तीसरी तिमाही में करीब एक लाख करोड़ रुपये रही। पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में भी तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्रीय बजट 2025-26 में व्यय की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उपभोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय/जीडीपी अनुपात को 2024-25 (संशोधित अनुमान) के 4.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 में 4.3 प्रतिशत करने का अनुमान है।

वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक परिदृश्य के बारे में अनिश्चितता का असर घरेलू इक्विटी बाजारों पर पड़ा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से बिकवाली के दबाव के कारण बेंचमार्क और व्यापक बाजारों में गिरावट आई क्योंकि भावनाएं कमजोर रहीं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण भारतीय रुपये में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरह गिरावट आई है। मजबूत सूक्ष्म-वित्त आधार और बाहरी क्षेत्र की सुभेद्यता के विभिन्न उपायों में सुधार ने भारत को वैश्विक अनिश्चितता की मौजूदा लहर से उबरने में मदद की है।

जनवरी 2025 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर पांच महीने के निचले स्तर 4.3 प्रतिशत पर आ गई, क्योंकि खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार में सर्दियों की फसलों के आने से प्रेरित थी। कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति ने मई 2024 से धीरे-धीरे वृद्धि दिखाई है, लेकिन 4 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

फरवरी 2025 की द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया, क्योंकि वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता ने वृद्धि का समर्थन करने के लिए नीतिगत स्थान बनाया, जबकि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया। एमपीसी ने उल्लेख किया कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता और वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में निरंतर अनिश्चितताएं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ, विकास और मुद्रास्फीति के परिदृश्य के लिए जोखिम पैदा करती हैं। तदनुसार, एमपीसी ने एक

⁵ आईएमएफ डब्ल्यूईओ जनवरी 2025 अपडेट।

⁶ आईएमएफ ने 2025 के दौरान भारत के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है (डब्ल्यूईओ, जनवरी 2025), जबकि विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि 6.7 प्रतिशत (जीईपी, जनवरी 2025) आंकी है।

⁷ Nनीलसनआईक्यू इंडिया एफएमसीजी तिमाही स्नैपशॉट- ति4- 2024।

तटस्थ रुख जारी रखने के लिए मतदान किया, जो विकसित हो रही व्यापक आर्थिक स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

II. वैश्विक स्थिति

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर लेकिन मध्यम गति से बढ़ रही है, हालांकि विकास के दृष्टिकोण विभिन्न देशों में काफी भिन्न हैं। जनवरी 2025 के अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अक्टूबर डब्ल्यूईओ परिदृश्य की तुलना में 10 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि के साथ 2025 के लिए विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 3.3 प्रतिशत कर दिया, जबकि 2026 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 3.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (जीडीपी) [सारणी II.1] में मोटे तौर पर इसी तरह का आकलन साझा किया है।

सारणी II.1: 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिंदा आई और ईएमई

(प्रतिशत)

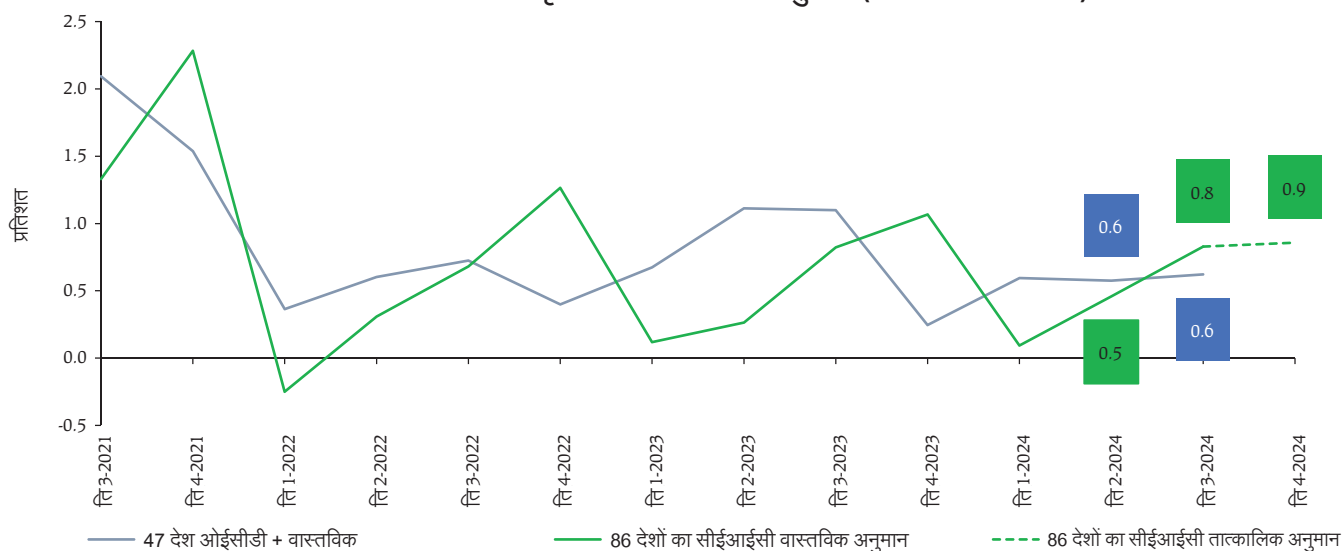
देश	आईएमएफ		विश्व बैंक	
	जनवरी 2025 (नवीनतम)	अक्टूबर 2024 (पिछला)	जनवरी 2025 (नवीनतम)	जून 2024 (पिछला)
 विश्व*	3.3	3.2	3.2	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ				
 यूएस	2.7	2.2	2.3	1.8
 यूके	1.6	1.5	-	-
 यूरो क्षेत्र	1.0	1.2	1.0	1.4
 जापान	1.1	1.1	1.2	1.0
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ				
 ब्राज़िल	2.2	2.2	2.2	2.2
 रूस	1.4	1.3	1.6	1.4
 भारत*	6.5	6.5	6.7	6.7
 चीन	4.6	4.5	4.5	4.1
 दक्षिण अफ्रीका	1.5	1.5	1.8	1.3

नोट: *: पीपीपी भारिता #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।

स्रोत: आईएमएफ; और विश्व बैंक।

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हमारा मॉडल-आधारित पूर्वानुमान 2024 की चौथी तिमाही में वैश्विक विकास की गति में मामूली तेजी का संकेत देता है (चार्ट II.1)।

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक अनुमान (तिमाही-दर-तिमाही)



स्रोत: सीईआईसी, ओईसीडी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और प्रमुख ईएमई में उपभोक्ता भावनाएँ खराब हो गईं, जबकि जनवरी 2025 में यूरो क्षेत्र में इसमें सुधार हुआ (चार्ट 11.3ए और 11.3बी)। प्रमुख एई में

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जनवरी 2025 में 12 महीने के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी की भरपाई सेवा क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि वृद्धि में मंदी से हो गई (चार्ट II.4)। जहां वैश्विक विनिर्माण पीएमआई विस्तार क्षेत्र में वापस आ कर 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, वहीं वैश्विक सेवा पीएमआई धीमी नई व्यावसायिक वृद्धि के कारण 13 महीने के निचले स्तर पर गिर गया।

जनवरी 2025 में, व्यापार नीति अनिश्चितता महामारी की शुरुआत के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई (चार्ट 11.5), जो मुख्य रूप से अमेरिकी प्रशासन में बदलाव और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की ओर से संभावित जवाबी उपायों के

ए. वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई)

औसत मूल्य से मानक विचलन

बी. भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक

सूचकांक

सी. बाल्टिक शुष्क सूचकांक

सूचकांक

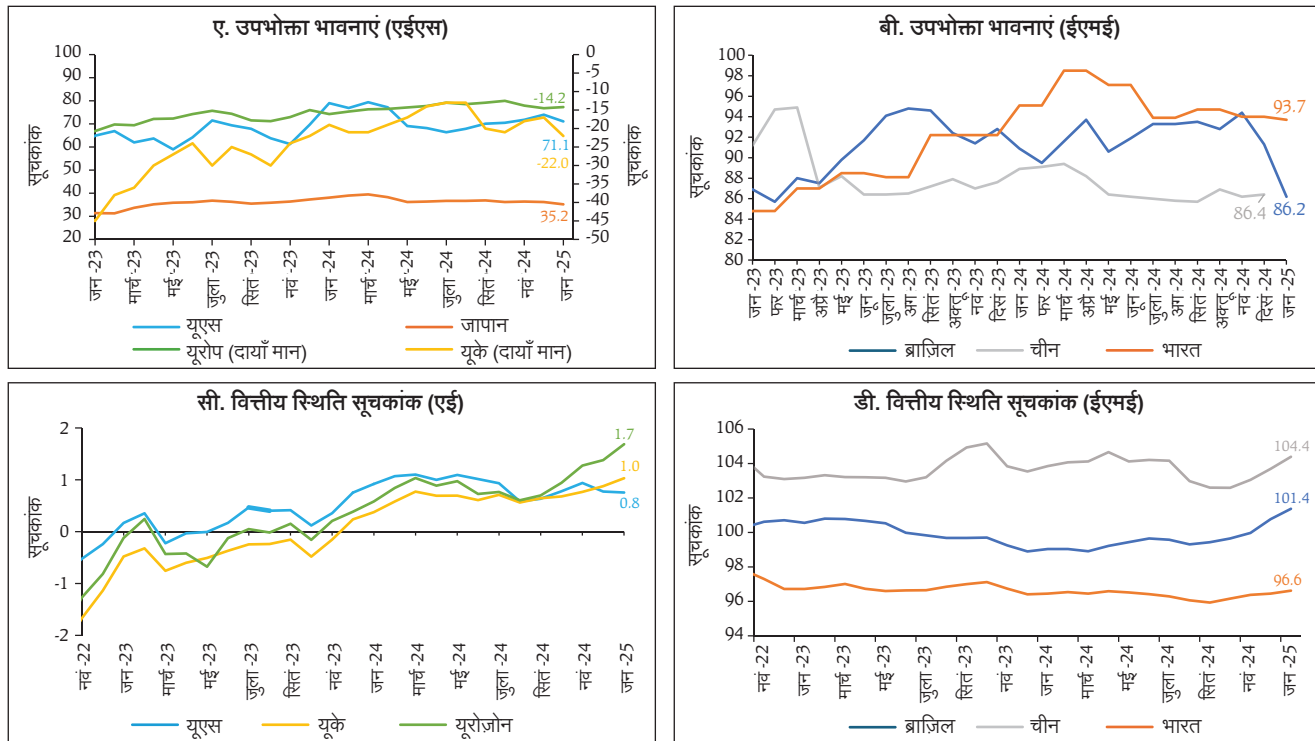
डी. ड्रयूरी वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स (डबल्यूसीआई)

प्रति 40 फीट कंटेनर अमेरिकी डॉलर

टिप्पणियाँ: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।
2. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स समुद्र के रास्ते प्रमुख कच्चे माल की दुलाई की कीमत के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करता है और इसमें तीन उप-सूचकों शामिल हैं जो ड्राई बल्क कैरियर के विभिन्न आकारों को मापते हैं।
3. ड्यूरी द्वारा साप्ताहिक रूप से मूल्यांकन किया गया डबल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल दुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। समग्र रूप से उक्त मान मात्रा के आधार पर 8 शिपिंग मार्गों के भास्ति औसत का प्रतिनिधित्व करता है और इसे प्रति 40-फुट कंटेनर अमेरिकी डॉलर में रिपोर्ट किया जाता है।

स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरोक इनवेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, जनवरी 2025; और ब्लूमबर्ग

चार्ट II.3: उपभोक्ता भावना और वित्तीय स्थितियाँ



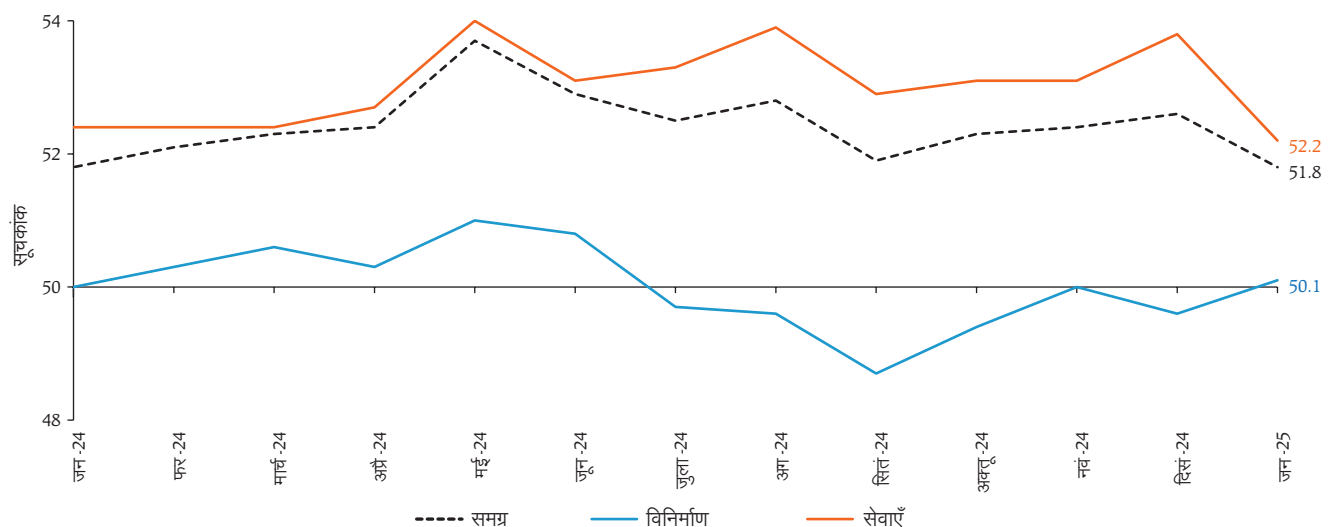
- टिप्पणियाँ:**
1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे का स्कोर उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है तथा 50 तटस्थता को दर्शाता है।
 2. यूरो ज़ोन और यूके: -100 अत्यधिक अविश्वास को दर्शाता है, 0 तटस्थता को दर्शाता है जबकि 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
 3. भारत और अमेरिका: सूचकांक मूल्य जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास भी उतना ही अधिक होगा।
 4. वित्तीय स्थिति सूचकांक (गोल्डमैन सैक्स द्वारा निर्मित ईएमई से संबंधित) के लिए, 100 से नीचे का मान समायोजनात्मक है और इसके विपरीत। ईई के लिए, ब्लूमबर्ग द्वारा निर्मित सूचकांक एक जेड-स्कोर है जहाँ एक धनात्मक मान समायोजनात्मक/आसान वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है और इसके विपरीत।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

बाद नए व्यापार प्रतिबंधों, टैरिफ वृद्धि और कठोर आव्रजन नीतियों की चिंताओं से प्रेरित थी।

आईएमएफ ने विश्व व्यापार मात्रा (वस्तुओं और सेवाओं) की वृद्धि को 2025 के लिए 20 बीपीएस घटाकर 3.2 प्रतिशत

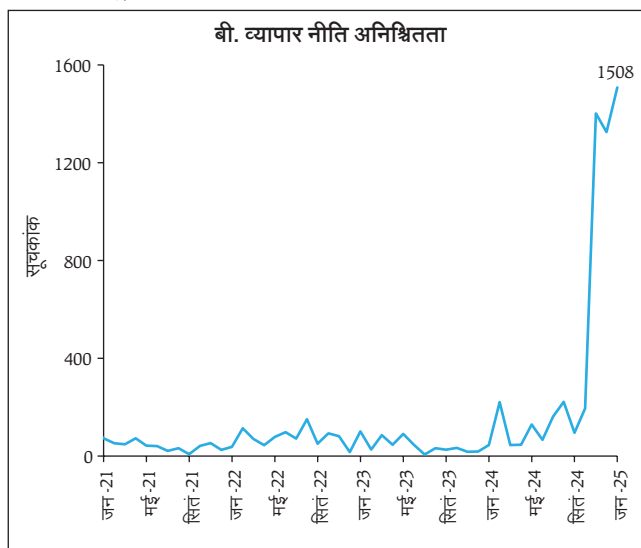
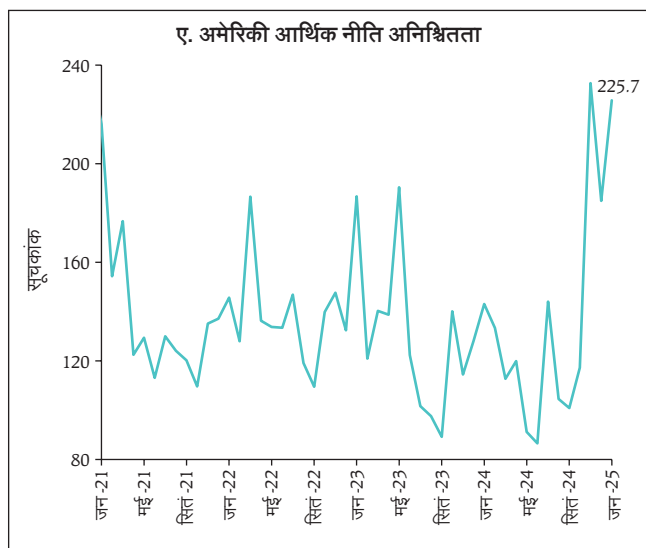
चार्ट II.4: वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट II.5: नीति अनिश्चितता सूचकांक



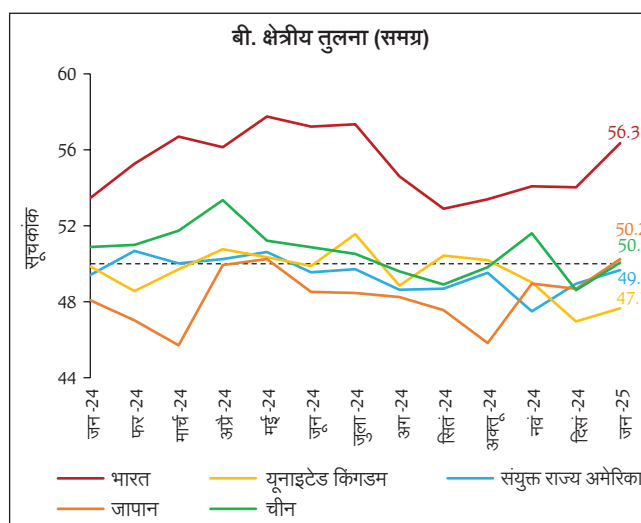
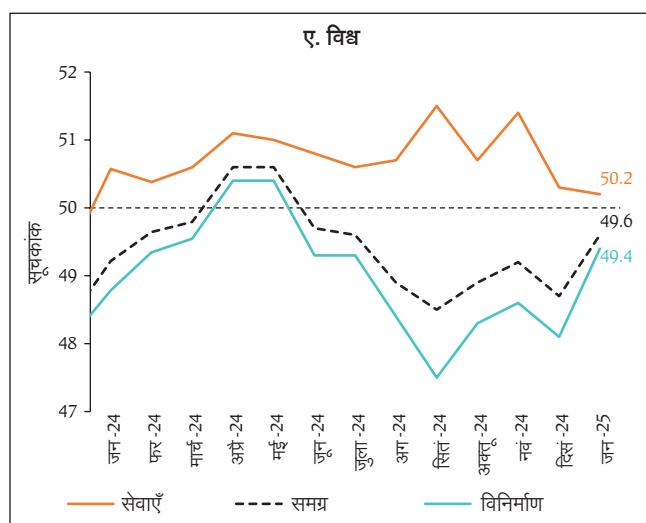
स्रोत: एनवाई फेड फ्रेड डेटाबेस; और बेकर, ब्लूम, और डेविस (2016)।

और 2026 के लिए 10 बीपीएस घटाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया है।⁸ जनवरी 2025 में नए निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई संकुचन क्षेत्र में रहा, जबकि विनिर्माण निर्यात ऑर्डर में वृद्धि के कारण क्रमिक वृद्धि हुई, जिसने सेवा निर्यात ऑर्डर में गिरावट की भरपाई की। जापान, भारत और चीन के निर्यात सूचकांकों में विस्तार दर्ज किया गया,

जबकि अमेरिका और यूके में संकुचन देखा गया (चार्ट II.6ए और II.6बी)।

जनवरी में वैश्विक पण्य की कीमतों में आम तौर पर बढ़ोतरी हुई है जैसा कि ब्लूमबर्ग पण्य सूचकांक में परिलक्षित होता है, जिसमें 3.6 प्रतिशत की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है (चार्ट II.7ए)। रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों

चार्ट II.6: वैश्विक पीएमआई: नए निर्यात ऑर्डर

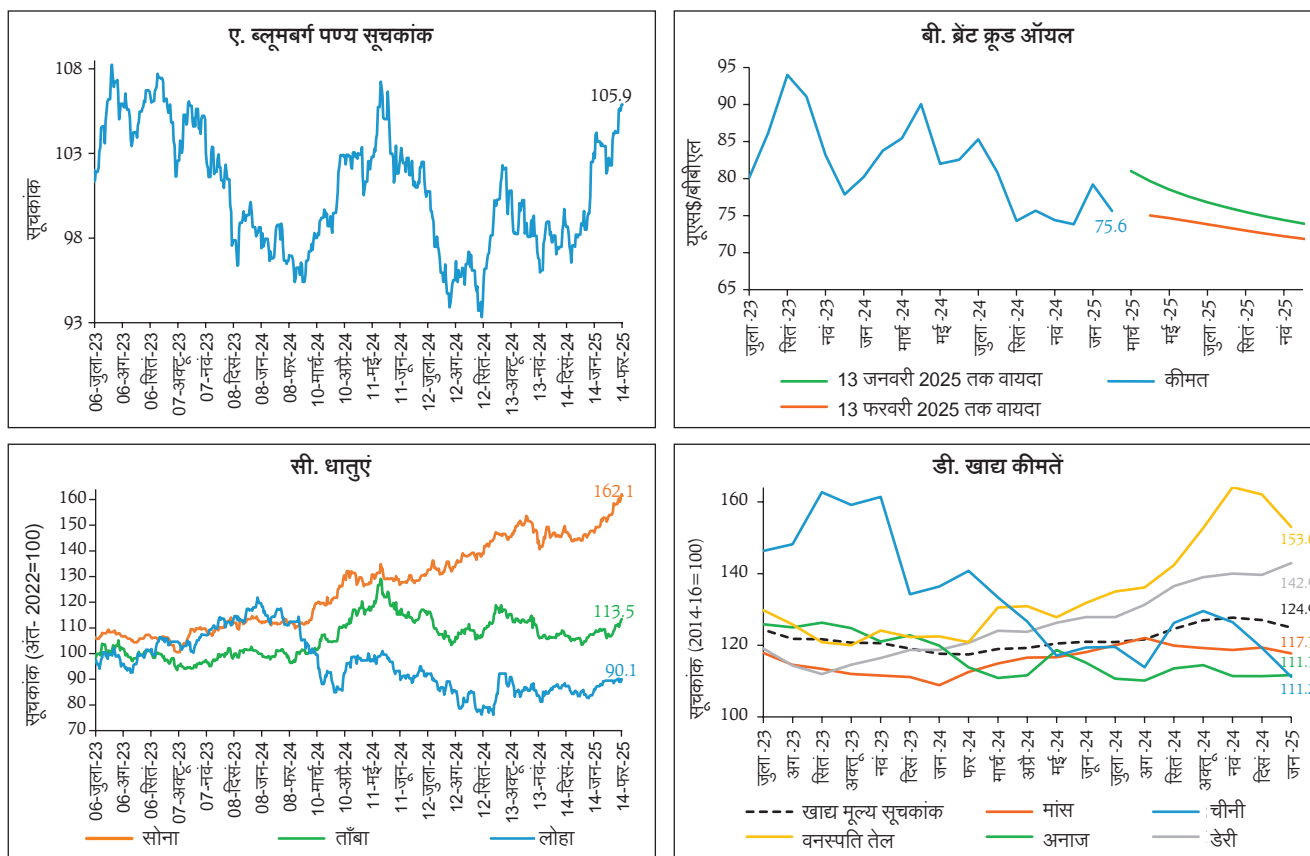


टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

⁸ आईएमएफ डब्ल्यूईओ जनवरी 2025 अपडेट।

चार्ट II. 7: पण्य और खाद्य वस्तुओं की कीमतें



स्रोत: ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिक शीट; तथा एफएओ।

और ठंड के मौसम में मांग बढ़ने के बीच जनवरी में कच्चे तेल की कीमतों में 7.2 प्रतिशत (मासिक) की बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.7बी)। आधार धातुओं के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों का संकेत देने के बाद जनवरी में आधार धातुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। जनवरी में कीमती धातुओं, खास तौर पर सोने की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसे भू-आर्थिक और व्यापार अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित-आश्रय मांग से समर्थन मिला (चार्ट II.7सी)। एफएओ के खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य कीमतों में जनवरी 2025 में (-) 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से चीनी, वनस्पति तेल और मांस की कीमतों में कमी के कारण हुई, जिसे डेयरी और अनाज की कीमतों में वृद्धि से आंशिक रूप से समायोजित किया गया (चार्ट II.7डी)।

अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर में 2.9 प्रतिशत से जनवरी में बढ़कर 3.0 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) अपस्फीतिकारक के संदर्भ में मुद्रास्फीति भी नवंबर में 2.4 प्रतिशत से दिसंबर में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गई। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर में 2.4 प्रतिशत से जनवरी में 2.5 प्रतिशत हो गई। जापान में मुद्रास्फीति (ताजा भोजन को छोड़कर सीपीआई) दिसंबर में बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गई, जबकि यूके में यह 10 बीपीएस घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.8 ए) । ईएमई में, चीन में सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी में पांच महीने के उच्च स्तर 0.5 प्रतिशत पर पहुंच गई; रूस और दक्षिण अफ्रीका में भी दिसंबर में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई; अमेरिका और यूरो क्षेत्र दोनों में सेवा मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन यह उच्च स्तर पर बनी हुई है (चार्ट II.8सी और II.8डी)।

मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व इक्विटी सूचकांक जनवरी में 3.3 प्रतिशत (माह दर माह) बढ़

चार्ट ॥.८: मुद्रास्फीति - आई और ईएमई



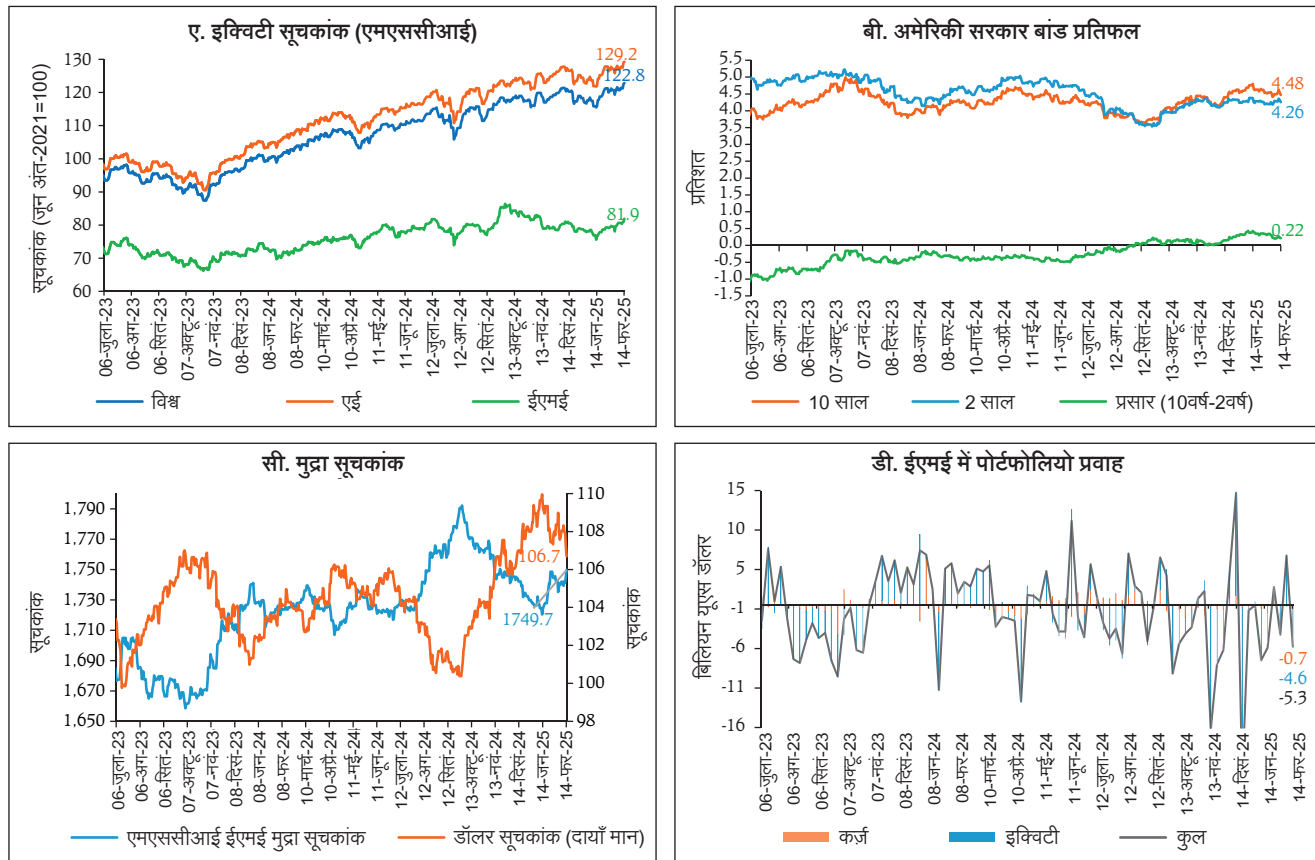
स्रोत: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी।

गया, जिसमें आई इक्विटी बाजारों में ईएमई की तुलना में अधिक लाभ हुआ, भले ही नीति अनिश्चितता के कारण अस्थिरता अधिक रही (चार्ट ॥.९ए)। जनवरी के पहले पखवाड़े में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल मजबूत हुआ क्योंकि कम बेरोजगारी के बीच मजबूत खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन जैसे डेटा जारी होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मजबूती का संकेत मिला। दूसरी छमाही में प्रतिफल कम हो गया, क्योंकि मुद्रास्फीति के डेटा जारी होने और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के बयान ने अनिश्चितता को कम करने में मदद की। उम्मीद से अधिक सीपीआई मुद्रास्फीति के कारण फरवरी में प्रतिफल में फिर से वृद्धि हुई (चार्ट ॥.९बी)। जनवरी के पहले पखवाड़े में यूएस डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) में वृद्धि हुई, लेकिन बाद में इसने अपने कुछ लाभ खो दिए। नए यूएस प्रशासन द्वारा व्यापार नीति उपायों की घोषणाओं के प्रतिउत्तर में डीएक्सवाई अस्थिर रहा। ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा

सूचकांक ने डीएक्सवाई में उतार-चढ़ाव को प्रतिबिंबित किया, जिसमें पूंजी बहिर्वाह, विशेष रूप से इक्विटी खंड में, नीचे की ओर दबाव डाला गया (चार्ट ॥.९सी और ॥.९डी)।

विभिन्न देशों में मौद्रिक नीति कार्रवाइयों में भिन्न-भिन्न समष्टि आर्थिक स्थितियाँ प्रतिबिंबित होती हैं। आई केंद्रीय बैंकों में, यूएस, दक्षिण कोरिया और नॉर्वे ने अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। इसके विपरीत, यूरो क्षेत्र, कनाडा और स्वीडन ने जनवरी में अपनी नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की, जबकि यू.के. और चेक गणराज्य ने फरवरी में अपनी प्रमुख दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की (चार्ट ॥.१०ए)। हालाँकि, जापान ने अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, चीन, चिली, हंगरी, कोलंबिया, मलेशिया, फिलीपींस और पेरू ने अपनी नीतिगत दरें बनाए रखीं। दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने जनवरी 2025 में अपनी नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की,

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाज़ार

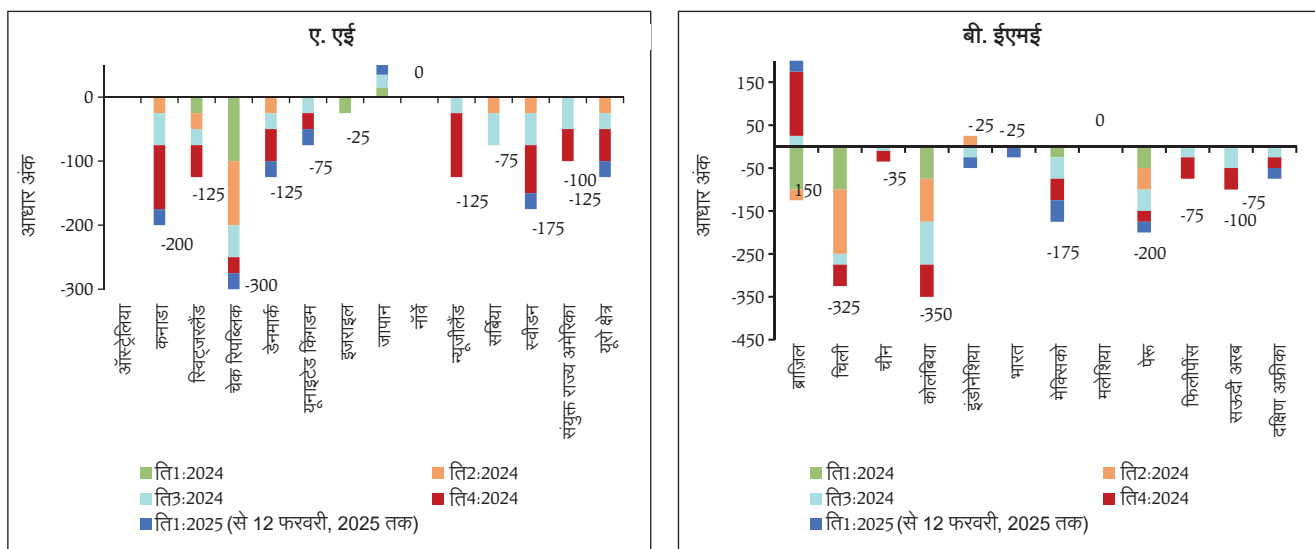


स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

जबकि मेक्सिको और भारत ने फरवरी में अपनी बेंचमार्क दरों में क्रमशः 50 आधार अंकों और 25 आधार अंकों की कटौती की।

दूसरी ओर, ब्राजील ने जनवरी में इसमें 100 आधार अंकों की वृद्धि की (चार्ट II.10बी)।

चार्ट II.10: नीति दरों में परिवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोग मांग और समग्र निवेश में सुधार के कारण अपनी वृद्धि की गति को पुनः प्राप्त कर रही है। जनवरी 2025 में आरबीआई के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, उपभोक्ता विश्वास आशावादी बना हुआ है, भविष्य की अपेक्षा सूचकांक (एफईआई) आशावादी क्षेत्र में दृढ़ता से बना हुआ है, हालांकि इसमें थोड़ी क्रमिक नरमी आई है, हालांकि वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) निराशावादी क्षेत्र में बना हुआ है (चार्ट III.1ए)। जनवरी में मामूली वृद्धि के बावजूद आपूर्ति शृंखला दबाव ऐतिहासिक औसत स्तरों से नीचे रहा (चार्ट III.1बी)। सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर निर्मित आर्थिक गतिविधि सूचकांक, यह दर्शाता है कि जनवरी में गतिविधि ने अपनी गति बनाए रखी और 2024-25 की चौथी तिमाही के

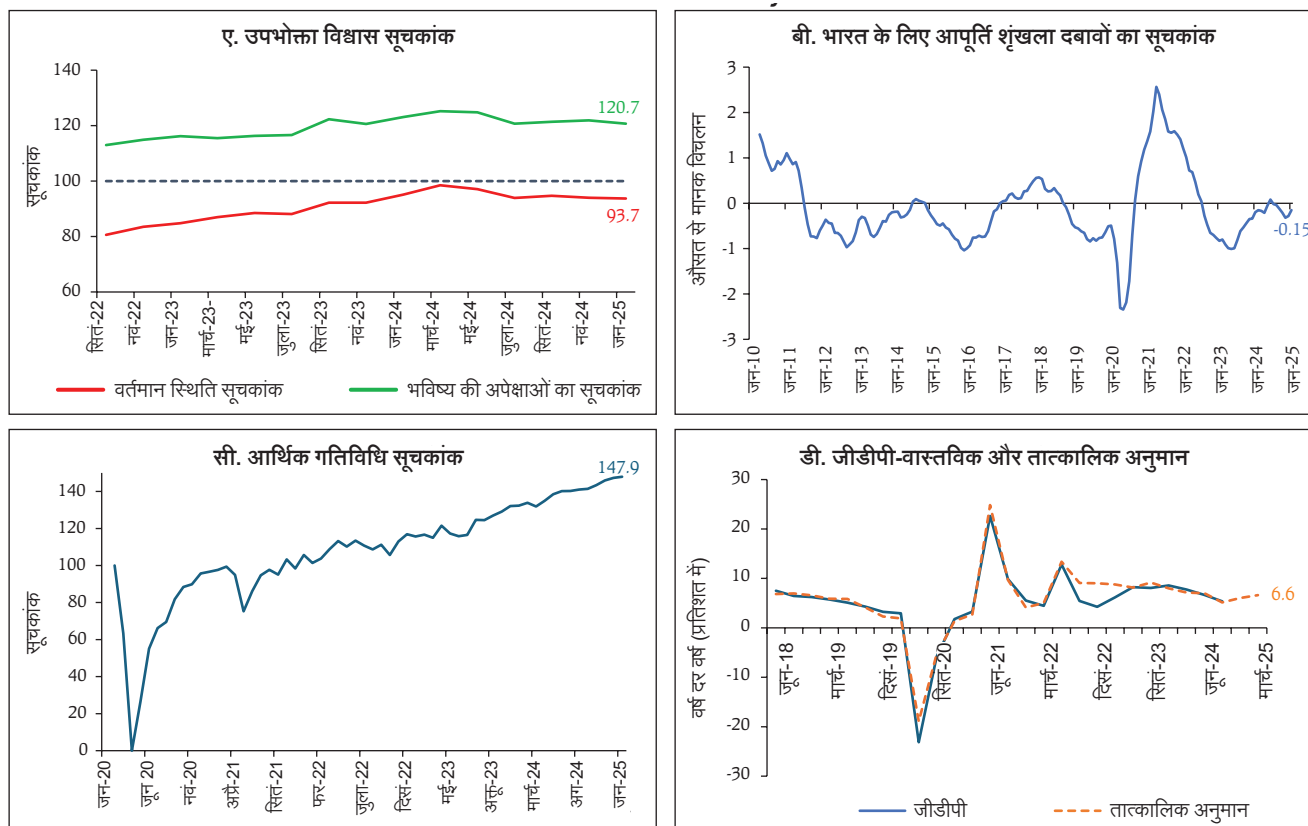
लिए जीडीपी का अब तक का अनुमान 6.6 प्रतिशत रखा गया है (चार्ट III.1सी और चार्ट III.1डी)।

समग्र मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि कुल मांग पहली छमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है। जनवरी में ई-वे बिल की वृद्धि बढ़कर 23.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.2ए)। टोल संग्रह में मात्रा और मूल्य दोनों के दृष्टिकोण से मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.2बी)।

जनवरी में थोक ऑटोमोबाइल बिक्री में सुधार हुआ, दो महीने की गिरावट के बाद, इसमें 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.3ए)। दोपहिया वाहन खंड में सुधार देखा गया, मुख्य रूप से स्कूटर की बिक्री में उछाल के कारण, हालांकि मोटरसाइकिल की बिक्री में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई (चार्ट III.3बी)। ट्रैक्टर की बिक्री में लगातार दूसरे महीने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज

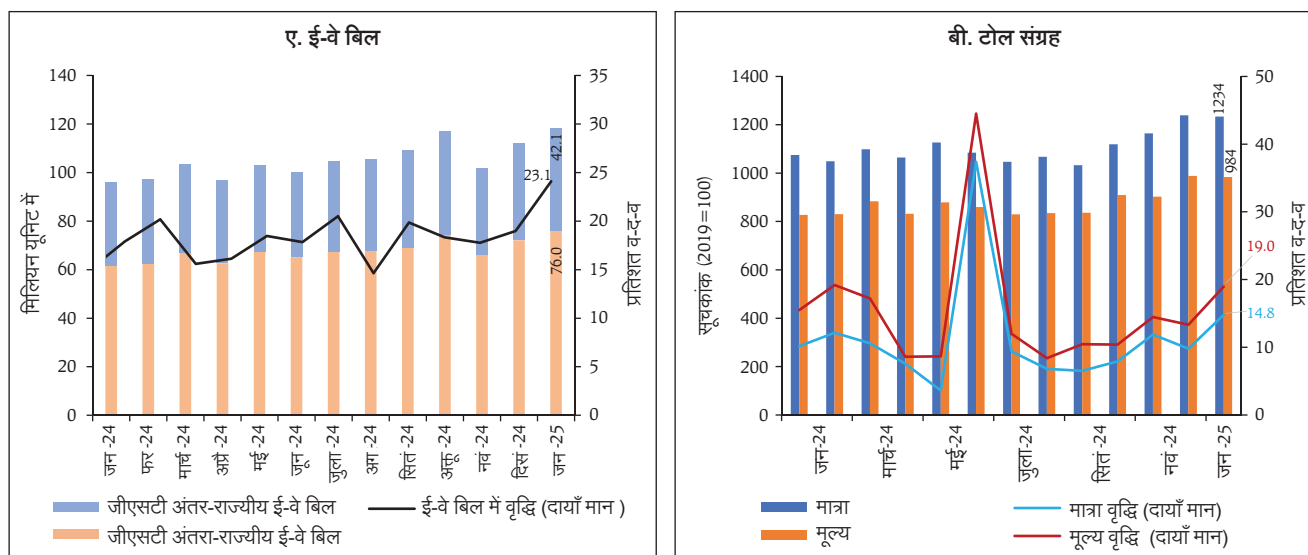
चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि संकेतक



टिप्पणियाँ: 1. आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण डायनेमिक फैक्टर मॉडल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर किया जाता है। फरवरी 2020 में ईएआई को 100 और अप्रैल 2020 में 0 पर रखा गया, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।
2. जीडीपी तात्कालिक अनुमान के लिए, अंतर्निहित संख्या प्रथम अग्रिम अनुमान (एफई) से उपलब्ध है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.2 : ई-वे बिल और टोल संग्रह

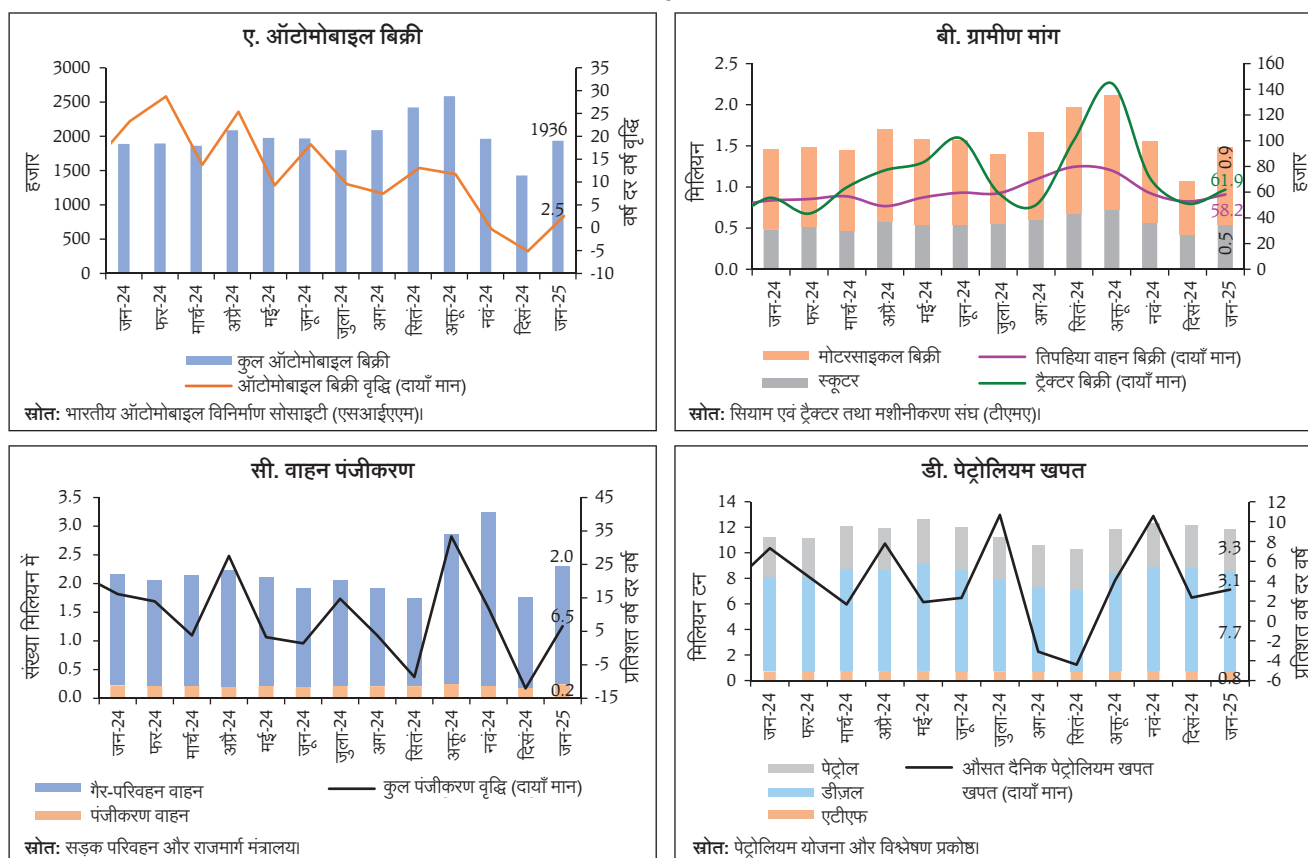


स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई।

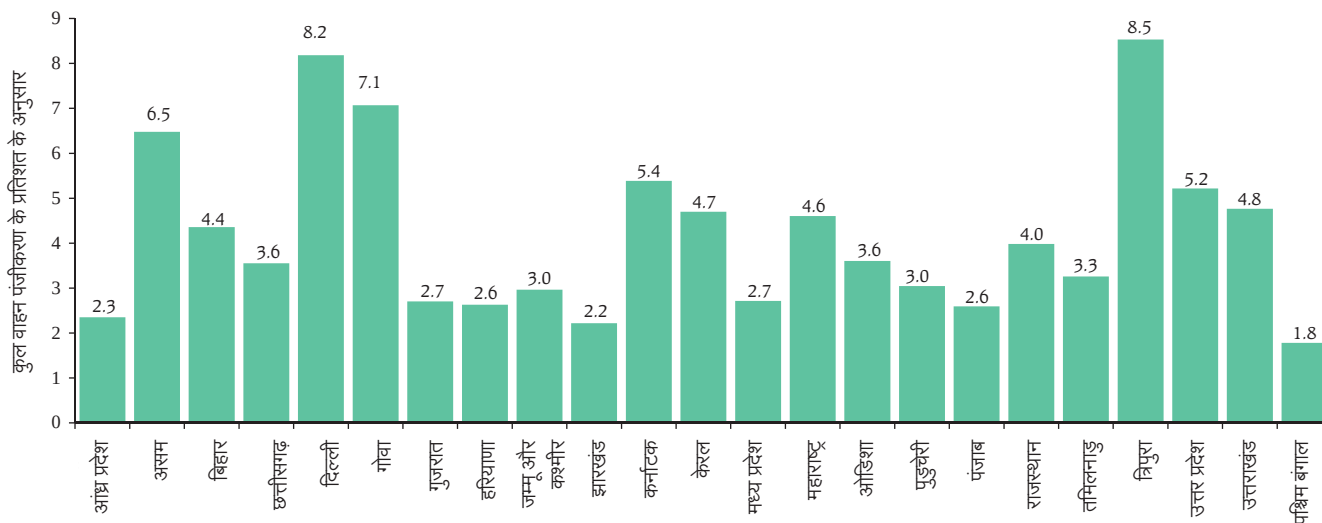
की गई। जनवरी में वाहन पंजीकरण में विस्तार दर्ज किया गया, जो गैर-परिवहन और परिवहन वाहन दोनों खंडों में वृद्धि के कारण

हुआ (चार्ट III.3सी)। जनवरी में पेट्रोलियम की खपत में 3.1 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.3डी)।

चार्ट III.3: परिवहन क्षेत्र संकेतक



चार्ट III.4: राज्यवार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दरें

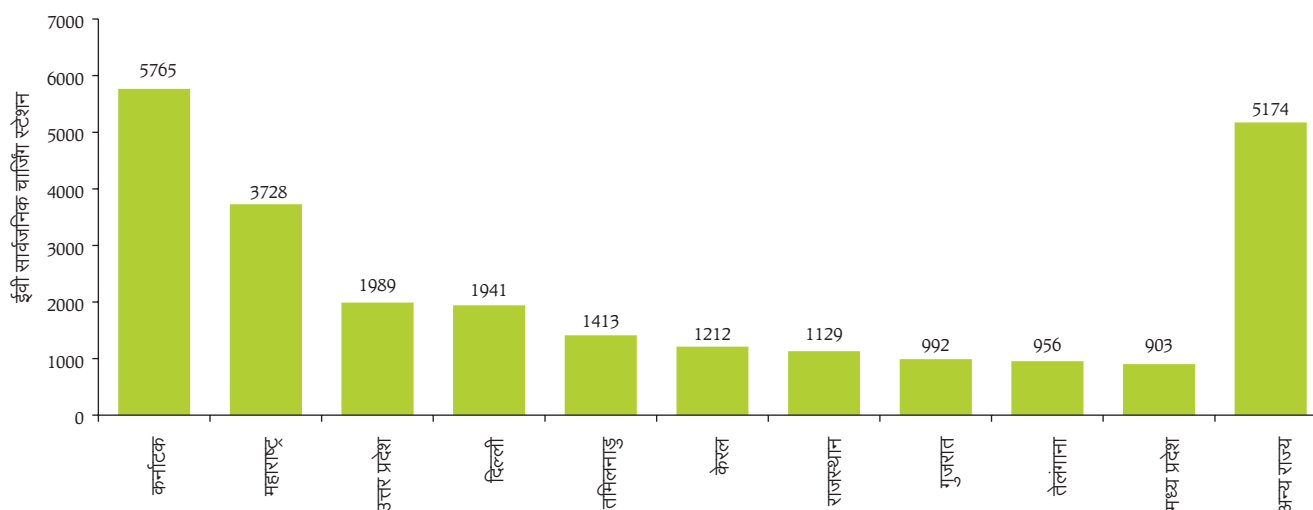


स्रोत: 'वाहन डैशबोर्ड'।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने की दर में वृद्धि देखी गई है। 2024 में, कुल वाहन पंजीकरण में ईवी की हिस्सेदारी 2021 में 2 प्रतिशत से कम से बढ़कर 7 प्रतिशत से अधिक हो गई। असम, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ईवी अपनाने की दर अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है⁹ (चार्ट III.4)।

सितंबर 2024 में शुरू की गई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना का उद्देश्य ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करना है और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) के विकास का प्रावधान किया गया है।¹⁰ दिसंबर 2024 तक, कर्नाटक में सबसे अधिक ईवीपीसीएस थे, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (चार्ट III.5) थे।

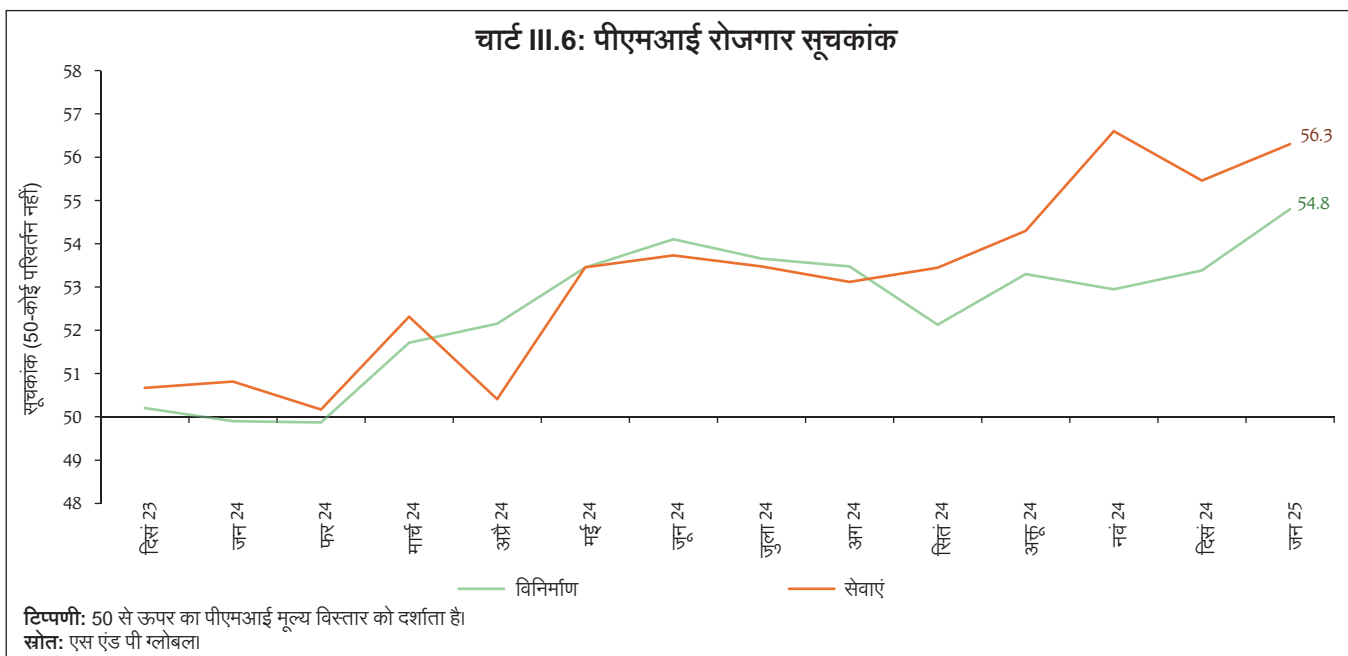
चार्ट III.5: ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या



स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय, पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 20 दिसंबर, 2024।

⁹ जनवरी 2019 से फरवरी 2025 की अवधि के लिए संबंधित राज्य में कुल ईवी पंजीकरण को कुल वाहन पंजीकरण से विभाजित करके अपनाने की दरों की गणना की जाती है।

¹⁰ दो साल की अवधि के लिए ₹10,900 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया, जिसमें से ₹2,000 करोड़ ईवीपीसीएस के लिए रखे गए हैं।

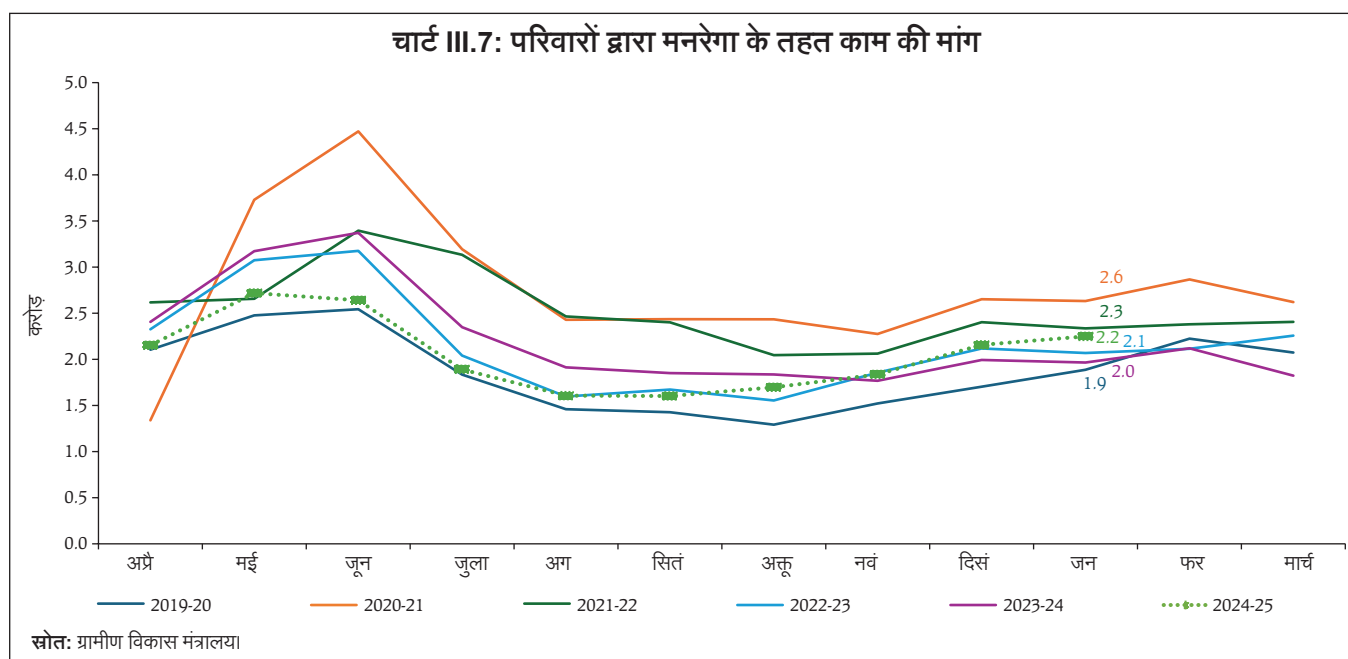


जनवरी 2025 में, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पीएमआई सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से रिकॉर्ड गति से बढ़ा, जबकि सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन भी इस शृंखला¹¹ में सबसे मजबूत था (चार्ट III.6)।

रबी की बुवाई करीब आने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत

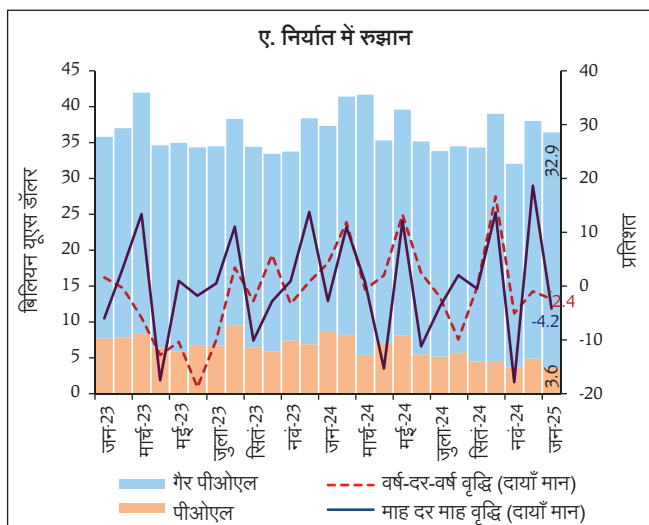
काम की मांग जनवरी 2025 में लगातार तीसरे महीने 14.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी (चार्ट III.7)।

भारत का पण्य निर्यात जनवरी 2025 में 2.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जिसका मुख्य कारण तेल निर्यात में गिरावट है (चार्ट III.8)।



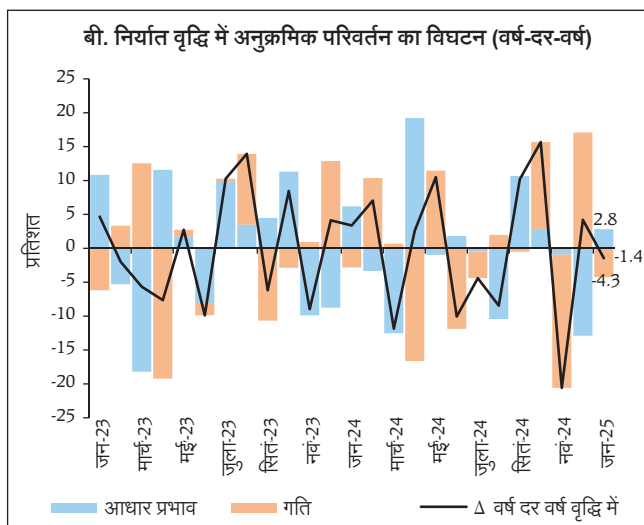
¹¹ सर्वेक्षण 2005 में शुरू हुआ था।

चार्ट III.8: भारत का पण्य निर्यात



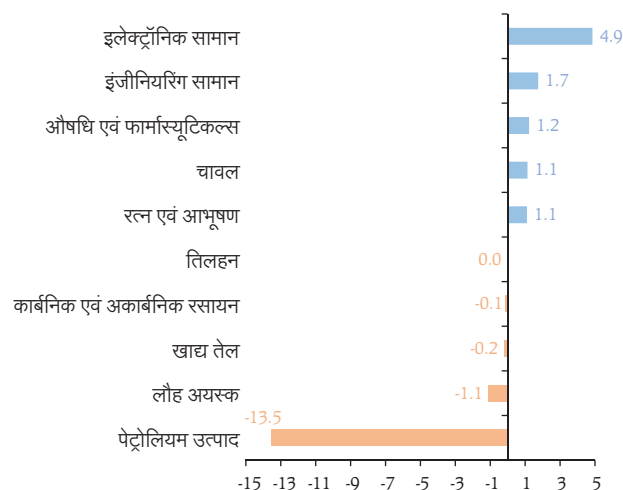
टिप्पणी: पीओएल: पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक।

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।



संकुचन कुछ उत्पाद समूहों तक ही सीमित रहा क्योंकि 30 प्रमुख वस्तुओं (निर्यात बास्केट का 27.6 प्रतिशत हिस्सा) में से केवल 5 के निर्यात में साल दर साल आधार पर गिरावट आई। प्रमुख समूहों में, पेट्रोलियम उत्पादों और लौह अयस्क ने ऋणात्मक योगदान दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान और दवाओं तथा फार्मास्यूटिकल्स ने समर्थन दिया (चार्ट III.9)।

चार्ट III.9: भारत का पण्य निर्यात - सापेक्ष योगदान (जनवरी 2024 की तुलना में जनवरी 2025)



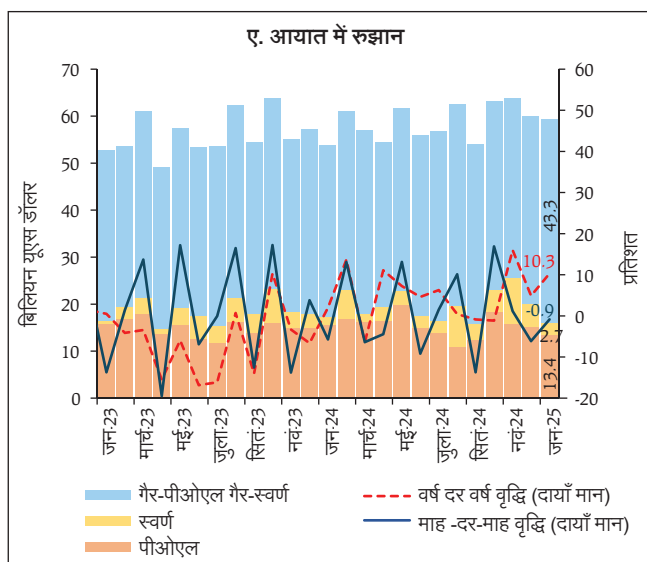
अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात 1.4 प्रतिशत बढ़कर 358.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य नेतृत्व इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स ने किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण और लौह अयस्क ने निर्यात को नीचे ला दिया।

जनवरी 2025 में 20 प्रमुख गंतव्यों में से 10 को निर्यात में विस्तार हुआ। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, 20 प्रमुख गंतव्यों में से 15 को निर्यात में विस्तार हुआ, जिसमें अमेरिका, यूई और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य रहे।

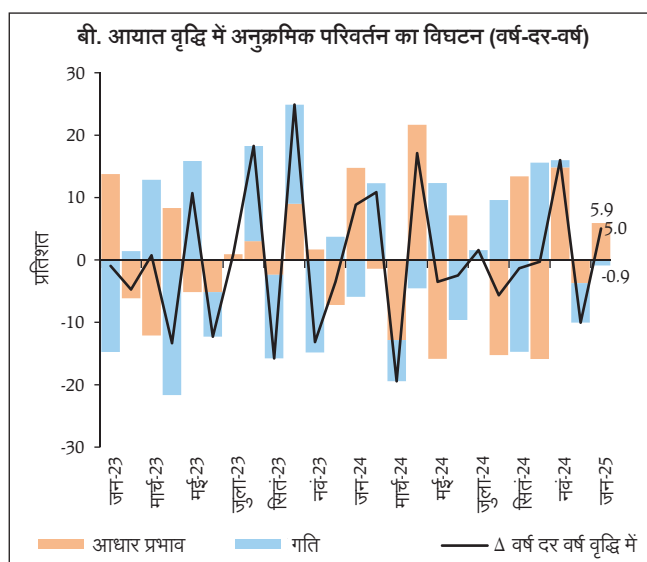
जनवरी में व्यापारिक आयात 10.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 59.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया (चार्ट III.10)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 26 वस्तुओं (आयात बास्केट का 59.7 प्रतिशत हिस्सा) में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की गई।

इलेक्ट्रॉनिक सामान, विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी और सोना प्रमुख समूह थे जिन्होंने धनात्मक योगदान दिया, जबकि पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पाद तथा मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर प्रमुख समूह थे जिन्होंने ऋणात्मक योगदान दिया (चार्ट III.11)।

चार्ट III. 10: भारत का पण्य आयात



स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।



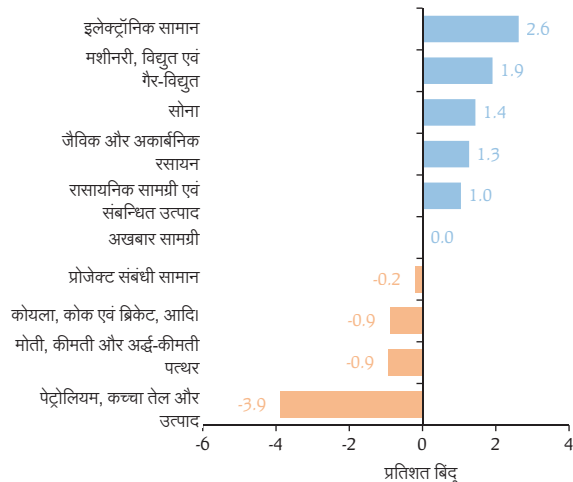
अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, भारत का व्यापारिक आयात 7.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 609.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें मुख्य रूप से सोना, पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का योगदान रहा, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों तथा लोहा और इस्पात के आयात में गिरावट आई।

जनवरी में 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात बढ़ा और अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों

में से 15 से आयात बढ़ा। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान प्रमुख स्रोत देशों यानी चीन, रूस और यूएई से आयात में वृद्धि दर्ज की गई।

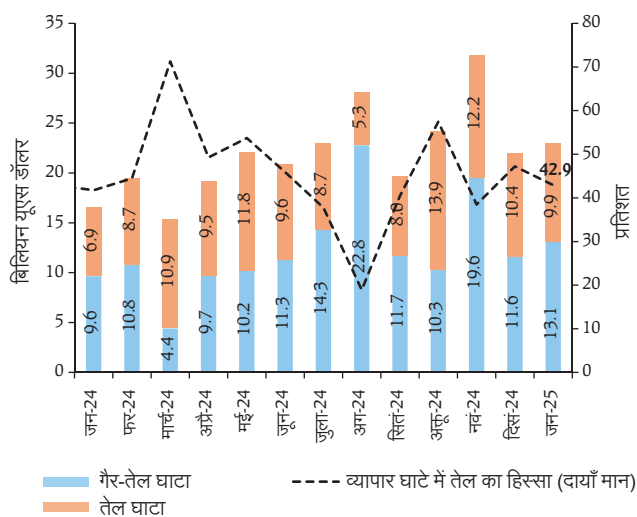
जनवरी 2025 में व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़कर 23.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो जनवरी 2024 में 16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जनवरी में तेल और गैर-तेल दोनों घाटा एक साल पहले की तुलना में अधिक रहा (चार्ट III.12)। जनवरी में कुल व्यापार घाटे में तेल घाटे की

चार्ट III.11: भारत का पण्य आयात
- सापेक्ष योगदान
(जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2024)

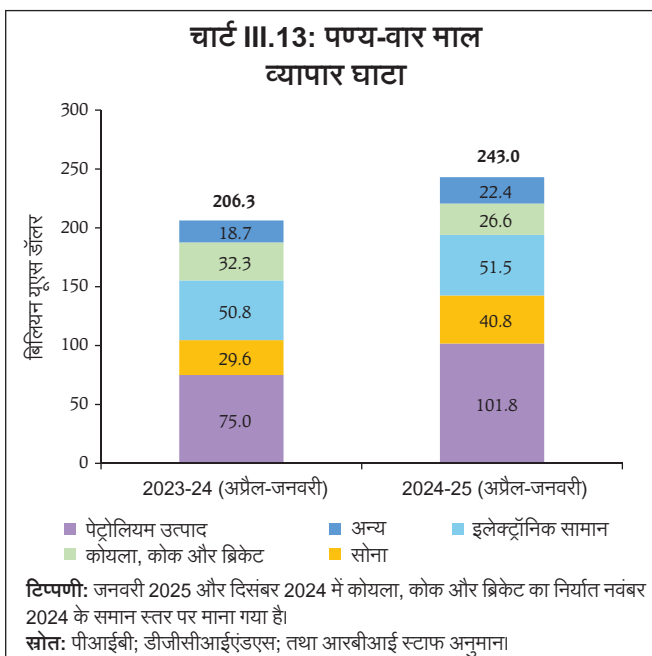


स्रोत: पीआईबी; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.12: भारत के पण्य व्यापार घाटे का अपघटन



स्रोत: पीआईबी; तथा डीजीसीआईएंडएस।



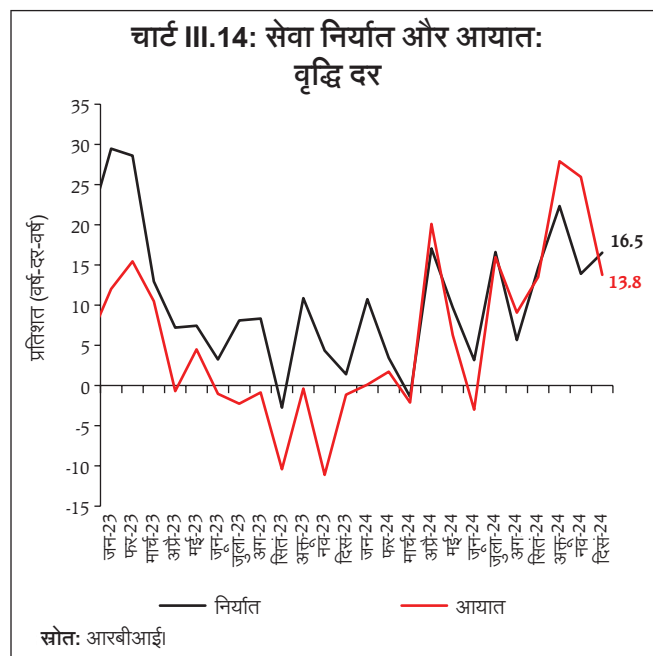
हिस्सेदारी 42.9 प्रतिशत थी, जबकि एक साल पहले यह 41.8 प्रतिशत थी।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, भारत का पण्य व्यापार घाटा एक साल पहले के 206.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 243.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना (चार्ट III.13) का स्थान रहा।

दिसंबर 2024 के दौरान, सेवाओं का निर्यात 16.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि सेवाओं का आयात 16.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.14)। महीने के दौरान निवल सेवा निर्यात आय 19.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा (आरडी) निरपेक्ष रूप से पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था; जबकि वे संशोधित अनुमानों (आरई) के प्रतिशत के रूप में अधिक थे।¹² सकल

¹² लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के अनुसार।



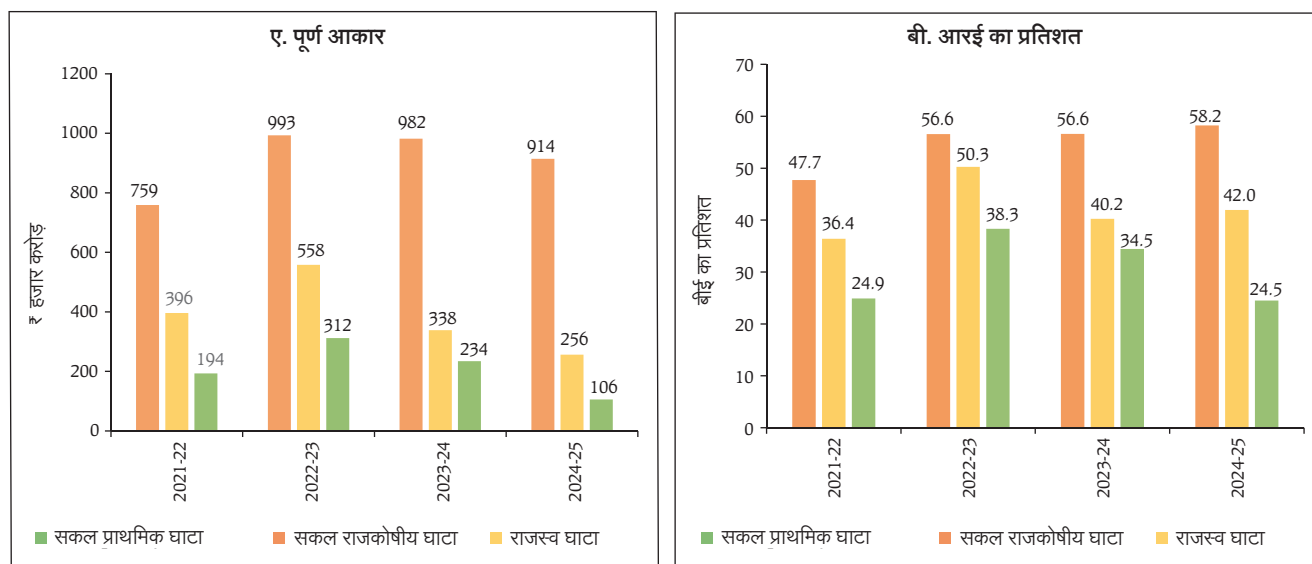
प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निरपेक्ष रूप से और संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में कम रहा (चार्ट III.15ए और 15बी)।

व्यय घटकों में, राजस्व व्यय में अप्रैल-दिसंबर 2024 में 7.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडी द्वारा संचालित, प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 21.0 प्रतिशत की कमी आई थी। ब्याज भुगतान और सब्सिडी के बाद राजस्व व्यय में 5.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 4.5 प्रतिशत थी।

नवंबर और दिसंबर 2024¹³ में पूंजीगत व्यय में सुधार हुआ, जिससे अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान साल-दर-साल वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.16ए)। शीर्ष छह मंत्रालयों में, जो 2024-25 के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, वित्त, और आवास एवं शहरी मामलों ने साल-दर-साल आधार पर विस्तार दर्ज किया, जबकि रक्षा और संचार ने संकुचन दर्ज

¹³ साल-दर-साल आधार पर, पूंजीगत व्यय में नवंबर और दिसंबर 2024 के दौरान क्रमशः 21.3 प्रतिशत और 95.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट III.15: अप्रैल-दिसंबर के दौरान केंद्र सरकार का बजटीय घाटा



स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए); तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज।

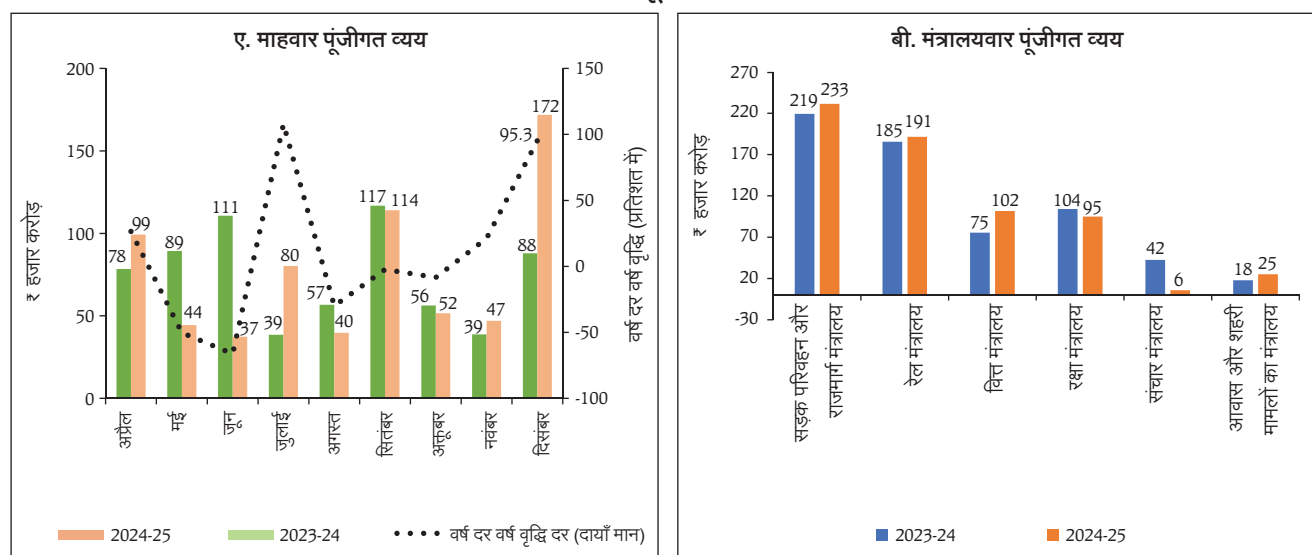
किया (चार्ट III.16बी)। कुल मिलाकर, कुल व्यय में वृद्धि अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 5.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8.4 प्रतिशत थी।

केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में अप्रैल-दिसंबर 2024 में 10.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से आयकर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), और सीमा शुल्क (चार्ट III.17ए) के कारण हुआ। गैर-कर राजस्व ने संशोधित अनुमान का 84.3 प्रतिशत प्राप्त किया, जो रिज़र्व

बैंक से 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण के कारण था (चार्ट III.17बी)। हालांकि, ऋणों की वसूली और विनिवेश प्राप्ति दोनों में गिरावट के कारण गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति संकुचित हुई। केंद्र सरकार के निवल कर राजस्व में अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, कुल प्राप्ति पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.9 प्रतिशत बढ़ी।

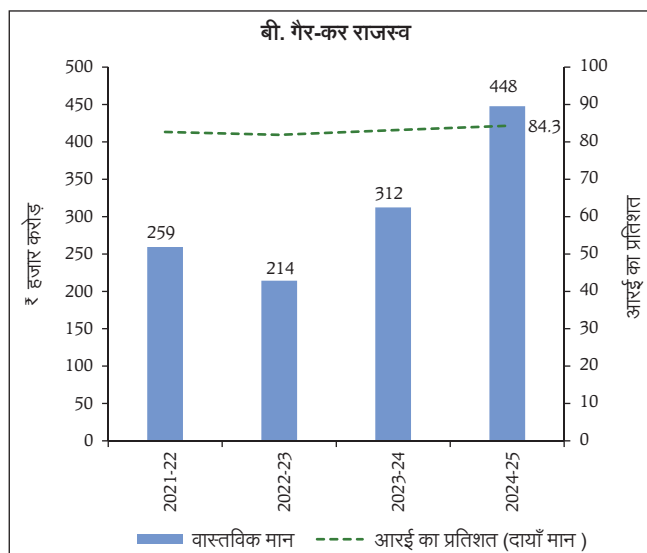
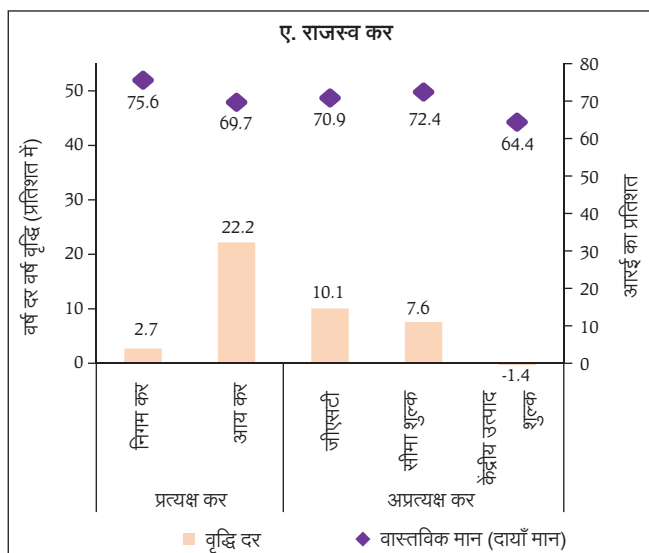
जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) 12.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹1.96 लाख करोड़ पर पहुंच गया

चार्ट III.16: पूंजीगत व्यय



स्रोत: सीजीए

चार्ट III.17: अप्रैल-दिसंबर के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति

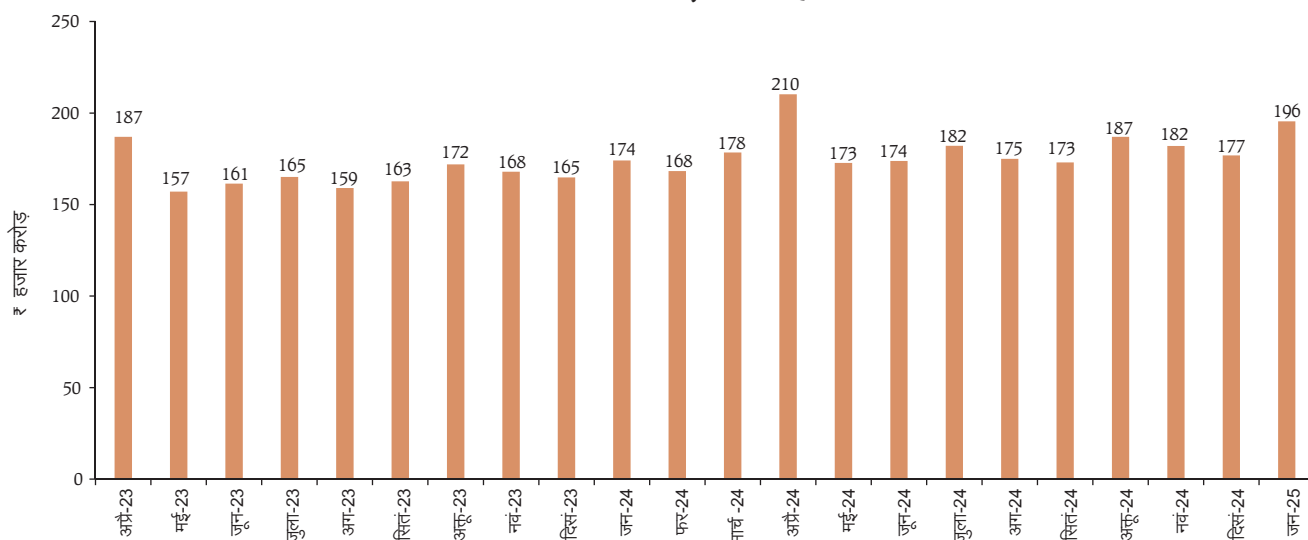


स्रोत: सीजीए।

(चार्ट III.18)। घरेलू लेन-देन¹⁴ से संग्रह में 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि आयात पर 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी 2025 के लिए कर रिफंड में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, निवल जीएसटी संग्रह 10.9 प्रतिशत बढ़कर ₹1.72 लाख करोड़ हो गया। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के लिए संचयी सकल जीएसटी संग्रह एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक था।

जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) 12.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹1.96 लाख करोड़ हो गया (चार्ट III.18)। घरेलू लेन-देन से संग्रह में 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि आयात पर 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी 2025 के लिए कर वापसी में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, निवल जीएसटी संग्रह 10.9 प्रतिशत बढ़कर ₹1.72 लाख करोड़ हो गया। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के लिए

चार्ट III.18: जीएसटी संग्रह



स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी); और जीएसटी पोर्टल।

¹⁴ जनवरी 2025 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह में घरेलू लेनदेन से संग्रह का हिस्सा 75.3 प्रतिशत रहा।

संचयी सकल जीएसटी संग्रह एक साल पहले के इसी अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक था।

1 फरवरी, 2025 को घोषित केंद्रीय बजट 2025-26 ने राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें 2025-26 (बीई) में जीएफडी को जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रखा गया, जो 2024-25 (आरई) में जीडीपी के 4.8 प्रतिशत से कम है। प्रस्तावित समेकन राजस्व व्यय को जीडीपी के 11.0 प्रतिशत (2024-25 आरई में 11.4 प्रतिशत की तुलना में) तक कम करके, पूंजीगत व्यय को जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर बनाए रखते हुए (जीडीपी के 4.3 प्रतिशत से अधिक प्रभावी पूंजीगत व्यय के साथ)¹⁵ जबकि सकल कर राजस्व को जीडीपी के 12.0 प्रतिशत (2024-25 आरई में 11.9 प्रतिशत की तुलना में) तक बढ़ाने के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की गई है। 2026-27 से 2030-31 तक, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार बनाए रखने का प्रयास कर रही है कि उसका ऋण घटता रहे और 31 मार्च 2031 तक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 50 ± 1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाए।

अनंतिम लेखों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान बजट अनुमानों (बीई) के प्रतिशत के रूप में राज्यों

सारणी III.1: राज्यों के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-दिसंबर)

(बीई का प्रतिशत)

घाटा संकेतक	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा	4.2	52.3	98.3
सकल राजकोषीय घाटा	39.9	52.1	54.8
प्राथमिक घाटा	15.0	39.9	44.9

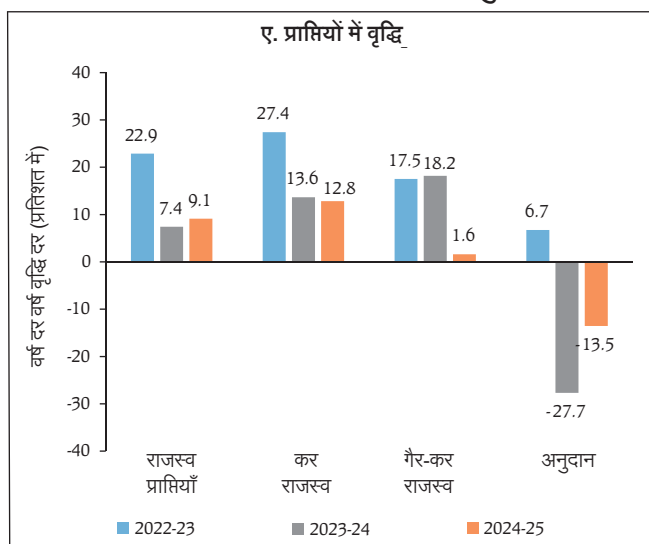
टिप्पणी: डेटा 23 राज्यों से संबंधित है। बीई: बजट अनुमान।

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

के प्रमुख घाटा संकेतक पिछले वर्ष के स्तर से अधिक हैं (सारणी III.1)।

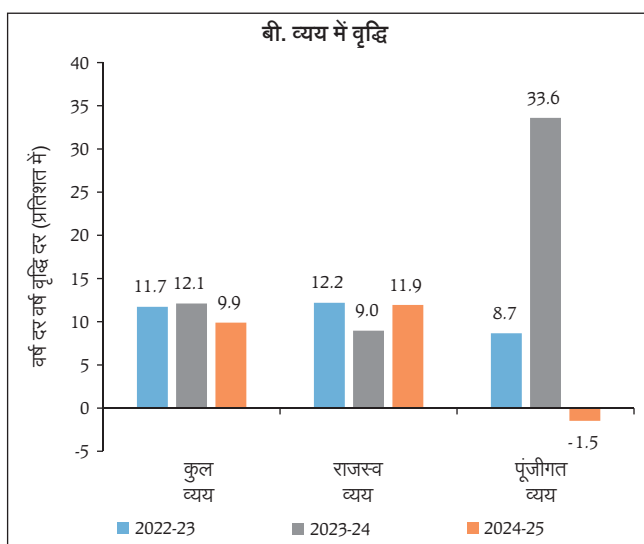
राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से उच्च कर राजस्व द्वारा प्रेरित थी, भले ही केंद्र सरकार से अनुदान में कमी आई (चार्ट III.19ए)। राज्यों के जीएसटी (एसजीएसटी) और राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि थोड़ी कम हुई, जबकि बिक्री कर/वैट में पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक बदलाव देखा गया। राज्यों के राजस्व व्यय में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में गिरावट आई (चार्ट III.19बी)। तदनुसार, आरईसीओ¹⁶ अनुपात पिछले वर्ष की समान अवधि के 6.0 से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2024 में 7.0 हो गया।

चार्ट III.19: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-दिसंबर)



टिप्पणी: डेटा 23 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: सीएजी।



¹⁵ प्रभावी पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता है।

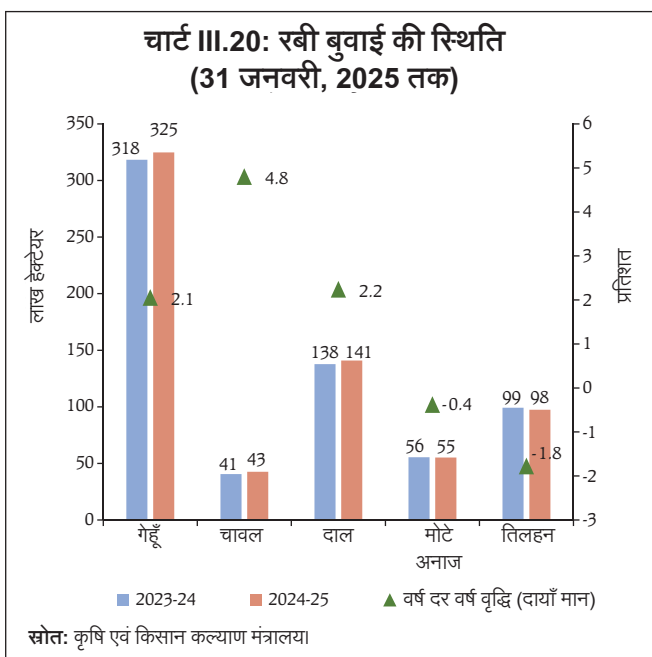
¹⁶ पूंजीगत व्यय के लिए राजस्व व्यय।

समग्र आपूर्ति

रबी सीजन 2024-25 के दौरान बुवाई का रकबा 661 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक है। गेहूँ का रकबा, जो सामान्य रबी क्षेत्र के तहत बुवाई के रकबे का लगभग आधा है, 2.1 प्रतिशत बढ़ा (चार्ट III.20)। दालों की बुवाई में वृद्धि मुख्य रूप से चने के अधिक रकबे के कारण हुई।

पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2024-25 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 362.1 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 2.1 प्रतिशत अधिक है। प्याज और आलू के अधिक उत्पादन के कारण सालाना आधार पर वृद्धि हुई (चार्ट III.21)।

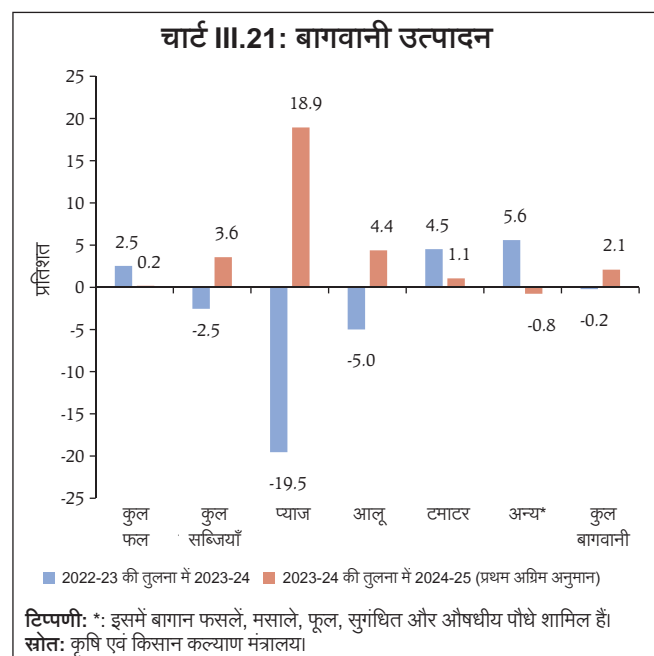
केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने तथा कृषि अवसंरचना में सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में 'प्रधानमंत्री धन- धान्य कृषि योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है, ताकि उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार हो, फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाया जा सके तथा लगभग 1.7 करोड़ किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता में सुविधा हो। इसमें अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते



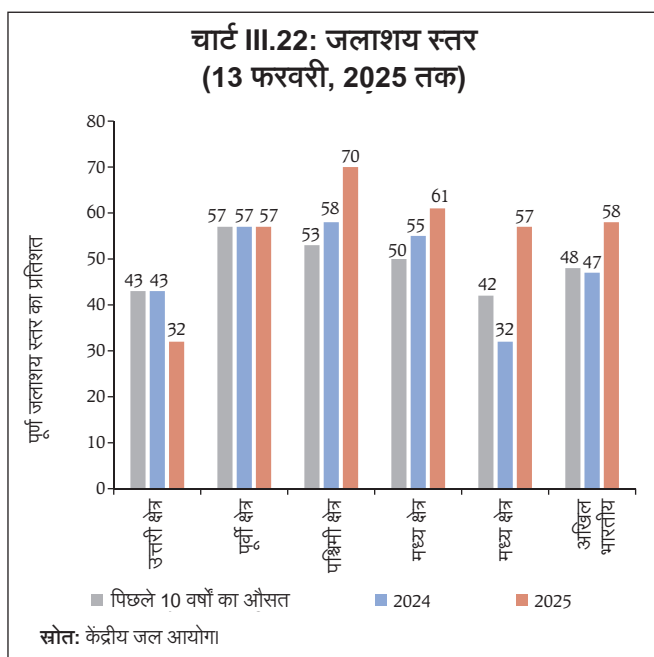
हुए 6 वर्षीय "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू करने की भी घोषणा की गई है।

जलाशय स्तर (155 प्रमुख जलाशयों पर आधारित) कुल जलाशय क्षमता (13 फरवरी, 2025 तक) के 58 प्रतिशत पर एक आरामदायक स्थिति में बना हुआ है, जो पिछले वर्ष के साथ-साथ दशकीय औसत स्तरों (चार्ट III.22) से भी अधिक है। जलाशय की आरामदायक स्थिति देश में कम सर्दियों की बारिश (जनवरी-मार्च) से उत्पन्न रबी फसलों के लिए कुछ चिंताओं को दूर करती है¹⁷।

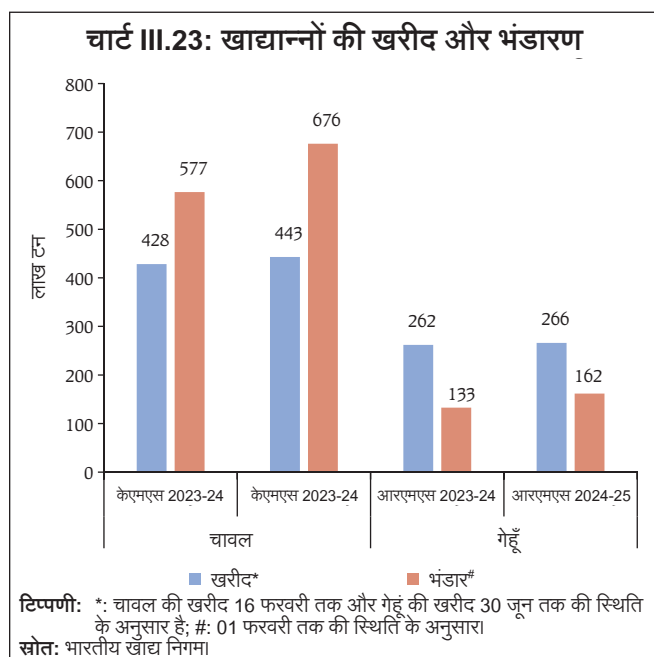
01 फरवरी, 2025 तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास चावल का स्टॉक 676 लाख टन था - जो बफर आवश्यकताओं से नौ गुना अधिक है। सरकार ने राज्य सरकारों और इथेनॉल डिस्टिलरी को बिक्री के लिए खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत चावल का आरक्षित मूल्य ₹2,800 प्रति क्विंटल से घटाकर ₹2,250 कर दिया। 162 लाख टन गेहूँ का स्टॉक पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है और बफर मानदंडों के अनुरूप है। चालू विपणन सत्र के दौरान चावल की खरीद 443 लाख टन (16 फरवरी, 2025 तक) पिछले साल की तुलना में 3.4 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.23)।



¹⁷ 12 फरवरी, 2025 तक सर्दियों की बारिश दीर्घ अवधि के औसत से 70 प्रतिशत कम थी।

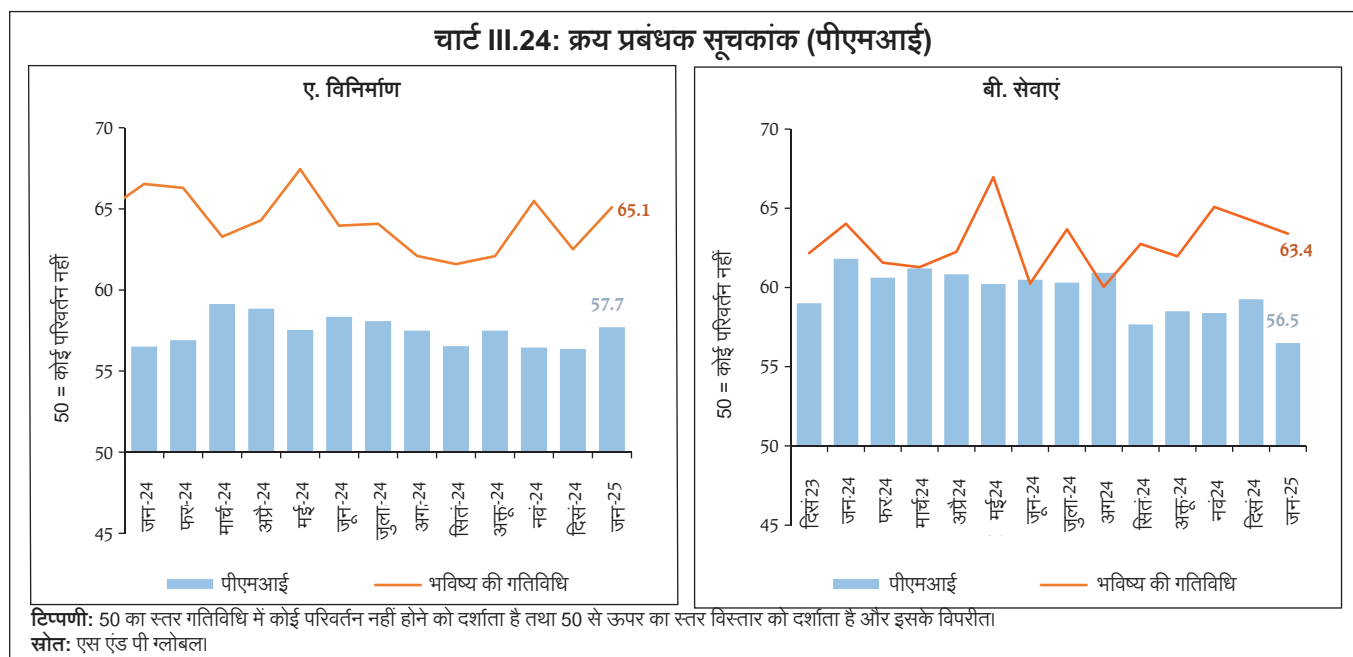


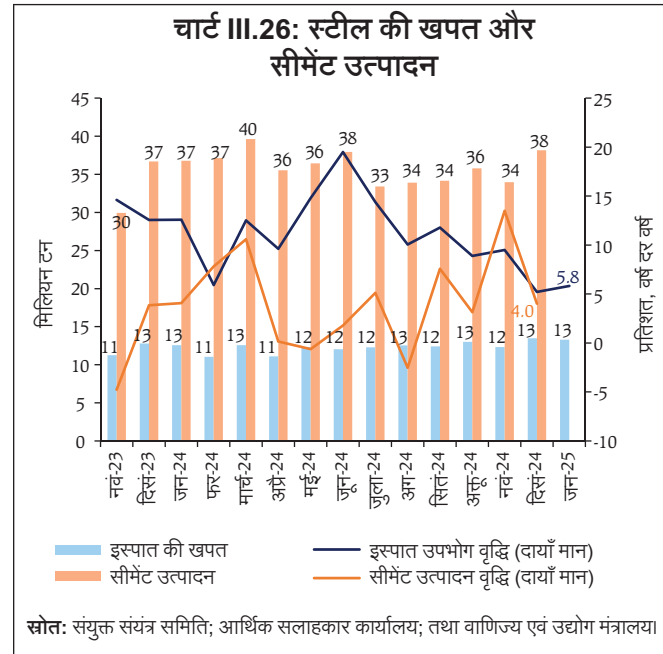
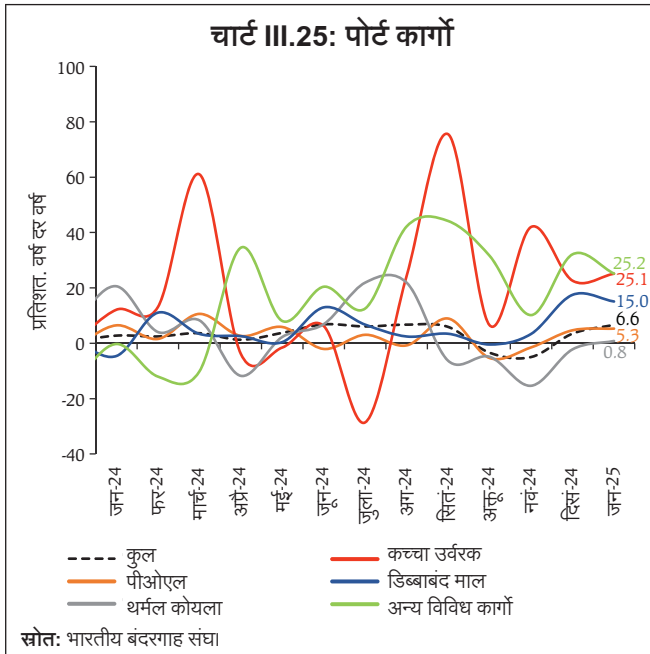
भारत का विनिर्माण पीएमआई जनवरी में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो नए ऑर्डर (घरेलू और निर्यात) और रोजगार (चार्ट III.24ए) के कारण हुआ। हालांकि, नई व्यावसायिक गतिविधि में मंदी के कारण सेवा पीएमआई में नरमी आई (चार्ट III.24बी)। विनिर्माण के लिए व्यावसायिक उम्मीदों में सुधार हुआ, जबकि सेवाओं के लिए भविष्य के उत्पादन आकलन तीन महीने के निचले स्तर पर आ गए।



बंदरगाह यातायात दिसंबर 2024 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2025 में 6.6 प्रतिशत हो गया, जो उर्वरकों, कंटेनरयुक्त कार्गो और अन्य विविध कार्गो द्वारा संचालित है (चार्ट III.25)।

निर्माण क्षेत्र में, जनवरी में इस्पात की खपत में वृद्धि बढ़कर 5.8 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई, जबकि सीमेंट उत्पादन स्तर दिसंबर में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नौ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.26)।





सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधि में सुदृढ़ दर्शाते हैं, जिसमें

अधिकांश संकेतक वर्ष दर वर्ष वृद्धि में सुधार दर्शाते हैं (सारणी III.2)।

सारणी III.2 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएँ

(वर्ष दर वर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नव-24	दिसं-24	जन-25
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	9.5	8.9	1.2	4.3	4.9	-2.0	-1.6	-0.4	1.1	4.4	11.4	3.5
	दुपहिया वाहन बिक्री	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8	14.2	-1.1	-8.8	2.1
	तीन पहिया वाहन बिक्री	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	6.7	-0.7	-1.3	3.5	7.7
	ट्रैक्टर बिक्री	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7	22.4	-1.3	14.0	11.4
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	-3.8			3.5			-10.9			1.3		
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0					
	पोर्ट कार्गो यातायात	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8	5.9	6.7	5.8	-3.4	-4.9	3.4	6.6
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	14.0	8.9	0.3	4.3	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	20.5	18.4	16.1	10.5	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.4	9.6	13.8	10.8	14.1
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात*	19.3	15.0	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	11.2	10.3	10.7	9.0	9.8
	जीएसटी ई-वे बिल्लस (कुल)	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5	16.9	16.3	17.6	23.1
	जीएसटी ई-वे बिल्लस (अंतरा राज्य)	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0	18.3	5.4	17.9	23.3
	जीएसटी ई-वे बिल्लस (अंतर राज्य)	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7	14.4	44.1	17.1	22.8
	होटल कमरा बुकिंग	1.8	2.7	-1.4	-2.6	-3.1	3.6	0.7	2.1	-5.3	11.1	-0.2	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	7.8	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2	3.5	4.8	10.7	8.9	
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	7.0	12.5	9.6	15.9	19.5	14.4	10.0	11.8	8.9	9.5	5.2	5.8
	सीमेंट उत्पादन	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.8	5.1	-2.5	7.6	3.1	13.5	4.0	
पीएमआई संकेतक #	सेवाएँ	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7	58.5	58.4	59.3	56.5

<< संकुचन विस्तार >>

टिप्पणी: #: डेटा स्तरों में है। *: दिसंबर 2024 के डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप का निर्माण किया गया है।

स्रोत: एसआईएम: रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर और मशीनीकरण एसोसिएशन; भारतीय बंदरगाह संघ; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; जीएसटीएन: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्किट।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)¹⁸ में साल-दर-साल होने वाले बदलावों के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, दिसंबर 2024 में 5.2 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2025 में 4.3 प्रतिशत के पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई (चार्ट III.27)। मुद्रास्फीति में 90 बीपीएस की गिरावट लगभग 100 बीपीएस (माह दर माह) की ऋणात्मक मूल्य गति के कारण थी, जो आंशिक रूप से लगभग 10 बीपीएस के प्रतिकूल आधार प्रभाव से समायोजित थी। खाद्य समूह ने महीने के दौरान लगभग 240 बीपीएस की ऋणात्मक गति दर्ज की, जबकि ईंधन और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों में क्रमशः 40 और 30 बीपीएस पर धनात्मक गति थी।

जनवरी में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 5.7 प्रतिशत रह गई, जो दिसंबर में 7.7 प्रतिशत (वार्षिक) थी। उप-समूहों के संदर्भ में, अनाज, अंडे, सब्जियों और दालों में मुद्रास्फीति कम हुई, लेकिन तेल और वसा, फल, चीनी और मिष्ठान, गैर-अल्कोहल पेय और तैयार भोजन में वृद्धि हुई। मांस और मछली, तथा दूध और उत्पादों में मुद्रास्फीति स्थिर रही, जबकि मसालों में अपस्फीति कम हुई (चार्ट III.28)।

जनवरी में ईंधन और बिजली की कीमतों में गिरावट (-)1.4 प्रतिशत रही, जबकि दिसंबर में यह (-)1.3 प्रतिशत

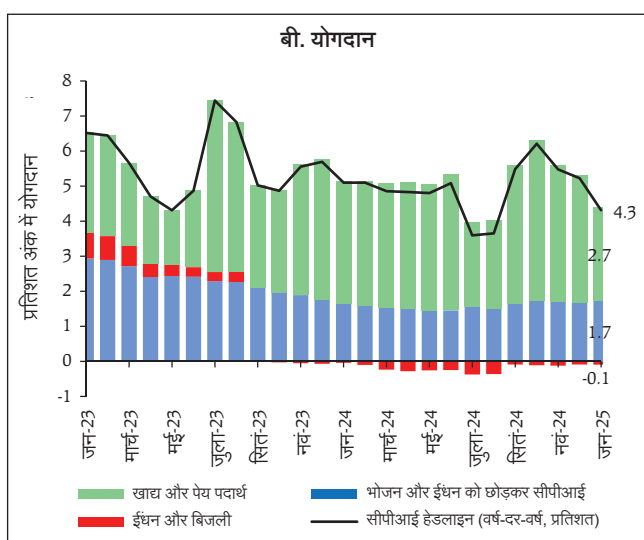
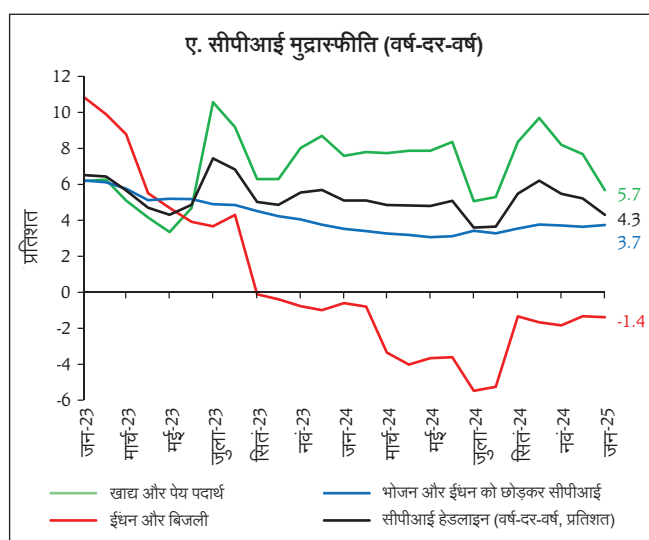
थी। इसका मुख्य कारण केरोसिन की कीमतों में गिरावट की उच्च दर है, जबकि एलपीजी की कीमतों में गिरावट स्थिर रही। हालांकि, बिजली की कीमतों में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई।

कोर मुद्रास्फीति दिसंबर में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2025 में 3.7 प्रतिशत हो गई। उप-समूहों में, आवास, घरेलू सामान और सेवाओं, परिवहन और संचार, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव उप समूहों में मुद्रास्फीति बढ़ी; यह कपड़े और जूते, तथा स्वास्थ्य में स्थिर रही; और पान, तंबाकू एवं नशीले पदार्थों, मनोरंजन और मनोविनोद, तथा शिक्षा में कमी आई (चार्ट III.29)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, जनवरी 2025 में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत थी। राज्य स्तर पर, मुद्रास्फीति दर 2.0 से 7.4 प्रतिशत के बीच थी। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की गई (चार्ट III.30)।

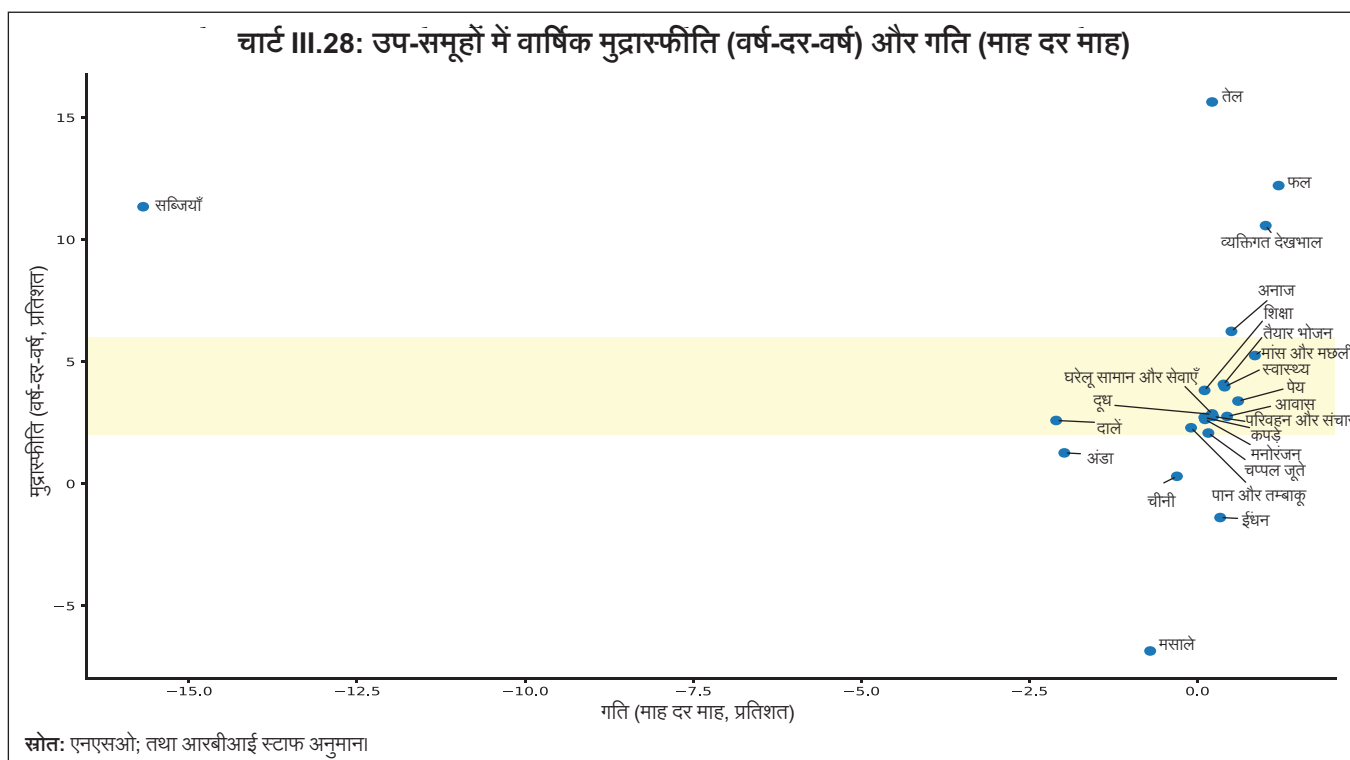
फरवरी के लिए अब तक (14 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा से पता चलता है कि चावल की कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित रहीं, जबकि गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही। खाद्य तेल की कीमतों में और मजबूती आई

चार्ट III. 27: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक



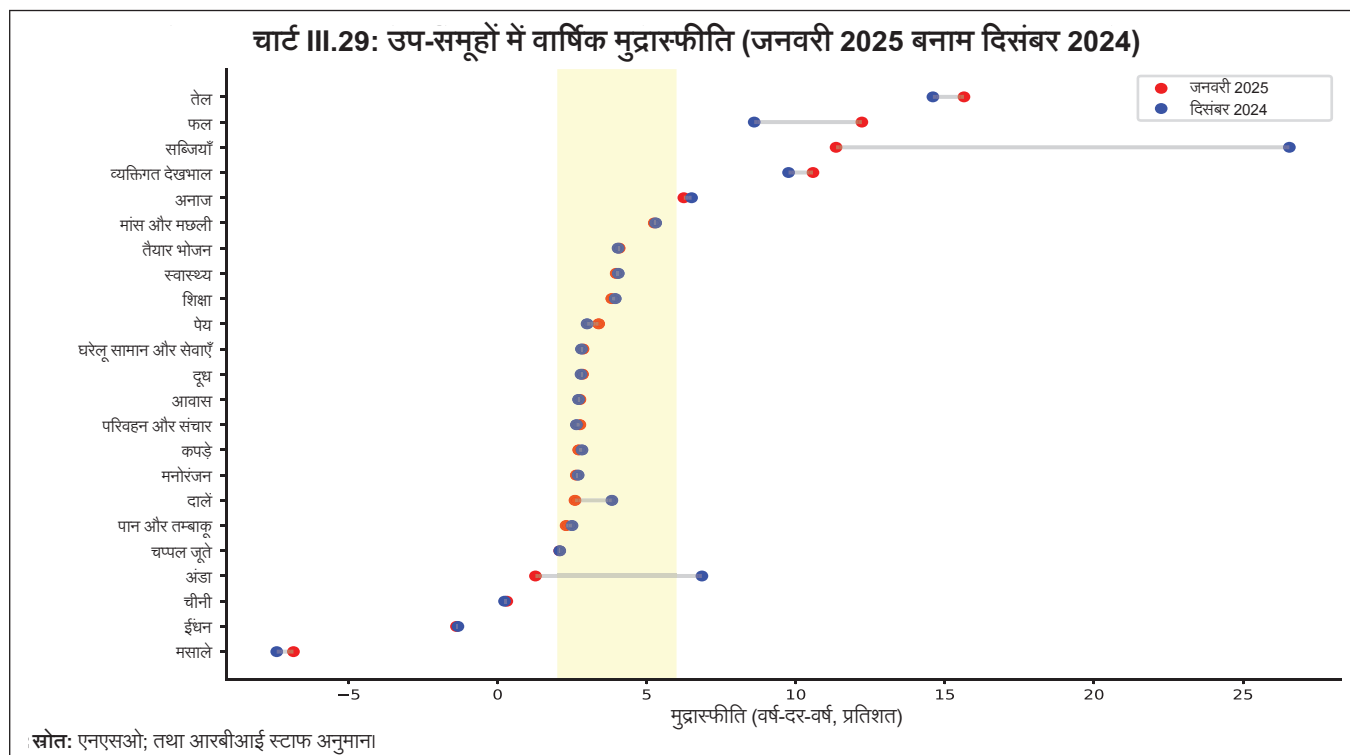
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

¹⁸ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 फरवरी, 2025 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

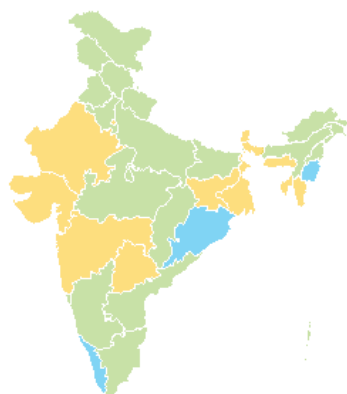


जबकि दालों की कीमतों में व्यापक आधार पर नरमी दर्ज की गई। आलू, प्याज और टमाटर सहित प्रमुख सब्जियों की कीमतों में सुधार जारी रहा (चार्ट III.31)।

पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतें फरवरी में अब तक (14 तारीख तक) अपरिवर्तित रहीं, जबकि केरोसिन की कीमतों में वृद्धि हुई (सारणी III.3)।



**चार्ट III.30: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण
जनवरी 2025
(सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष), (प्रतिशत)**



■ <4 ■ 4-6 ■ 6-8

टिप्पणी : मानचित्र केवल उदाहरणार्थ है।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पीएमआई के अनुसार, जनवरी में विनिर्माण क्षेत्र के लिए इनपुट लागत में नरमी आई, लेकिन सेवा क्षेत्र के लिए इसमें वृद्धि

सारणी III.3: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		दिसं-24	जन-25	फर-25 [^]	जन-25	फर-25 [^]
पेट्रोल	₹/लीटर	101.02	101.02	101.02	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	90.48	90.48	90.48	0.0	0.0
केरोसीन (सब्सिडी वाला)	₹/लीटर	44.75	43.93	46.37	-1.8	5.6
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	813.25	813.25	813.25	0.0	0.0

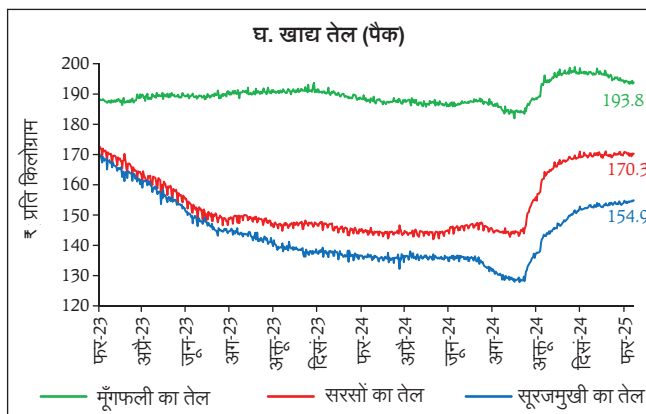
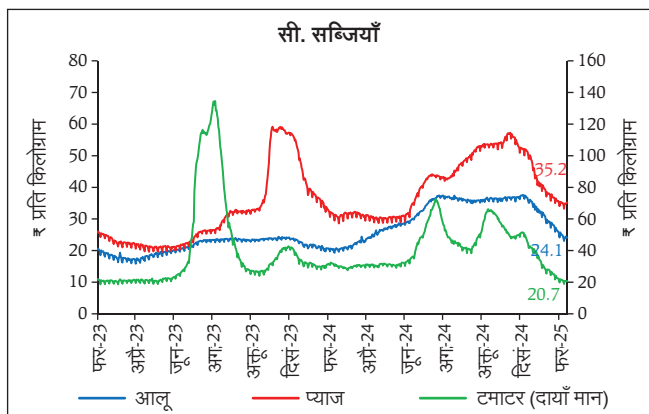
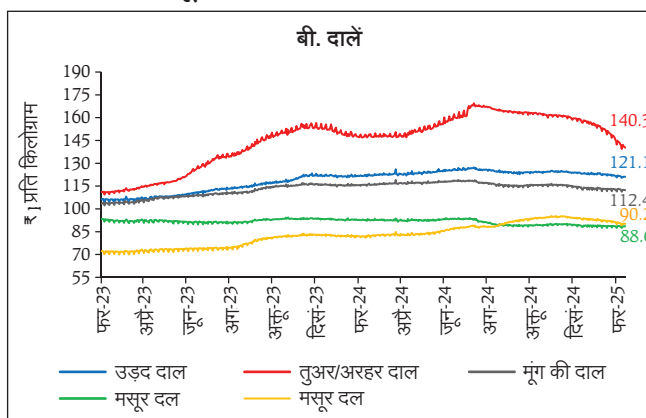
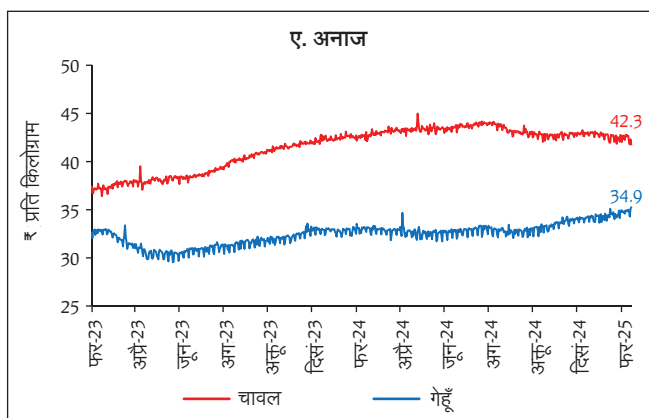
टिप्पणी: 1. [^]: 1-14 फरवरी, 2025 की अवधि के लिए।

2. केरोसीन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसीन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

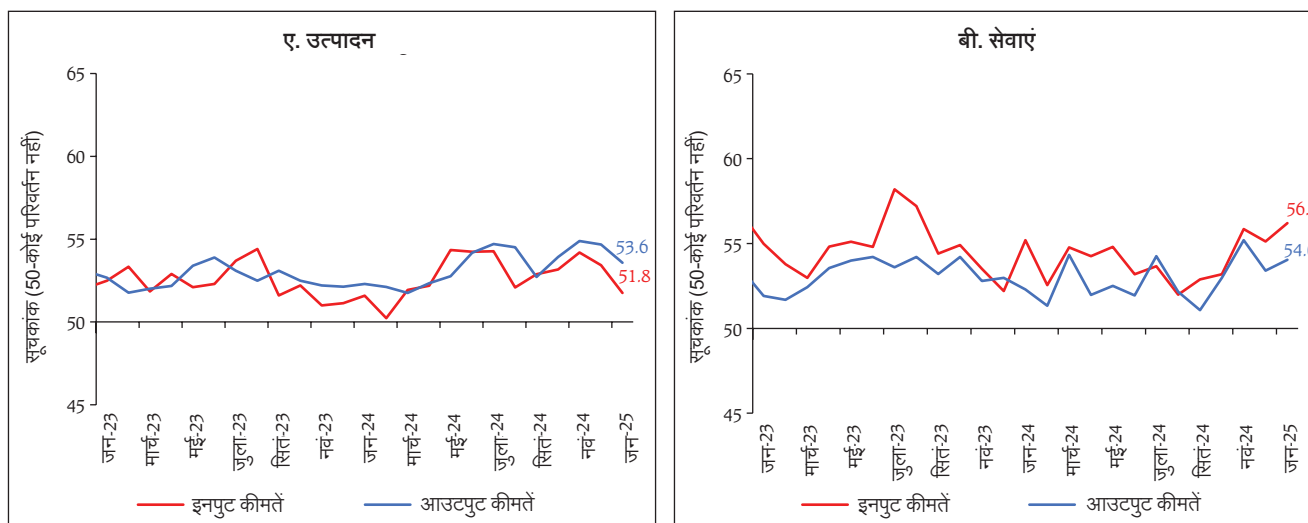
हुई। विनिर्माण फर्मों में बिक्री मूल्य दबाव कम हुआ, लेकिन सेवा फर्मों के लिए इसमें वृद्धि हुई (चार्ट III.32)।

चार्ट III. 31: डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

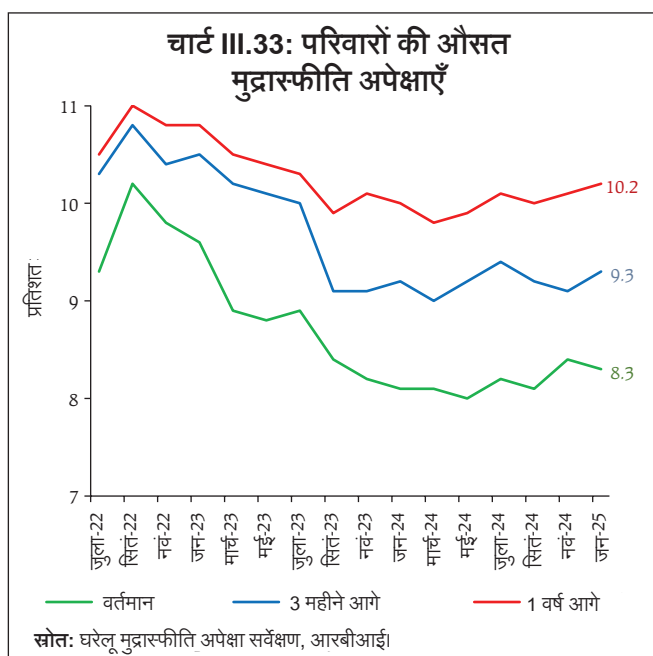
चार्ट III.32: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट मूल्य



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत

स्रोत: एस एंड पी

आरबीआई के मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण के जनवरी 2025 के दौर में मौजूदा मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की धारणा 10 बीपीएस कम होकर 8.3 प्रतिशत पर आ गई। हालांकि, अगले तीन महीनों और एक साल के लिए उनकी मुद्रास्फीति अपेक्षाएं पिछले दौर की तुलना में क्रमशः 20 बीपीएस और 10 बीपीएस बढ़ गईं (चार्ट III.33)।



IV. वित्तीय स्थितियाँ

दिसंबर 2024 के मध्य से प्रणाली में चलनिधि घाटे में चली गई है, क्योंकि तिमाही के अंत में अग्रिम कर निकासी, मासिक जीएसटी भुगतान, पूंजी निकासी और मुद्रा रिसाव के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि हुई है। बाजार सहभागियों को दिन-प्रतिदिन पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता का आश्वासन देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी, 2025 से प्रभावी दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी शुरू की। इसके अलावा, 24 जनवरी, 2025 को एक मुख्य 14-दिवसीय वीआरआर परिचालन आयोजित किया गया। चलनिधि की तंगी का संज्ञान लेते हुए, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली की टिकाऊ चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 27 जनवरी, 2025 को - खुले बाजार के संचालन, यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप और लंबी अवधि के वीआरआर आदि कई उपायों की घोषणा की। 30 जनवरी और 13 फरवरी को सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की खुले बाजार में खरीद नीलामी और 31 जनवरी को यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप ने मिलकर लगभग ₹1.04 लाख करोड़ की चलनिधि अंतर्विष्ट की। इसके अलावा, जनवरी के दौरान तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान क्षेत्र (एनडीएस-ओएम) के माध्यम से जी-

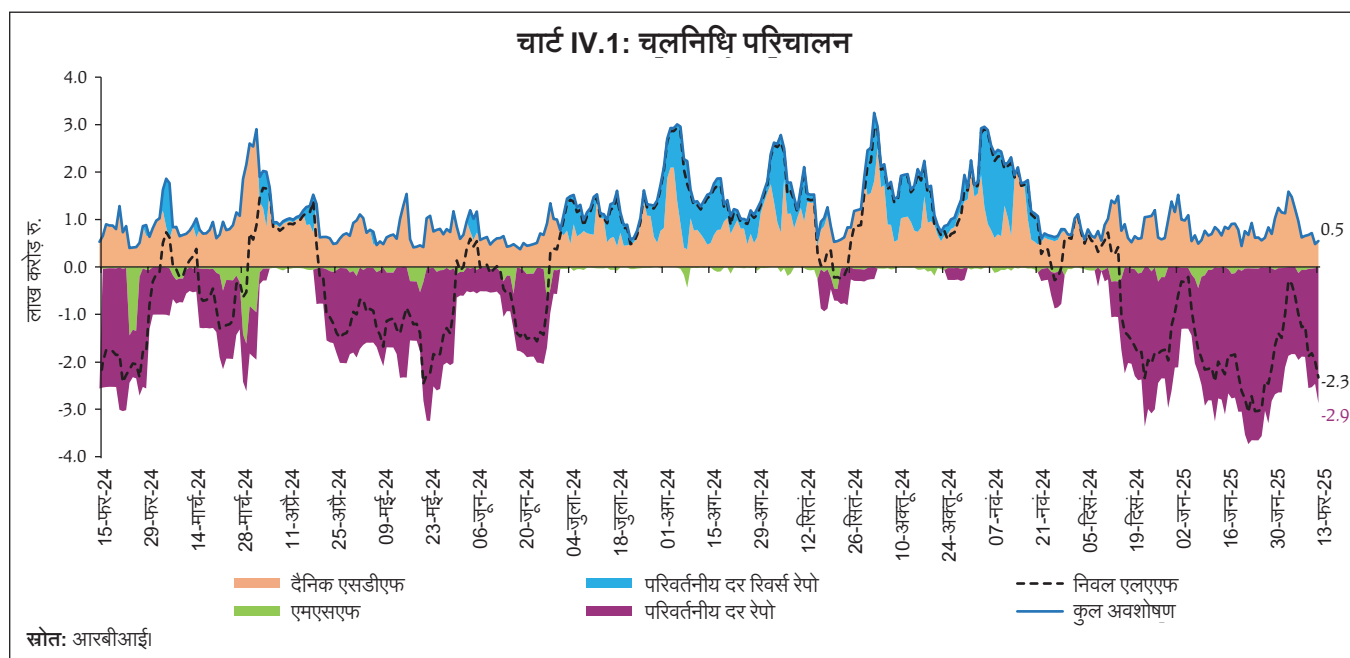
सेक की रिज़र्व बैंक की खरीद ने सिस्टम में लगभग ₹0.39 लाख करोड़ की टिकाऊ चलनिधि डाली। रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी, 2025 को ₹50,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 56-दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित की, इसके बाद 14 फरवरी, 2025 को ₹75,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 49-दिवसीय वीआरआर नीलामी की।

कुल मिलाकर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन 16 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 के दौरान ₹1.92 लाख करोड़ रहा, जबकि 16 दिसंबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के दौरान ₹1.6 लाख करोड़ का औसत निवल अंतर्वेशन दर्ज किया गया था (चार्ट IV.1)। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न चलनिधि उपायों और सरकारी खर्च में वृद्धि के परिणामस्वरूप, फरवरी की शुरुआत में चलनिधि की तंगी कुछ हद तक कम हुई। 16 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 के दौरान बैंकों द्वारा स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत औसतन ₹0.84 लाख करोड़ का निवेश किया गया, जो पिछले महीने की तुलना में अधिक है। घाटे की चलनिधि की स्थिति और एसडीएफ के तहत लगाए गए धन का सह-अस्तित्व बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के विषम वितरण और चुनिंदा बैंकों की

बंधक रहित के मांग मुद्रा बाजार में उधार देने की अनिच्छा जैसे व्यवहार संबंधी पहलुओं का संकेत है।¹⁹

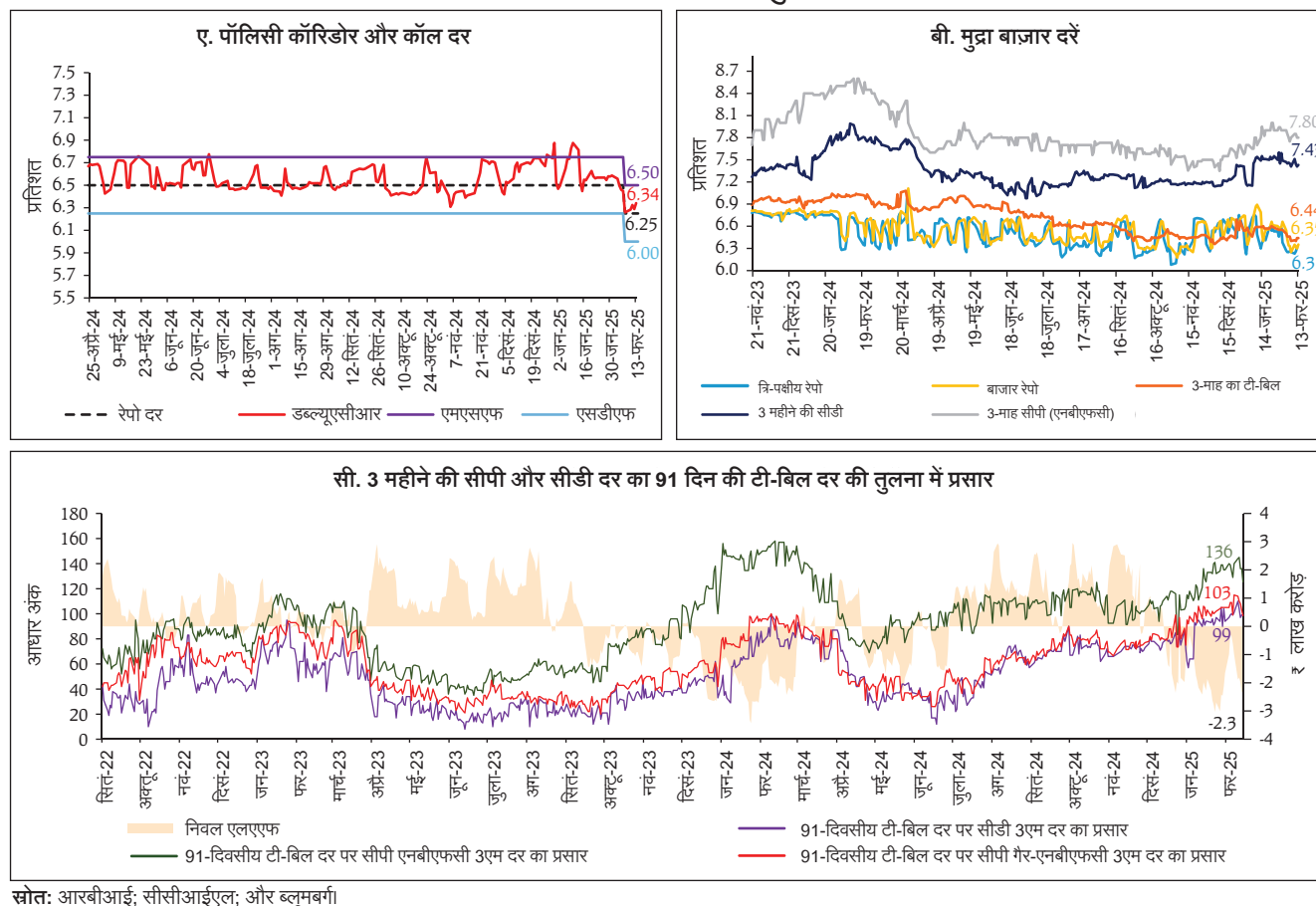
भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - दैनिक वीआरआर की शुरुआत और 7 फरवरी को रेपो दर में कटौती के साथ मध्य जनवरी से मध्यम हो गया। 16 दिसंबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के दौरान 6.69 प्रतिशत की तुलना में 16 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 के दौरान यह औसतन 6.49 प्रतिशत रही (चार्ट IV.2 ए)।

सावधि मुद्रा बाजार क्षेत्र में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर ब्याज दरें 16 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 के दौरान क्रमशः 7.49 प्रतिशत और 7.88 प्रतिशत रहीं, जो 15 दिसंबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के दौरान क्रमशः 7.35 प्रतिशत और 7.68 प्रतिशत थीं। 91-दिवसीय टी-बिल पर औसत प्रतिफल 15 दिसंबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के दौरान 6.54 प्रतिशत से 16 जनवरी - 13 फरवरी, 2025 के दौरान 6.51 प्रतिशत तक मामूली रूप से कम रही (चार्ट IV.2 बी)।



¹⁹ मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25, गवर्नर का वक्तव्य, 7 फरवरी, 2025।

चार्ट IV.2: पॉलिसी कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें

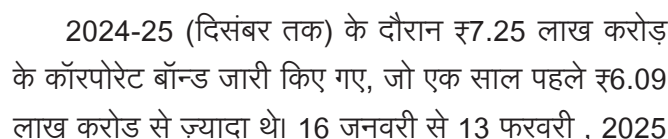


3 महीने के सीपी (एनबीएफसी) दर का 91-दिवसीय टी-बिल दर पर प्रसार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18 जनवरी - 14 फरवरी, 2025 के दौरान कम था। दूसरी ओर, 3 महीने के सीडी दर का 91-दिवसीय टी-बिल दर पर प्रसार बढ़ गया (चार्ट IV.2सी)।

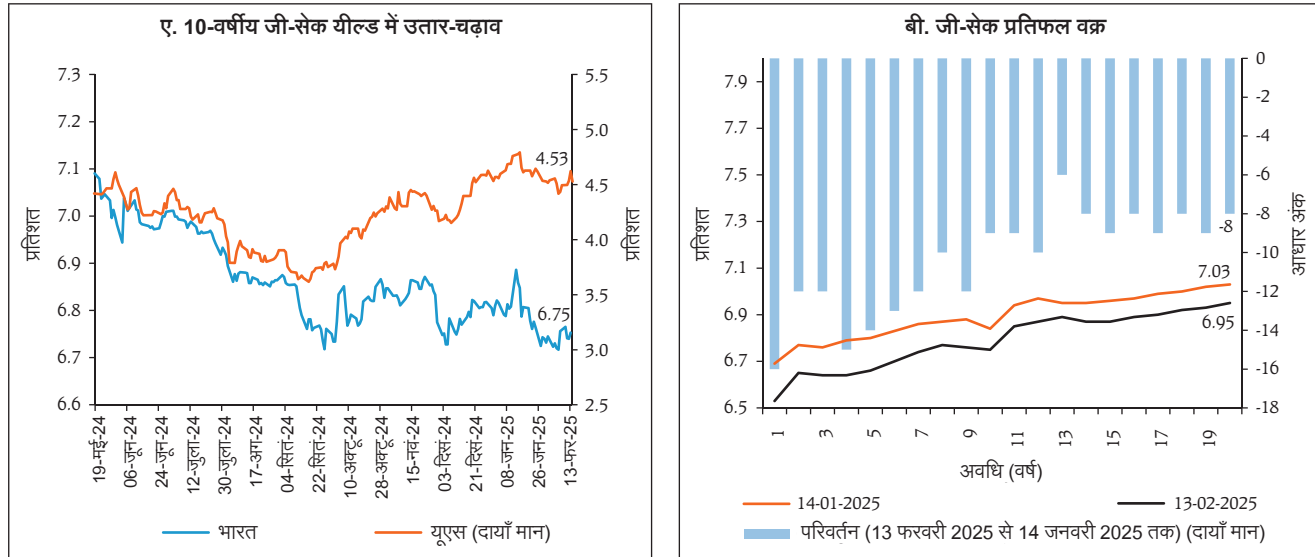
18 जनवरी - 14 फरवरी, 2025 के दौरान सीपी की भारित औसत छूट दर (डब्ल्यूएडीआर) एक साल पहले दर्ज किए गए स्तरों से कम रही (चार्ट IV.3)। सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूईआईआर) के लिए भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई। 18 जनवरी - 14 फरवरी, 2025 के दौरान डब्ल्यूईआईआर एक साल पहले के 7.86 प्रतिशत की तुलना में 7.58 प्रतिशत कम रही क्योंकि ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया।

प्राथमिक बाजार में, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 (7 फरवरी तक) के दौरान सीडी का निर्गम 43.9 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.66 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.4)। इसी तरह, 2024-25 (जनवरी तक) के दौरान सीपी का निर्गम 12.44 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 10.84 लाख करोड़ रुपये था।

10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क पर प्रतिफल 15 जनवरी, 2025 को 6.85 प्रतिशत से घटकर 13 फरवरी, 2025 को 6.75 प्रतिशत हो गई। यह नरमी अमेरिका के खजाना प्रतिफल में नरमी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और आरबीआई के चलनिधि अंतर्वेशन परिचालन (चार्ट IV.5ए) के अनुरूप थी। प्रतिफल वक्र सम्पूर्ण अवधि में नीचे की ओर खिसक गया। 16 जनवरी और 13 फरवरी, 2025 के बीच, औसत अवधि प्रसार



चार्ट IV.5: जी-सेक बाजार में विकास



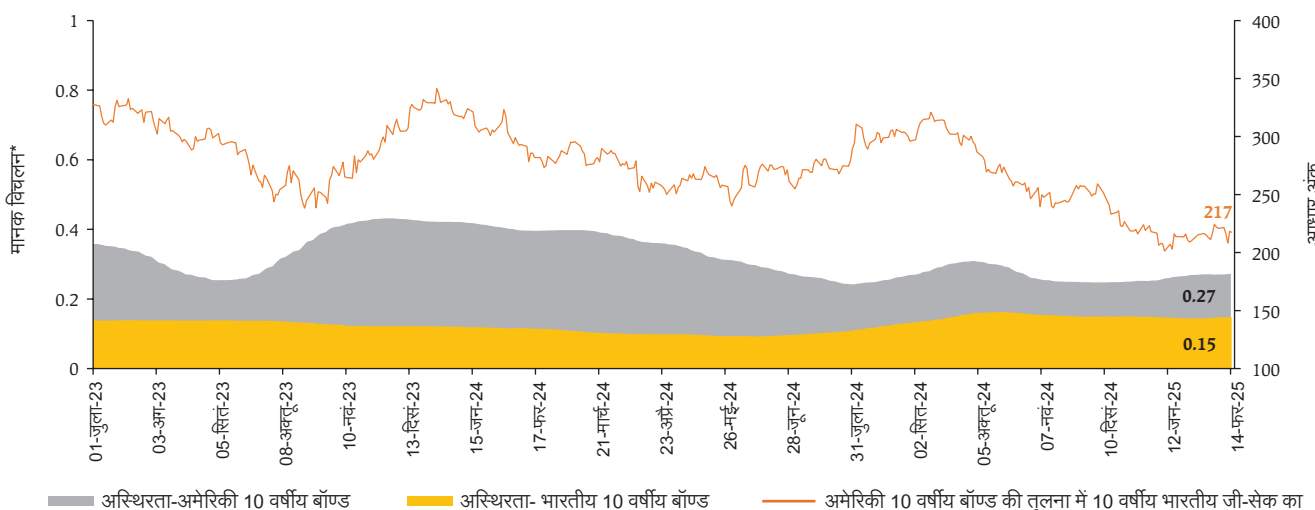
स्रोत: ब्लूमबर्ग: सीसीआईएल; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्ड का प्रतिफल आम तौर पर रेटिंग और अवधि के स्पेक्ट्रम में नरम रहा, जबकि संबंधित जोखिम प्रीमियम ने मिश्रित रुझान दिखाया (सारणी IV.1)।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 7

फरवरी, 2025 तक 6.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 5.9 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरएम के सबसे बड़े घटक, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि 7 फरवरी, 2025 तक 5.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 3.7 प्रतिशत थी।

चार्ट IV.6: अस्थिरता और स्प्रेड-बॉण्ड बाज़ार



टिप्पणी: *: 12-माह का रोलिंग मानक विचलन।

स्रोत: ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ की गणना।

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और प्रसार

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			प्रसार (आधार अंक)		
	(संबंधित जोखिम-मुक्त दर की तुलना में)					
	16 दिसंबर, 2024 – 15 जनवरी, 2025	16 जनवरी, 2025 – 13 फरवरी, 2025	भिन्नता (आधार अंक)	16 दिसंबर, 2024 – 15 जनवरी, 2025	16 जनवरी, 2025 – 10 फरवरी, 2025	उतार-चढ़ाव
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.88	7.88	0	112	117	5
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.74	7.65	-9	92	91	-1
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.62	7.50	-12	76	74	-1
(iv) एए (3-वर्षीय)	8.51	8.44	-7	169	170	1
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.18	12.11	-7	535	538	3

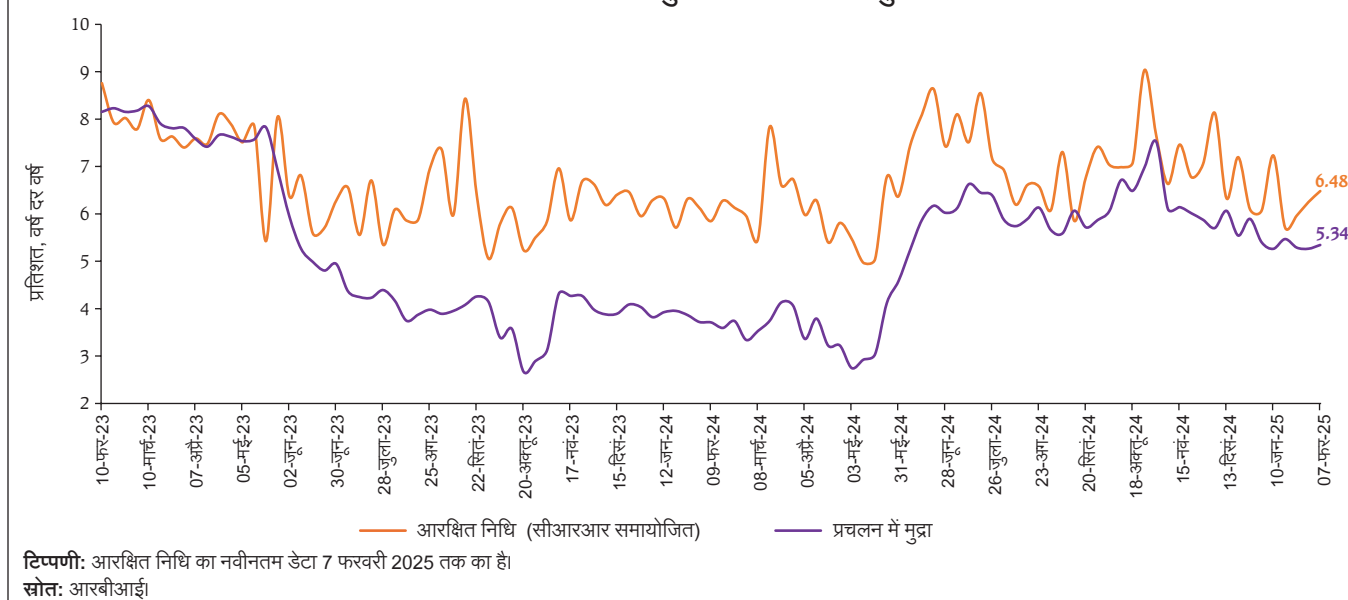
टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: एफआईएमएमडीए

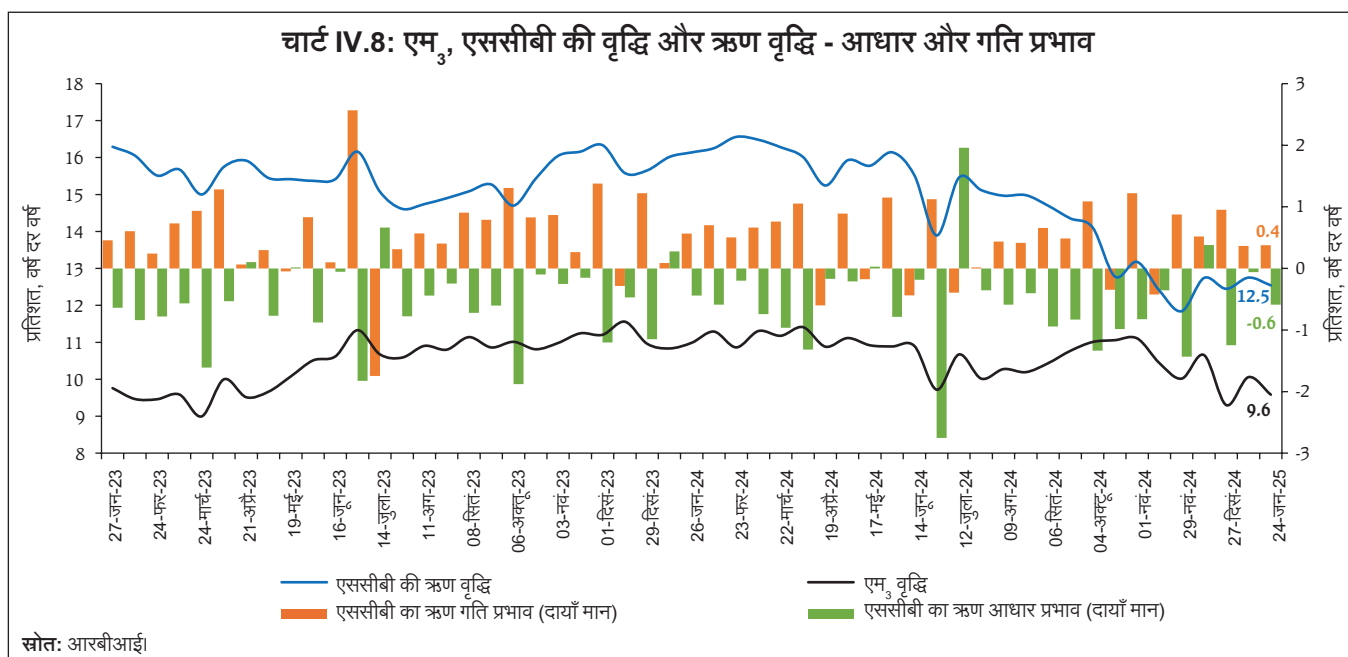
24 जनवरी, 2025 तक मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 9.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 11.0 प्रतिशत)²⁰ बैंकों के पास कुल जमा राशि, जो एम₃ का लगभग 86 प्रतिशत है, में 10.2 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 12.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 24 जनवरी, 2025 तक 12.5 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 16.1 प्रतिशत) [चार्ट IV.8]।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) 24 जनवरी 2025 को 10.6 प्रतिशत थी, जो दिसंबर 2024 के अंत में 10.2 प्रतिशत थी, जिसे जनवरी 2025 के पहले पखवाड़े में देखी गई सकारात्मक गति और अनुकूल आधार प्रभाव का समर्थन प्राप्त था (चार्ट IV.9)।

चार्ट IV.7: आरक्षित मुद्रा और प्रचलन में मुद्रा

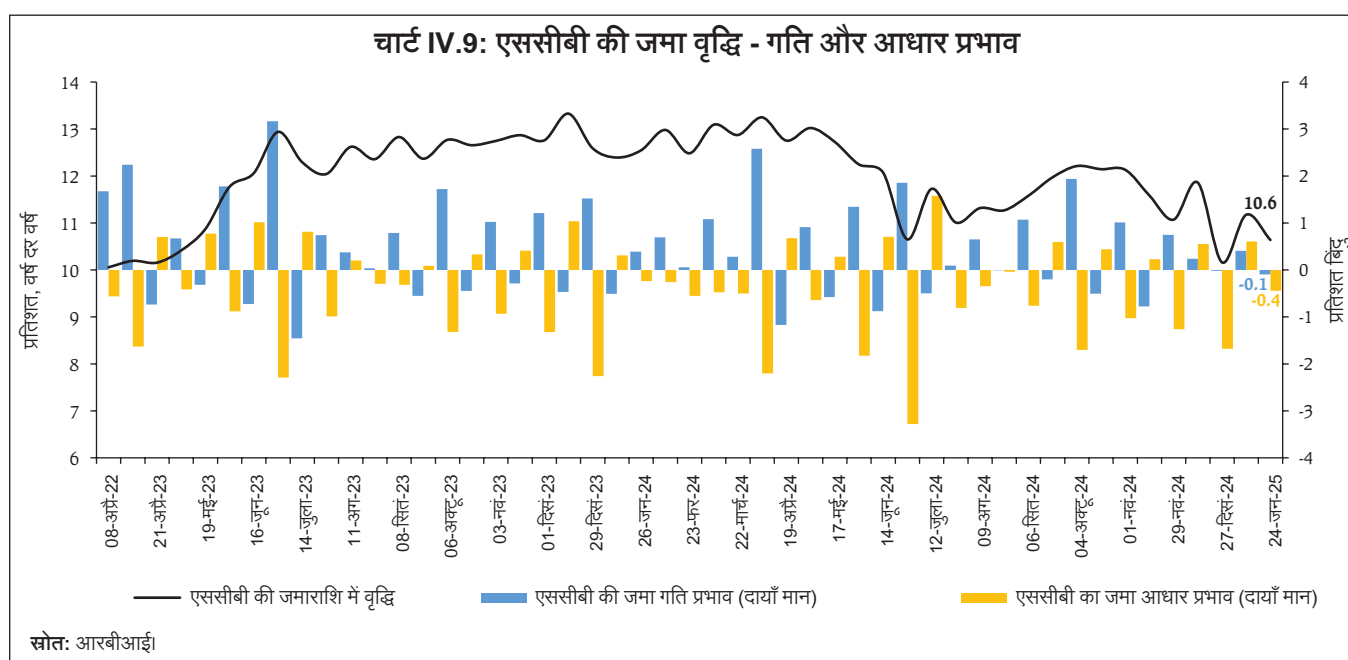


²⁰ किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।

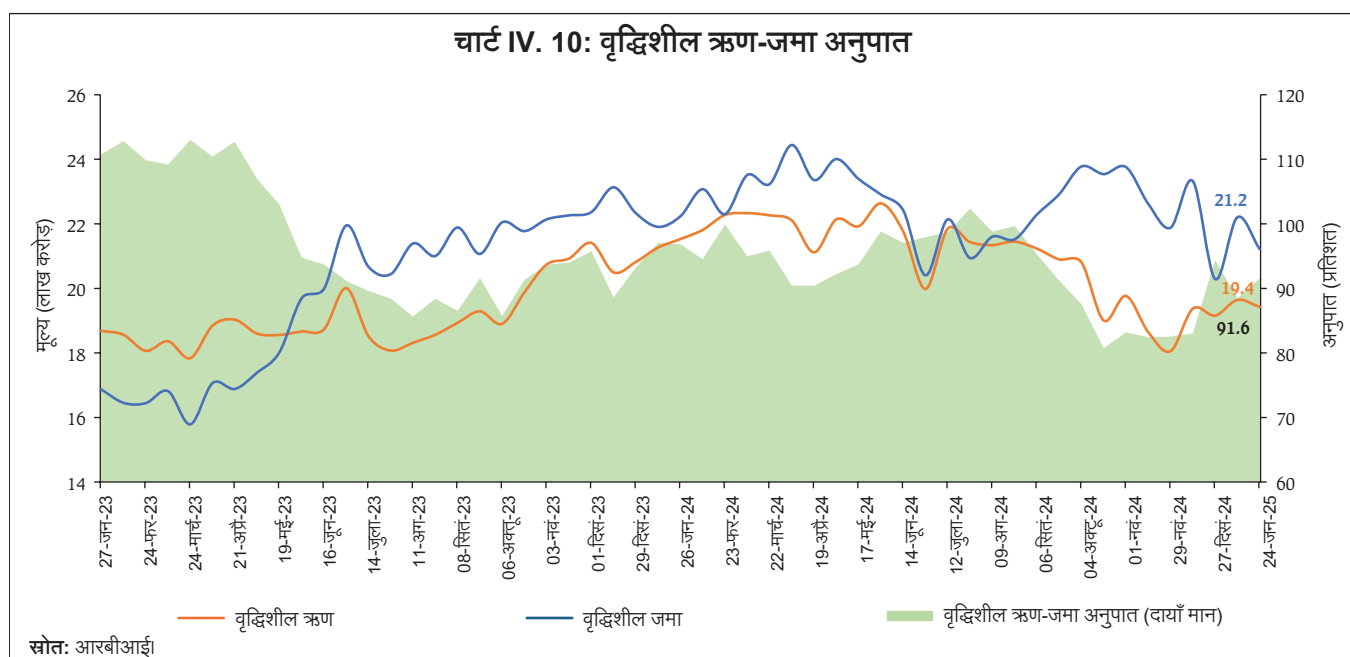


एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात अक्तूबर 2024 के अंत तक 80.7 प्रतिशत से बढ़कर 24 जनवरी 2025 को 91.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.10)।

दरों में तेजी से समायोजन के साथ, बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर)²¹ प्रणाली ने मौद्रिक नीति



²¹ रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) को यह अधिदेश जारी किया कि सभी नए परिवर्तनीय दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को परिवर्तनीय दर ऋण को नीतिगत रेपो दर या 3 महीने की टी-बिल दर या 6 महीने की टी-बिल दर या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित 1 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना चाहिए। यह निर्देश 1 अप्रैल, 2020 से मध्यम उद्यमों के लिए बढ़ा दिया गया था।



संचरण (आरबीआई, 2023)²² की गति को तेज कर दिया है। फरवरी 2025 की द्विमासिक नीति में, नीति रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया था। तदनुसार, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंकड उधार दरों को नीचे की ओर समायोजित करना शुरू कर दिया है। निधि-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत, जिसमें लंबी समायोजन अवधि होती है और जिसे जमा दरों के साथ में संदर्भित किया जाता है, को देरी से समायोजित किए जाने की उम्मीद है। मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान 250 बीपीएस नीति दर वृद्धि के प्रतिक्रिया में, एससीबी के 1 वर्ष-औसत एमसीएलआर में

178 बीपीएस की वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, मई 2022 से दिसंबर 2024 के दौरान एससीबी के नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएलआर) में क्रमशः 174 बीपीएस और 115 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)। जमा पक्ष पर, इसी अवधि के दौरान नए और बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 254 बीपीएस और 197 बीपीएस की वृद्धि हुई।

बैंक समूहों में संचरण से संकेत मिलता है कि नए रुपए ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए निजी बैंकों (पीवीबी) की तुलना में अधिक

सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों पर संचरण

(आधार अंक में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर	सावधि जमा दरें		ईबीएलआर	उधार दरें		
		डब्ल्यूएडीटीडीआर - नया जमा	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा		1-वर्ष एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएलआर - नया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण
फरवरी 2019 से मार्च 2022 तक ढिलाई युक्त चरण	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्ती की अवधि मई 2022 से दिसंबर* 2024 तक	+250	254	197	250	178	174	115

टिप्पणी: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।

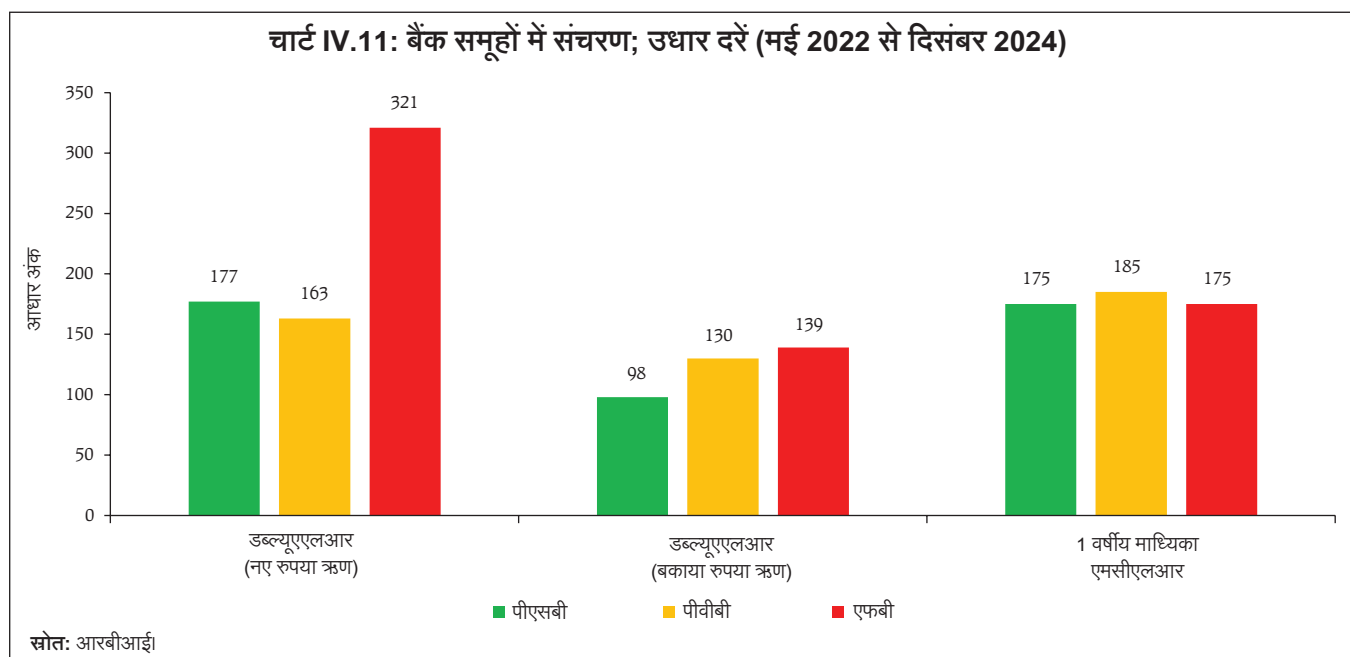
*: ईबीएलआर और एमसीएलआर पर डेटा जनवरी 2025 से संबंधित है।

डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर; **डब्ल्यूएडीटीडीआर:** भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर;

एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर; **ईबीएलआर:** बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर।

स्रोत: आरबीआई।

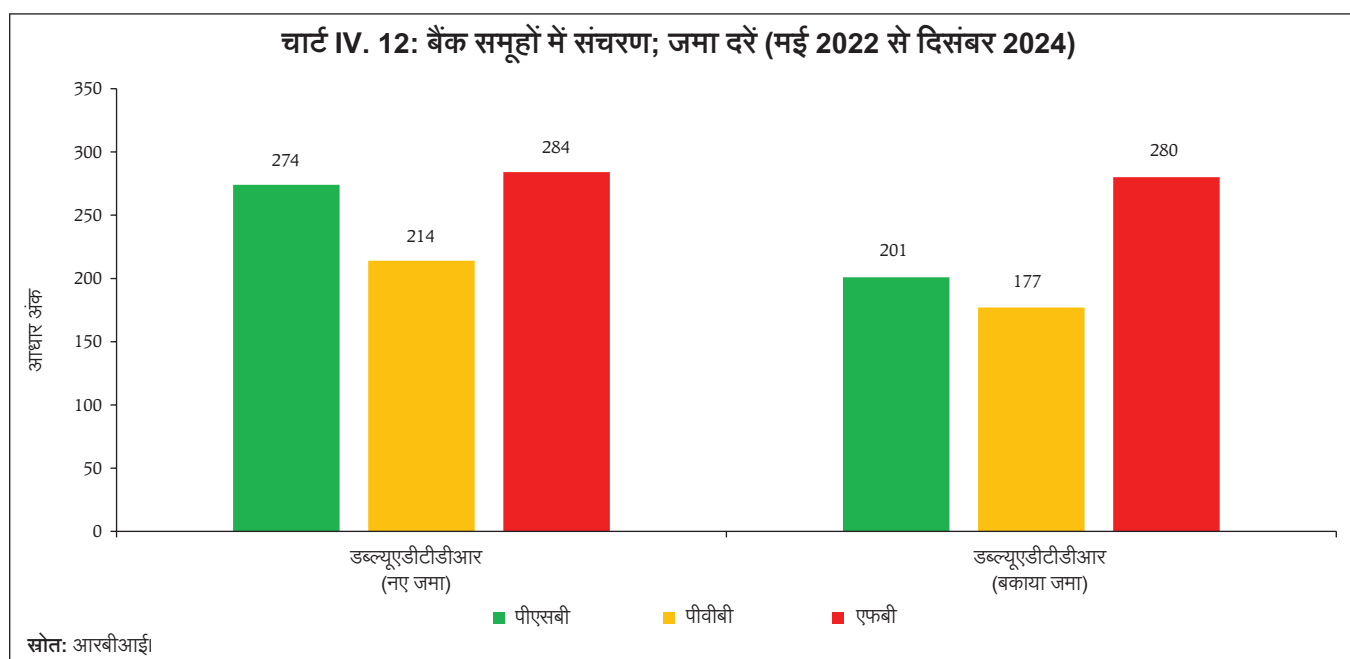
²² कश्यप, वाई., एवं अन्य., (2023)। भारत में मौद्रिक नीति संचरण: हालिया गतिशीलता, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, नवंबर- 2023, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=22192



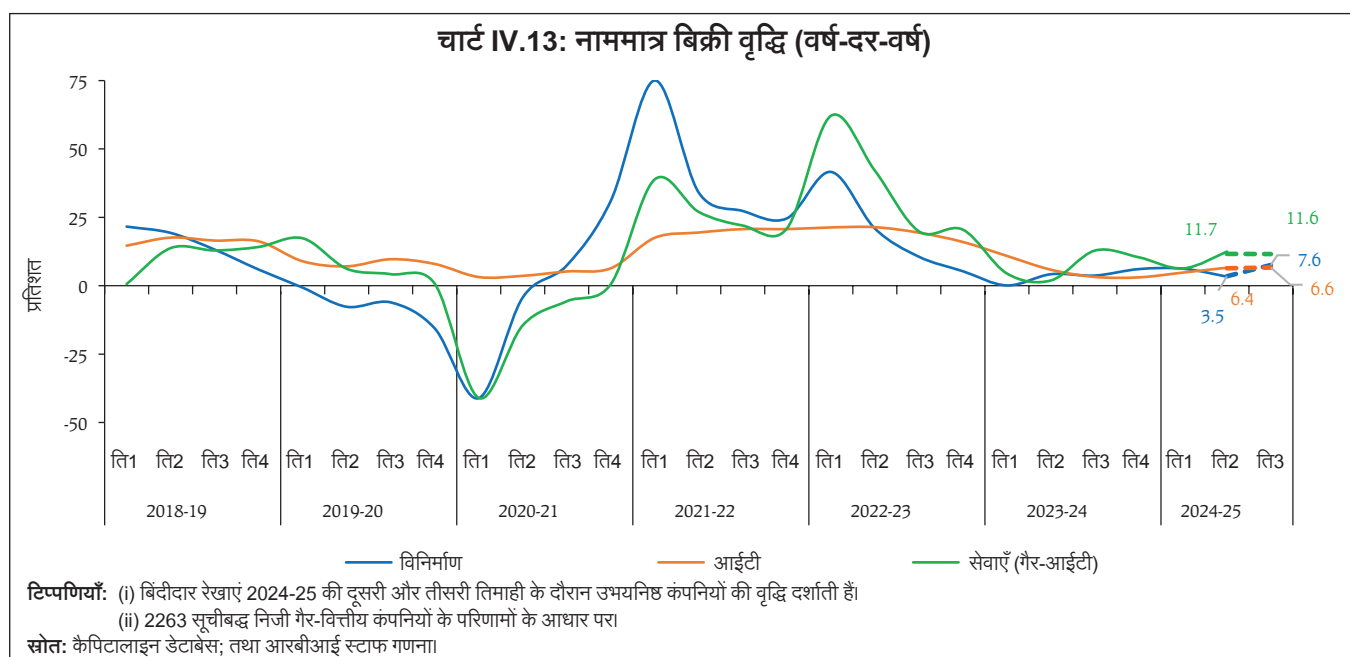
थी। हालांकि, बकाया ऋणों के मामले में, पीएसबी में संचरण कम था (चार्ट IV.11)। जमाराशियों में, मई 2022 और दिसंबर 2024 के दौरान पीवीबी की तुलना में पीएसबी के लिए नए और बकाया दोनों जमाराशियों के डब्ल्यूएडीटीडीआर में संचरण अधिक था (चार्ट IV.12)।

सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों²³ के परिणामों के आधार पर, 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान बिक्री में

7.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो पिछली तिमाही में 5.4 प्रतिशत थी। सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री में 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में यह 3.5 प्रतिशत थी (चार्ट IV.13)। ऑटोमोबाइल, रसायन, खाद्य और विद्युत मशीनरी उद्योग, जिनकी कुल मिलाकर विनिर्माण क्षेत्र की कुल बिक्री में लगभग 41 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने मुख्य रूप से

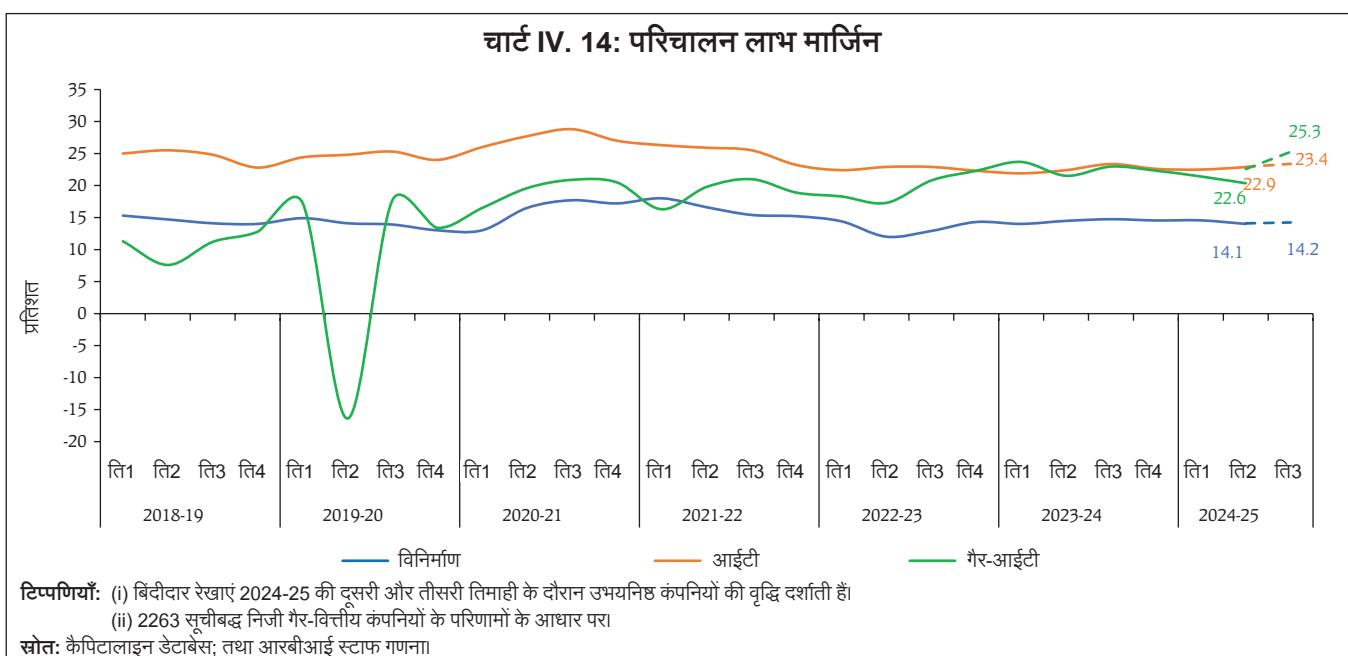


²³ 2263 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) कंपनियों पर आधारित।

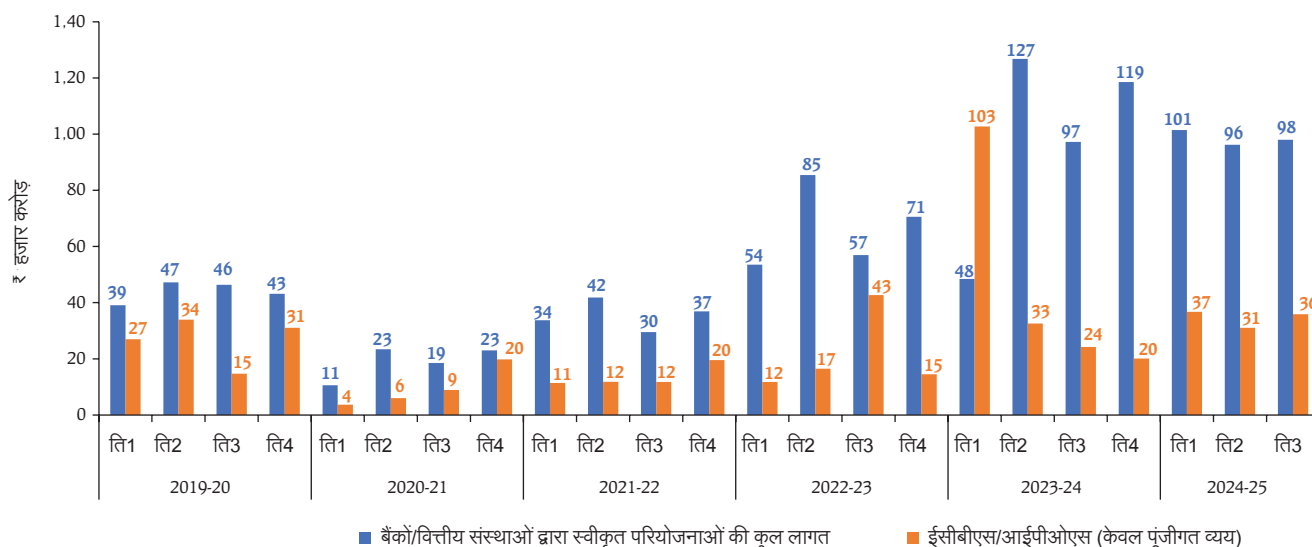


तीसरी तिमाही के दौरान विनिर्माण बिक्री वृद्धि में योगदान दिया। हालांकि, प्रमुख उद्योगों में पेट्रोलियम, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट उद्योगों की बिक्री में तीसरी तिमाही के दौरान कमी आई। गैर-आईटी सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन दोहरे अंकों की बिक्री वृद्धि से संकेत के रूप में बेहतर रहा। आईटी कंपनियों की बिक्री वृद्धि में भी थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान यह कम रही।

इनपुट लागत और अन्य खर्चों में वृद्धि के बावजूद, विनिर्माण कंपनियों के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष और क्रमिक आधार पर 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, पिछली तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही के दौरान परिचालन लाभ मार्जिन में मामूली सुधार हुआ। सेवा क्षेत्र में, 2024-25 के दौरान आईटी और गैर-आईटी सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार हुआ, जो उनकी निरंतर बिक्री वृद्धि (चार्ट IV.14) के अनुरूप है।



चार्ट IV.15: निजी कॉरपोरेट निवेश इरादे



स्रोत: आरबीआई; बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना वित्त पर आंकड़े; तथा आरबीआई स्टाफ की गणना।

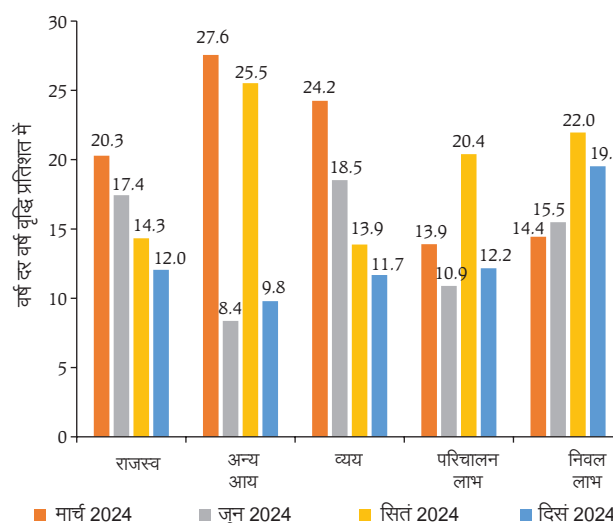
चुनिंदा बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) से एकत्र किए गए परियोजना वित्त डेटा से पता चलता है कि 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान, बैंकों/एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग ₹97,996 करोड़ थी, जो पिछली तिमाही में ₹96,226 से थोड़ी अधिक थी। लगभग 70 प्रतिशत इच्छित निवेश 'बिजली', 'धातु' और 'सड़क और पुल' उद्योगों में केंद्रित था। पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से ईसीबी और आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान ₹35,893 करोड़ थी, जबकि पिछली तिमाही में यह ₹31,027 करोड़ थी (चार्ट IV.15)।

2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान, भारतीय सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों²⁴ ने अपनी टॉप-लाइन वृद्धि में नरमी का अनुभव किया (चार्ट IV.16)। राजस्व, जिसमें मुख्य रूप से बैंकों के मामले में ब्याज आय शामिल है, ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित की, हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में इसमें कुछ नरमी आई। अन्य आय की वृद्धि, जिसमें शुल्क, कमीशन, निवेश से लाभ और हानि आदि से आय शामिल है, पिछली तिमाही की तुलना में धीमी रही। वेतन वृद्धि में नरमी के बीच व्यय वृद्धि

राजस्व वृद्धि की तुलना में धीमी रही। इसके अलावा, प्रावधान लागत में गिरावट के परिणामस्वरूप परिचालन लाभ की तुलना में निवल लाभ में तेज़ वृद्धि हुई।

जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान अब तक, भारतीय इक्विटी बाजारों ने मध्यम नुकसान दर्ज किया, बीएसई सेंसेक्स 1 प्रतिशत (15 जनवरी से) घटकर 14 फरवरी, 2025 को 75,939 पर बंद हुआ (चार्ट IV.17)। व्यापक बाजार सूचकांकों

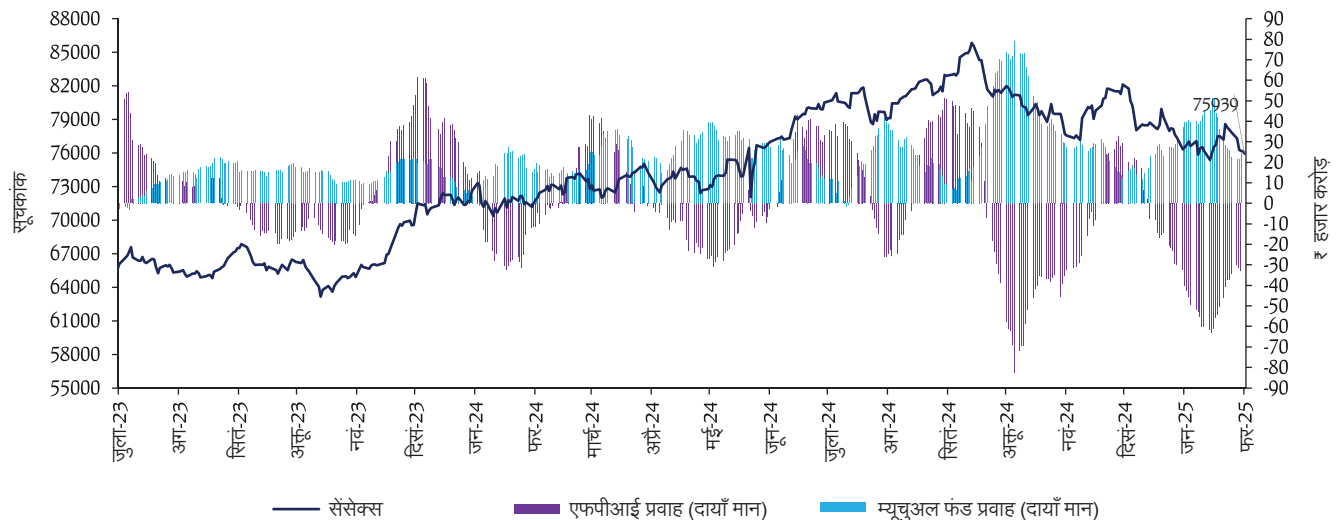
चार्ट IV. 16: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन



स्रोत: सीएमआई प्रोवेस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

²⁴ सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 81 प्रतिशत हिस्सा बनाने वाली 328 कंपनियों के नमूने के आधार पर।

चार्ट IV.17: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह



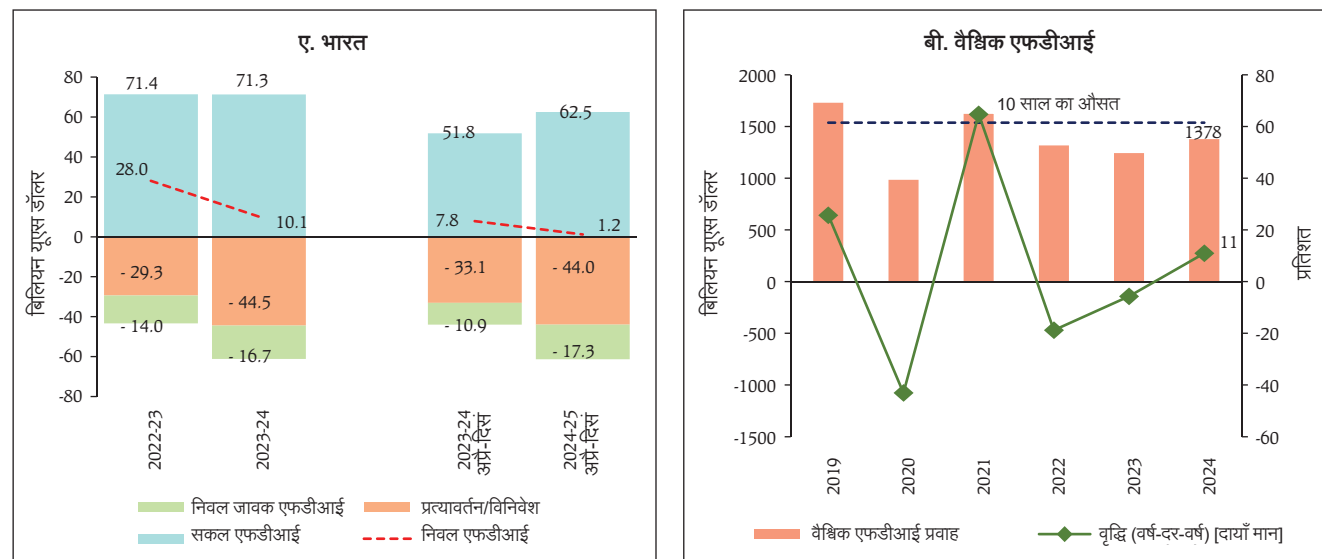
टिप्पणी: एफपीआई और एमएफ प्रवाह 15-दिवसीय रोलिंग योग के आधार पर दर्शाए जाते हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

ने बेंचमार्क से कमजोर प्रदर्शन किया, इसी अवधि के दौरान बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांकों में क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत की गिरावट आई। जनवरी के दूसरे भाग में, बाजारों में शुरुआत में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए कॉरपोरेट आय रिलीज और यूएस आउटलुक के बारे में अनिश्चितताओं का आकलन किया। बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने के लिए

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपायों की घोषणा और वैश्विक बाजारों से अनुकूल संकेतों के बीच जनवरी के अंतिम सप्ताह में बेंचमार्क ने तेज बदलाव दर्ज किया।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 20.6 प्रतिशत (व-द-व) बढ़कर 62.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट IV.18ए)। क्षेत्रों के मध्य, विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, बिजली और अन्य ऊर्जा,

चार्ट IV.18: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह



स्रोत: आरबीआई; और यूएनसीटीएडी।

और संचार सेवाओं को सकल इक्विटी अंतर्वाह का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ। सिंगापुर, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और अमेरिका शीर्ष निवेश स्रोत रहे, जिनकी इस अवधि के दौरान प्रवाह में 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रही। निवल आवक एफडीआई (यानी, प्रत्यावर्तन के लिए समायोजित सकल आवक एफडीआई) एक वर्ष पहले के 18.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान थोड़ा कम होकर 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो प्रत्यावर्तन में वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक एफडीआई 2024 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन लगातार तीसरे वर्ष अपने 10 वर्षीय औसत से नीचे रहा (चार्ट IV.18बी)।

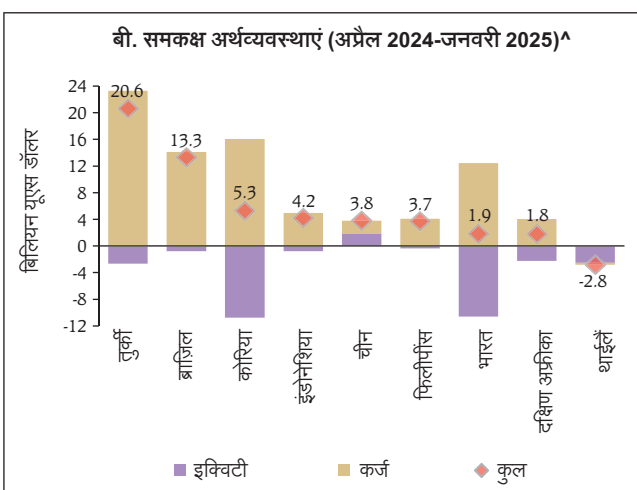
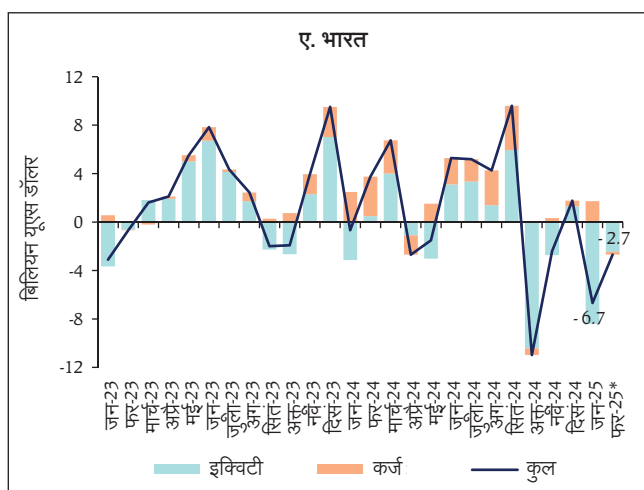
जनवरी 2025 में एफपीआई प्रवाह ऋणात्मक हो गए, जो वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि को दर्शाता है। निवेशकों के बीच जोखिम-विमुख रुझान के बढ़ने से 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इक्विटी बहिर्वाह के साथ 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल एफपीआई बहिर्वाह दर्ज किए गए (चार्ट IV.19ए)। हालांकि, कर्ज खंड ने पुनरुद्धार के संकेत दिखाए, जिसमें 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह था, जो अक्टूबर 2024 के बाद से सर्वाधिक था। 31 जनवरी 2025 को, ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज ने अपने ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट (ईएम) लोकल करेंसी इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉण्ड को शामिल किया,

जिससे कर्ज खंड में 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अंतर्वाह हुआ। 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, भारत में कर्ज अंतर्वाह समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत रहा, जिसने औने-पौने दाम पर हुई इक्विटी बिक्री के प्रभाव को कम किया (चार्ट IV.19बी)। फरवरी 2025 (13 फरवरी तक) में, निवल एफपीआई बहिर्वाह 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जारी रहा।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान गैर-निवासी जमा (एनआरडी) के तहत निवल अंतर्वाह, एक वर्ष पहले के 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें सभी तीन खातों, अर्थात् अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] खातों में प्रवाह शामिल है। अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान, निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) अंतर्वाह 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए प्रवाह का लगभग तीन गुना है (चार्ट IV.20)।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान पंजीकृत कुल ईसीबी में से 40 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसके अलावा, इस अवधि में पिछले वर्ष

चार्ट IV.19: निवल पोर्टफोलियो निवेश



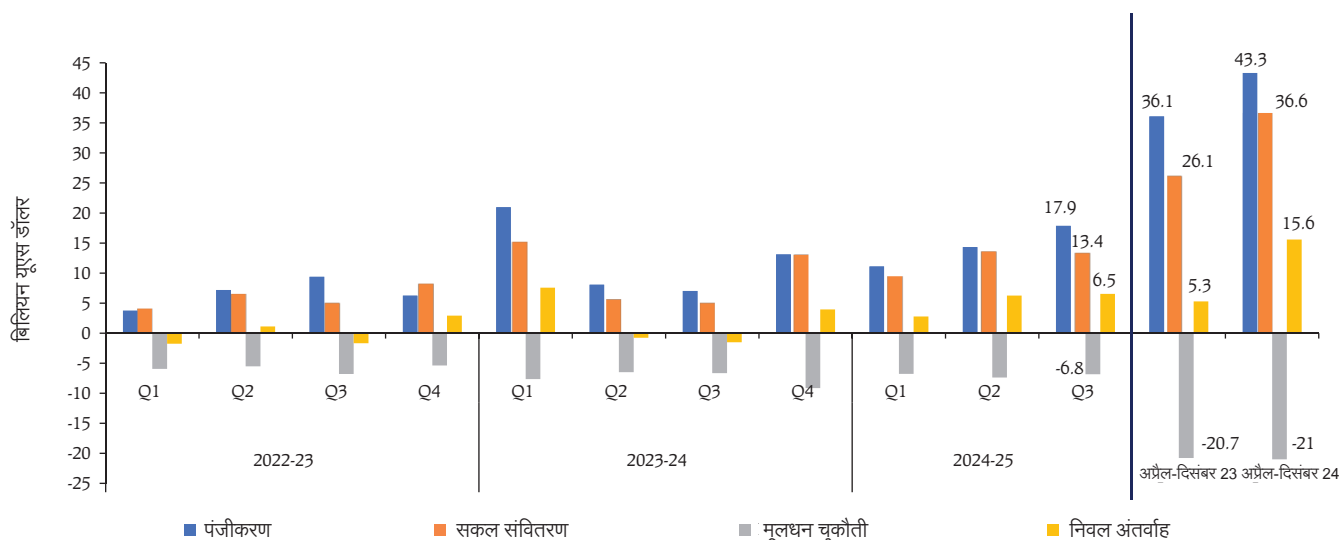
टिप्पणियाँ: 1. कर्ज में हाइब्रिड लिखतों के अंतर्गत निवेश भी शामिल है।

2.*: 13 फरवरी तक का डेटा।

3.^: भारत और अन्य देशों के लिए इक्विटी प्रवाह के आंकड़े जनवरी 2025 तक के हैं, जबकि अन्य देशों के लिए कर्ज प्रवाह दिसंबर 2024 तक के हैं।

स्रोत: नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस।

चार्ट IV.20: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण और प्रवाह



स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

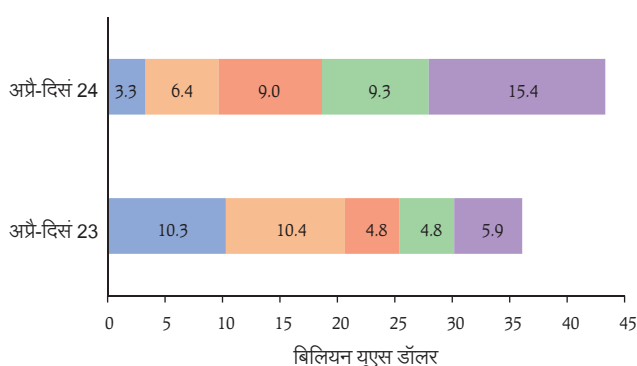
की तुलना में ईसीबी/रुपया ऋणों के पुनर्वित्तपोषण में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई (चार्ट IV.21)।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान, प्रभावी रूप से रक्षित (हेज किए गए) ईसीबी, यथा स्पष्ट रूप से हेज किए गए ऋण, रुपये में मूल्यवर्गित ऋण और विदेशी मूल कंपनियों से ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 61.6 प्रतिशत से बढ़कर 78.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.22)। यह ऐसे एक्सपोजर की ब्याज

और विनिमय दर संवेदनशीलता को प्रभावहीन करने में काफी मदद करता है।

मार्च 2024 से, वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दरें जैसे कि सुरक्षित एकदिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर) में 85 आधार अंकों तक की गिरावट हुई है, जिससे अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान ईसीबी की कुल लागत में 25 आधार अंकों की कमी आई है (चार्ट IV.23)।

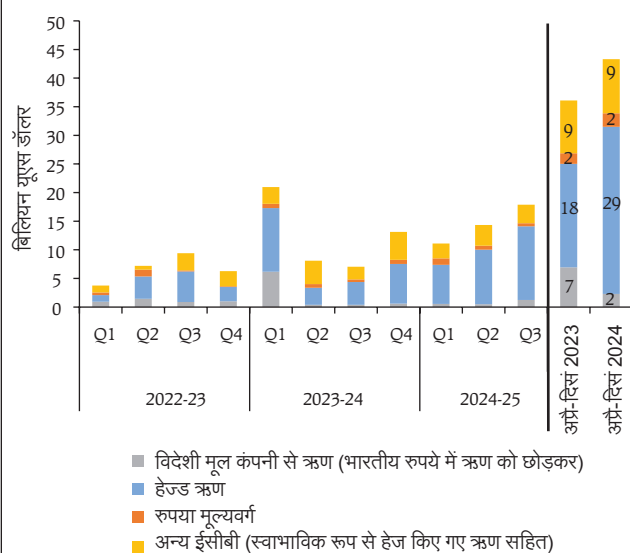
चार्ट IV.21: पंजीकृत ईसीबी का अंतिम उपयोग



- पूँजीगत वस्तुओं का आयात/स्थानीय प्रापण
- आगे उधार देना / उप-ऋण (पूँजीगत व्यय)
- अन्य (कार्यशील पूँजी और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य सहित)
- आधुनिकीकरण/नई परियोजना/बुनियादी ढांचे का विकास
- ईसीबी/रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण

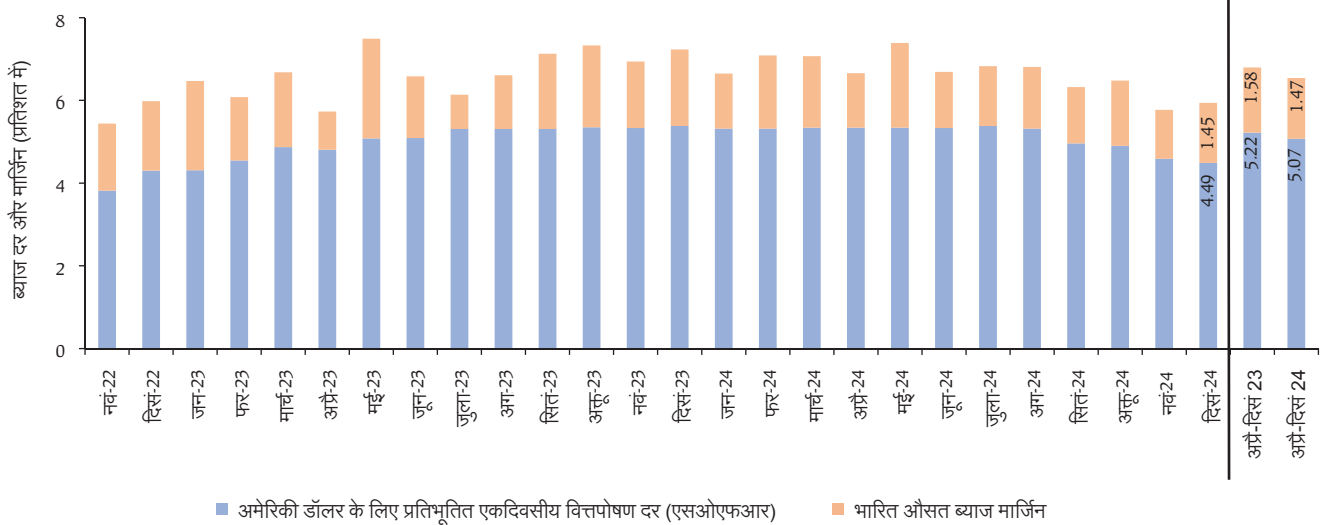
स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

चार्ट IV.22: ईसीबी समझौते - हेजिंग स्थिति



स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

चार्ट IV.23: ईसीबीएस की कुल लागत



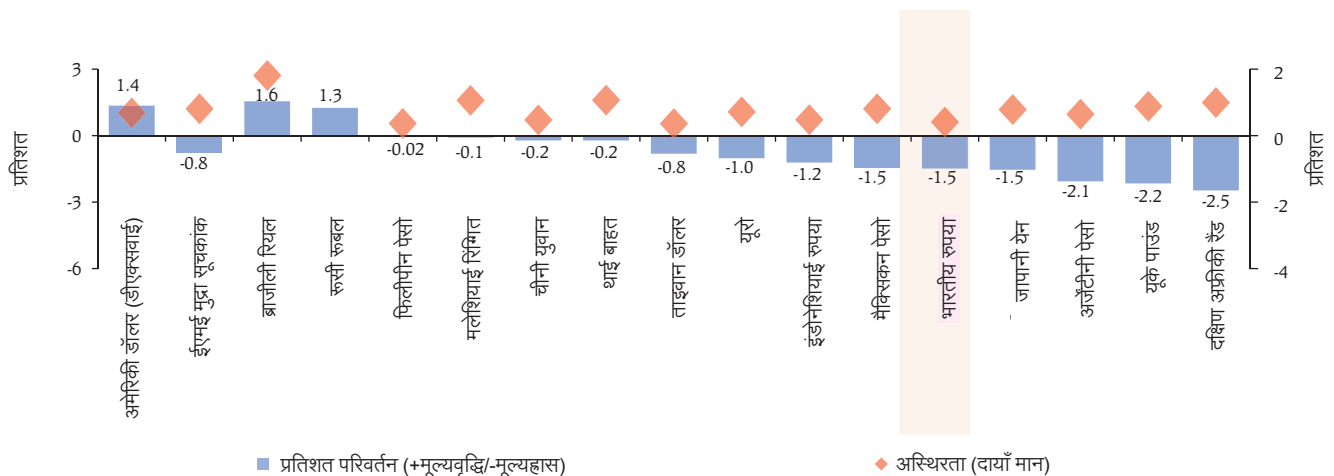
स्रोत: ईसीबी फॉर्म; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ते अमेरिकी डॉलर और ईएमई से एफपीआई के बहिर्वाह ने जनवरी 2025 के दौरान ईएमई मुद्राओं पर महत्वपूर्ण दबाव बनाया। जनवरी में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 1.5 प्रतिशत (मासिक) की गिरावट आई, जो अधिकांश प्रमुख मुद्राओं में उतार-चढ़ाव के अनुरूप

है (चार्ट IV.24)। वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के माहौल में, आईएनआर में अपेक्षाकृत कम अस्थिरता देखी गई।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, सांकेतिक प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपये के मूल्यहास और ऋणात्मक सापेक्षिक मूल्य अंतर के कारण, जनवरी 2025

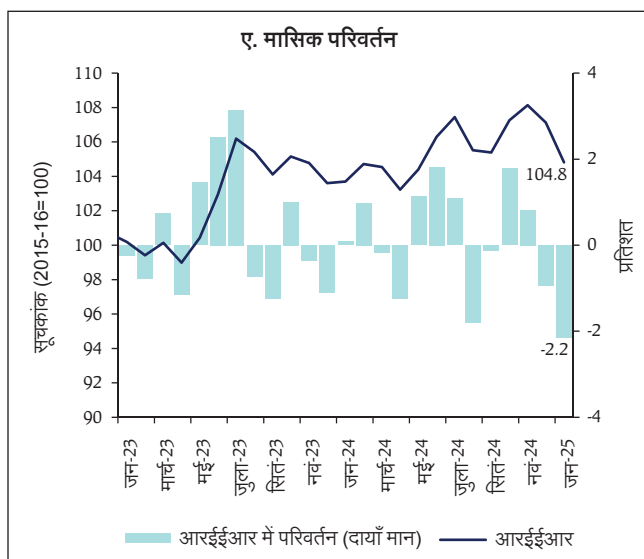
चार्ट IV.24: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं में परिवर्तन (जनवरी 2025 से दिसंबर 2024 तक)



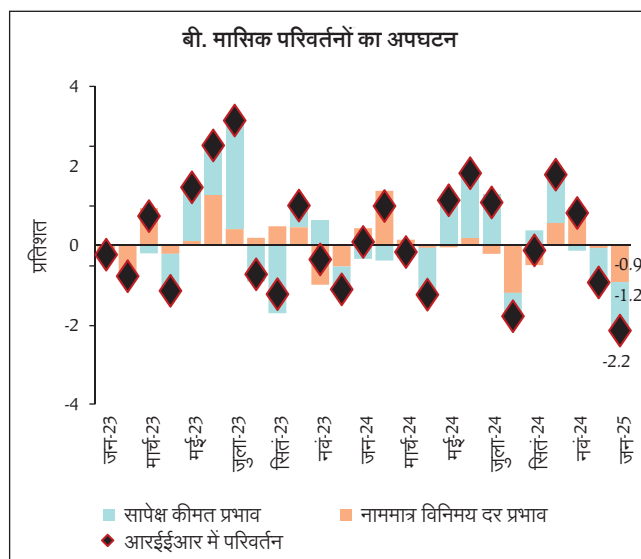
टिप्पणियाँ: अमेरिकी डॉलर (डीएसवीआई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस् फ्रैंक) की एक टोकरी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की गतिविधियों को मापता है।

स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.25: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में हलचल



स्रोत: आरबीआई



में भारतीय रुपये में 2.2 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई (चार्ट IV.25)।

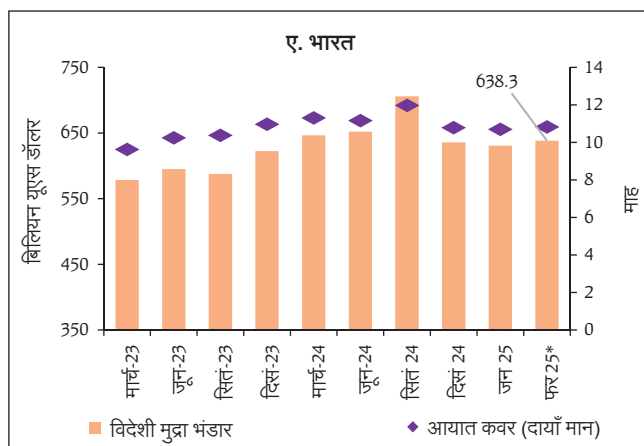
7 फरवरी 2025 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 638.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2024 के अंत में 10.8 महीने के आयात और 89.7 प्रतिशत बकाया बाह्य ऋण के लिए कवर प्रदान करता है (चार्ट IV.26ए)। विभिन्न रिजर्व

पर्याप्तता मैट्रिक्स के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर संधारणीय बना रहा (चार्ट IV.26बी)।

भुगतान प्रणालियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2024 में 465.3 पर पहुंच गया, जो देश में डिजिटलीकरण की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है।²⁵ जनवरी 2025 में, डिजिटल लेनदेन

चार्ट IV.26: विदेशी मुद्रा भंडार

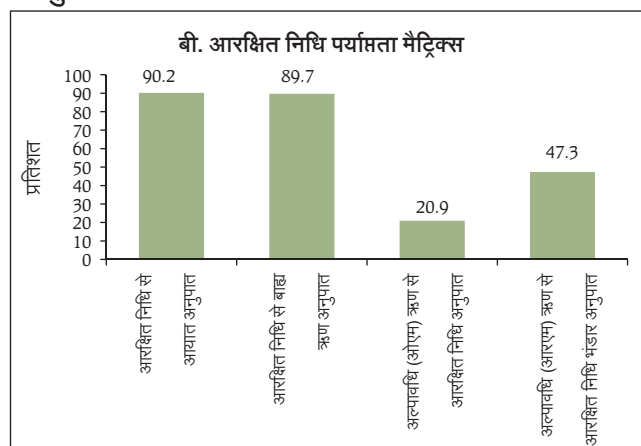


टिप्पणियाँ: 1. *: 7 फरवरी के आंकड़े।

2. दिसंबर 2024, जनवरी और फरवरी 2025 के लिए आयात कवर डेटा भुगतान संतुलन के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वार्षिक व्यापारिक आयात पर आधारित है।

3. ओएम: मूल परिपक्वता; आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता। रिजर्व पर्याप्तता मैट्रिक्स की गणना सितंबर 2024 के लिए नवीनतम उपलब्ध रिजर्व डेटा और वार्षिक व्यापारिक आयात और बाहरी ऋण का उपयोग करके की गई है।

स्रोत: आरबीआई; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।



²⁵ आरबीआई प्रेस प्रकाशनी, 29 जनवरी 2025, "आरबीआई – सितंबर 2024 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक"।

सारणी IV.3 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली	लेनदेन मात्रा				लेनदेन मूल्य			
	दिसं -23	दिसं-24	जन-24	जन-25	दिसं -23	दिसं -24	जन-24	जन-25
आरटीजीएस	7.1	13.8	13.1	16.1	15.7	20.6	17.1	19.1
एनईएफटी	37.5	24.5	43.4	24.5	13.0	13.2	19.8	14.3
यूपीआई	53.5	39.2	51.8	39.3	42.2	27.5	41.7	27.5
आईएमपीएस	2.7	-11.6	7.2	-12.7	17.2	5.5	18.6	7.1
एनएसीएच	10.9	28.2	22.8	17.2	4.6	27.6	21.5	22.5
एनईटीसी	13.0	9.8	10.2	14.8	18.6	13.3	15.5	19.0
बीबीपीएस	25.7	95.4	24.6	97.4	77.4	260.0	75.4	276.4

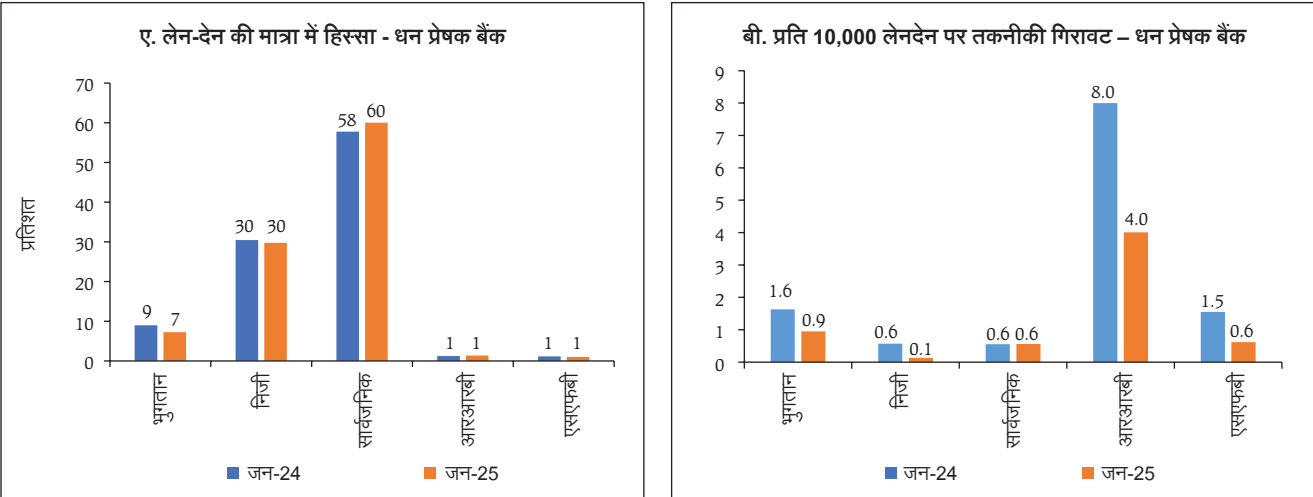
नोट: आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान; एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफेस; आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा; एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; और बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।
स्रोत: आरबीआई।

ने भुगतान मोड में व्यापक संवृद्धि गति को बनाए रखा, यद्यपि खुदरा भुगतान खंडों में वृद्धि में कुछ मंदी आई (सारणी IV.3)।

जनवरी 2025 के दौरान लेन-देन की मात्रा (विशेषकर बैंक की ओर से) में पीएसबी की हिस्सेदारी में एक वर्ष पहले दर्ज स्तरों की तुलना में वृद्धि हुई (चार्ट IV.27ए)। जनवरी

2024²⁷ की तुलना में जनवरी 2025 में अधिकांश बैंक श्रेणियों में प्रति 10,000 यूपीआई लेन-देन में तकनीकी अस्वीकरण²⁶ की संख्या कम हो गई, जो उच्च लेन-देन मात्रा के बावजूद बैंकों की प्रणालियों की बढ़ी हुई दक्षता को दर्शाती है। हालाँकि, बैंक समूहों में निष्पादन असमान रहा (चार्ट IV.27बी)।

चार्ट IV.27: यूपीआई लेनदेन में रुझान - बैंक समूहवार



टिप्पणी: सार्वजनिक: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; निजी -निजी क्षेत्र के बैंक; एसएफबी: लघु वित्त बैंक; आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; भुगतान: भुगतान बैंक। आंकड़े भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शीर्ष 50 सदस्यों के लिए रिपोर्ट किए गए लेनदेन की मात्रा पर आधारित हैं।
स्रोत: एनपीसीआई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

²⁶ तकनीकी कारणों से लेनदेन पूरा नहीं हो पाना, जैसे बैंक या एनपीसीआई की ओर से प्रणाली की अनुपलब्धता और नेटवर्क संबंधी समस्याएं।
²⁷ विशेषकर बैंकों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, तकनीकी अस्वीकरण (टीडी) दर 0.55 से मामूली रूप से बढ़कर 0.56 हो गई। लाभार्थी बैंकों के रूप में भुगतान बैंकों के लिए, टीडी दर 0.12 से बढ़कर 0.81 हो गई।

कार्ड टोकनाइजेशन और इसका उपयोग बढ़ रहा है, 98 प्रतिशत ई-कॉमर्स लेनदेन वास्तविक कार्ड डेटा का उपयोग किए बिना संसाधित किए जा रहे हैं।²⁸ रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में, भारत में जारी किए गए कार्डों का उपयोग करके ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (ऑनलाइन) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफए) सक्षम करने का प्रस्ताव रखा है।²⁹ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारतीय बैंकों के लिए 'bank.in' विशिष्ट इंटरनेट डोमेन भी शुरू कर रहा है ताकि साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी द्वेषपूर्ण गतिविधियों को कम किया जा सके, और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। ऑनलाइन और अन्य धोखाधड़ी को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने विनियमित निकायों के लिए विनियामक निर्देश और संस्थागत सुरक्षा उपाय जारी किए हैं, जिनमें मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची का उपयोग, मानक परिचालन प्रक्रियाओं का विकास तथा लेन-देन और प्रचार कॉल के लिए समर्पित नंबरिंग शृंखला शामिल हैं।³⁰ रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत मौद्रिक दंड लगाने और अपराधों को कम करने के लिए रुपरेखा के तहत अनुदेशों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है।³¹ 31 जनवरी 2025 तक, दो निकायों ने जनवरी 2025 में विनियामक सैंडबॉक्स के 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा के तहत परीक्षण चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।³²

V. निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था का सन्निकट दृष्टिकोण, अवस्फीति की धीमी गति के बीच, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की व्यापार-संबंधी

नीतियों द्वारा आकार ले रहा है। ऐसी चिंताएँ हैं कि ये नीतियाँ मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती हैं, वित्तीय स्थितियाँ सख्त कर सकती हैं और बाज़ार में उथल-पुथल बढ़ा सकती हैं। यूएस आर्थिक समुत्थानशीलता और व्यापार नीति धुरी द्वारा संचालित एक मज़बूत डॉलर, उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी बहिर्वाह को बढ़ा सकता है, जोखिम प्रीमियम में वृद्धि कर सकता है और बाह्य कमजोरियों को बढ़ा सकता है। ऐसे माहौल में अवस्फीति का "अंतिम लक्ष्य" अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए संभावित रूप से केंद्रीय बैंकों को नीतियों को पुनः समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

भारत में, आर्थिक गतिविधि की गति बनी रहने की संभावना है, कृषि क्षेत्र के मज़बूत निष्पादन से ग्रामीण मांग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शहरी मांग में भी सुधार होने की संभावना है, मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ-साथ केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित आय कर में बड़ी छूट से प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी। संवृद्धि के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात - को बढ़ावा देने के लिए बजट उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यमावधि संवृद्धि संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट ने पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके राजकोषीय सुदृढ़ता और संवृद्धि उद्देश्यों को संतुलित किया है, साथ ही कर्ज समेकन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करते हुए उपभोग को बढ़ावा देने के उपायों पर भी ध्यान दिया है। 7 फरवरी 2025 को अपनी बैठक में एमपीसी द्वारा रेपो दर में कटौती से घरेलू मांग को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

बहुतायत में खरीफ उत्पादन और बेहतर रबी बुवाई, साथ ही उच्च जलाशय स्तर और सब्जियों की कीमतों में मौसमी सर्दियों में सुधार, भविष्य में खाद्य मुद्रास्फीति के लिए शुभ संकेत हैं। जबकि मूल मुद्रास्फीति में कमी बनी हुई है, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता, ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता और प्रतिकूल मौसम की घटनाएँ मुद्रास्फीति के दिशा-पथ के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं।³³

²⁸ आरबीआई, 2025। भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024।

²⁹ आरबीआई प्रेस प्रकाशनियाँ, 07 फरवरी 2025।

³⁰ आरबीआई अधिसूचनाएँ। 17 जनवरी 2025। वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम - विनियामक निर्देश और संस्थागत सुरक्षा उपाय।

³¹ आरबीआई अधिसूचनाएँ। 30 जनवरी 2025। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत मौद्रिक दंड अधिरोपित करने और अपराधों की कपाउंडिंग करने के लिए फ्रेमवर्क।

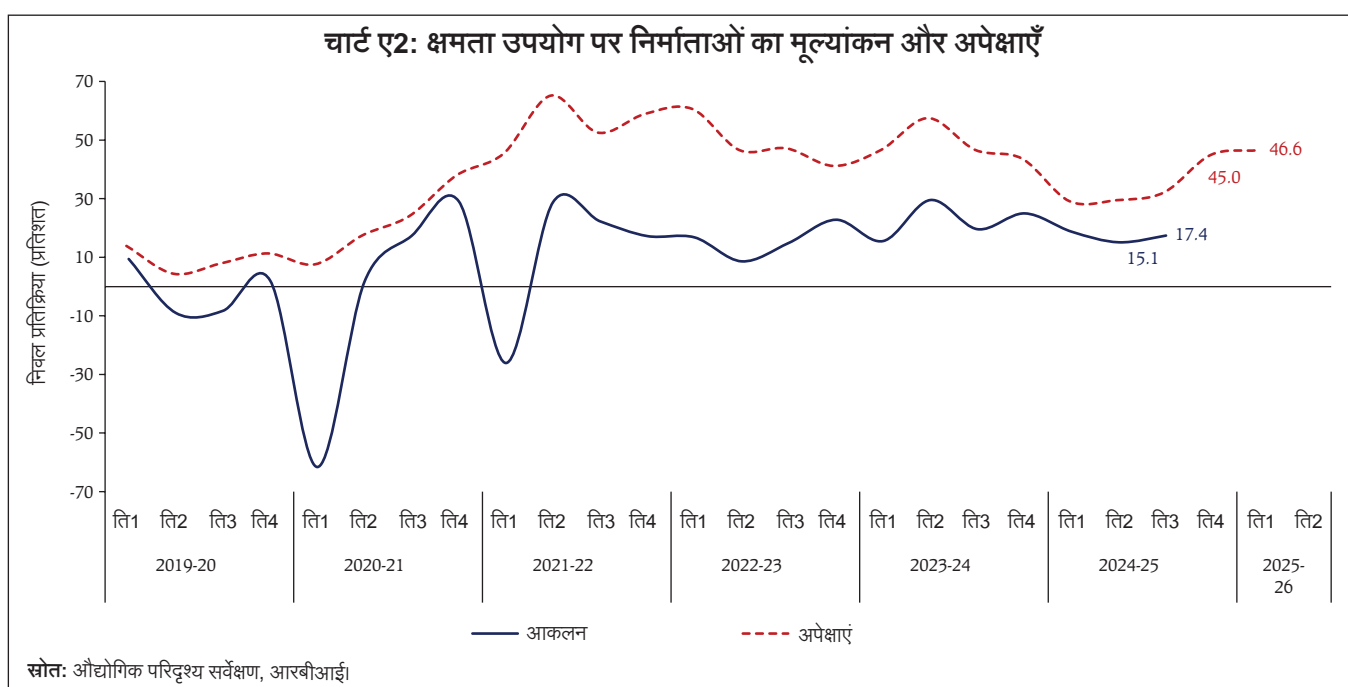
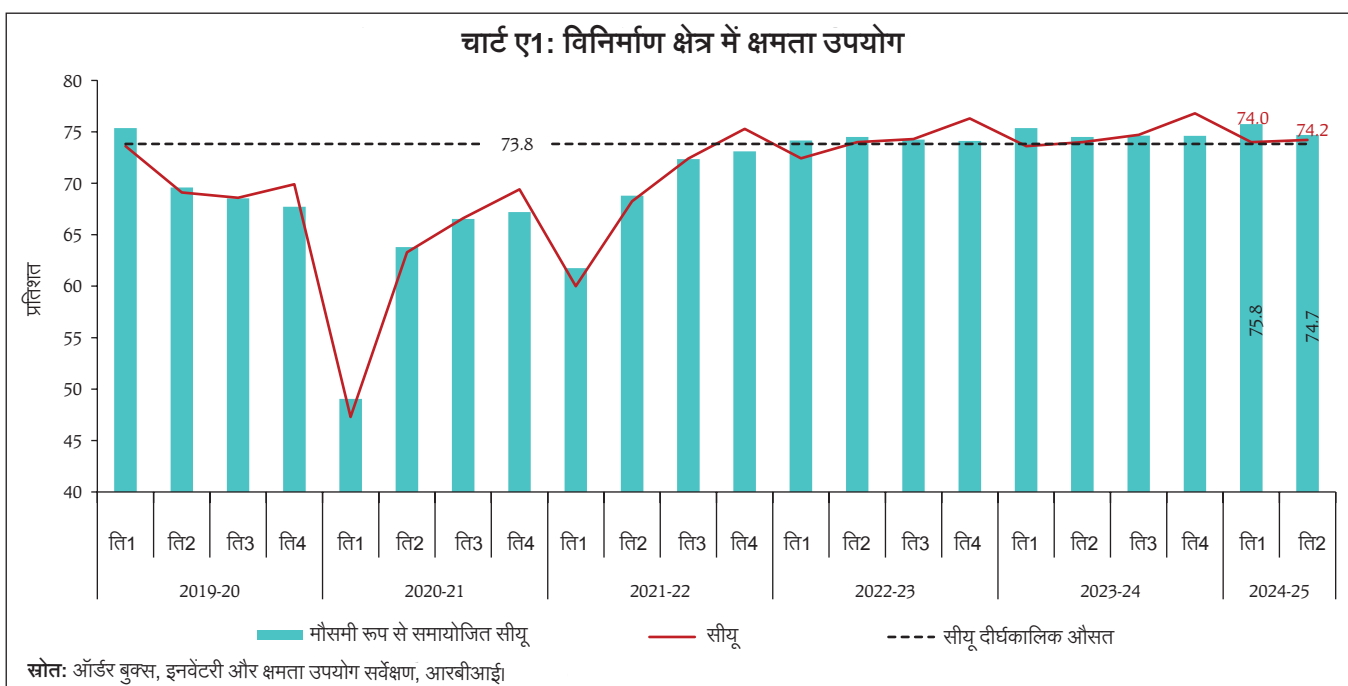
³² आरबीआई प्रेस प्रकाशनी। 29 जनवरी 2025। विनियामक सैंडबॉक्स: 'खुदरा भुगतान' विषय पर ऑन टैप एप्लिकेशन - परीक्षण चरण का समापन।

³³ मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25, मौद्रिक नीति समिति का संकल्प, 5-7 फरवरी 2025।

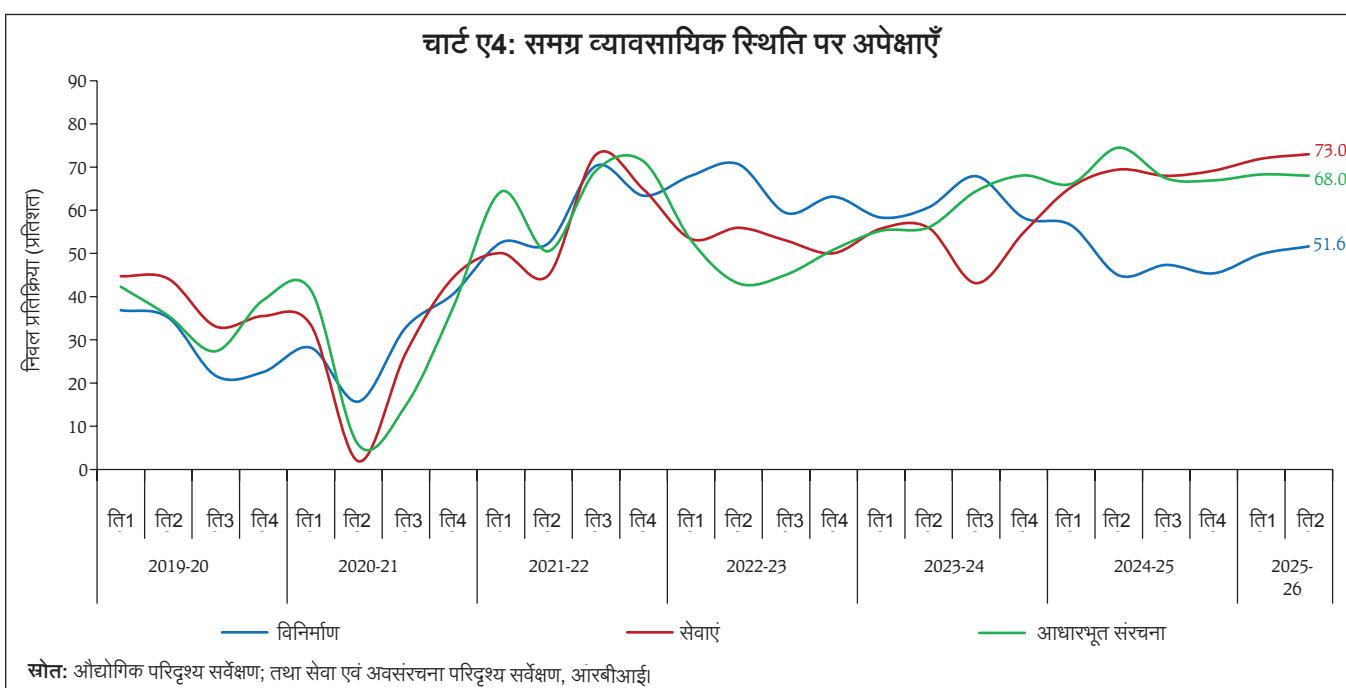
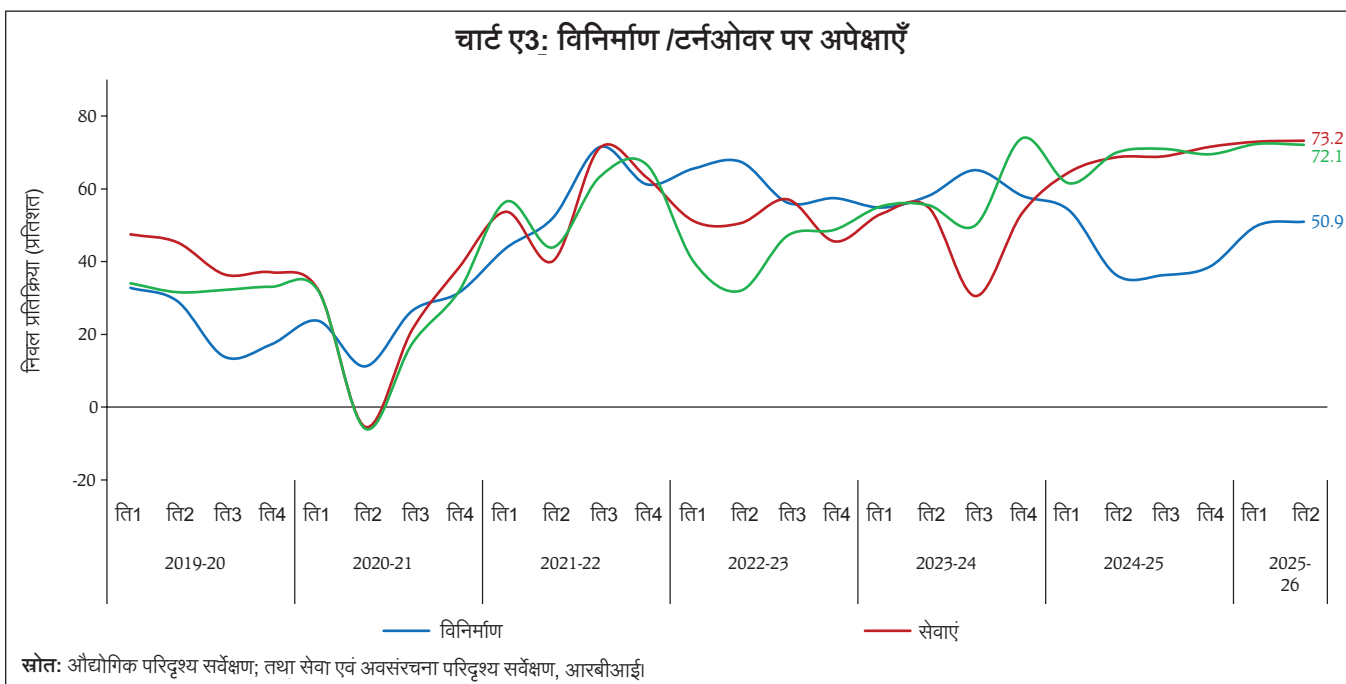
अनुबंध I

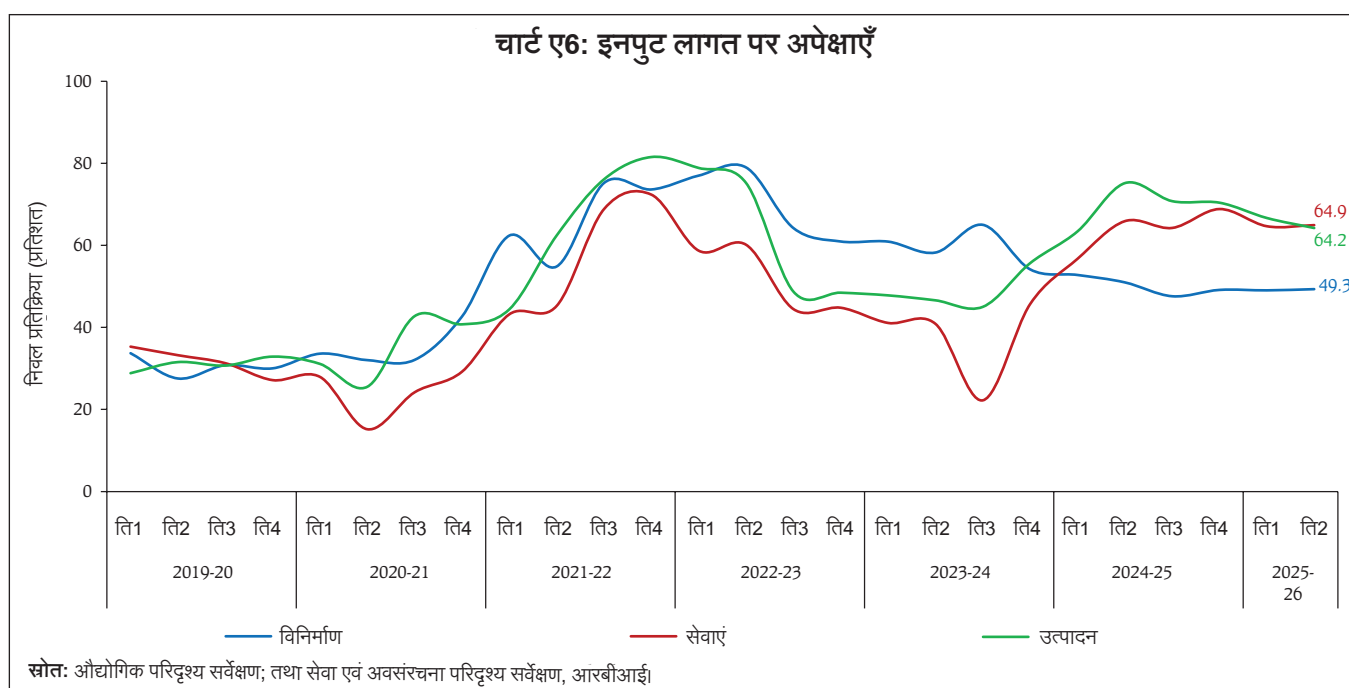
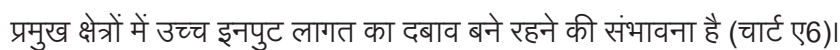
आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष

विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) पिछली तिमाही के 74.0 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 74.2 प्रतिशत हो गया। हालांकि, मौसमी रूप से समायोजित सीयू पिछली तिमाही से 110 आधार अंकों की गिरावट के साथ 74.7 प्रतिशत पर आ गया। विनिर्माताओं ने आगामी तिमाहियों में सीयू पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा (चार्ट ए1 और ए2)।

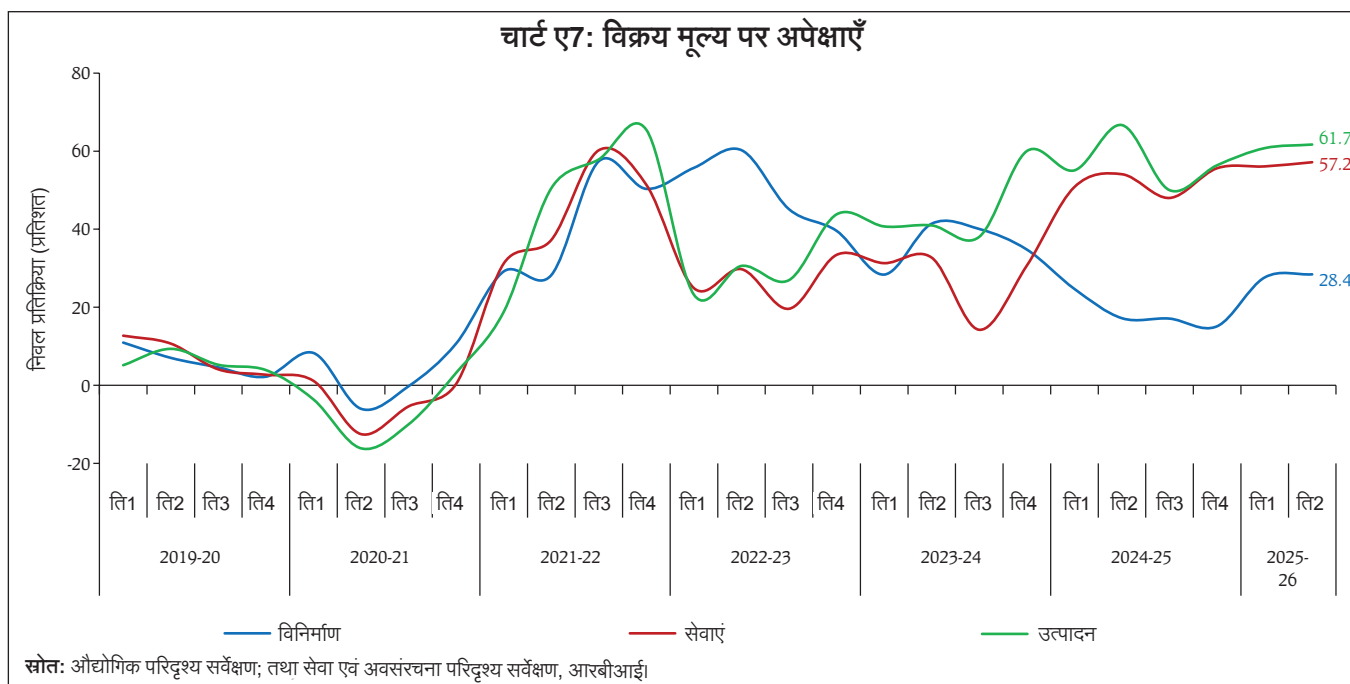


सभी प्रमुख क्षेत्र 2025-26 की दूसरी तिमाही तक उत्पादन/कारोबार और समग्र कारोबार स्थिति के बारे में आशावादी बने रहे (चार्ट ए3 और ए4)। रोज़गार की स्थिति मांग की स्थिति के अनुरूप है (चार्ट ए5)।

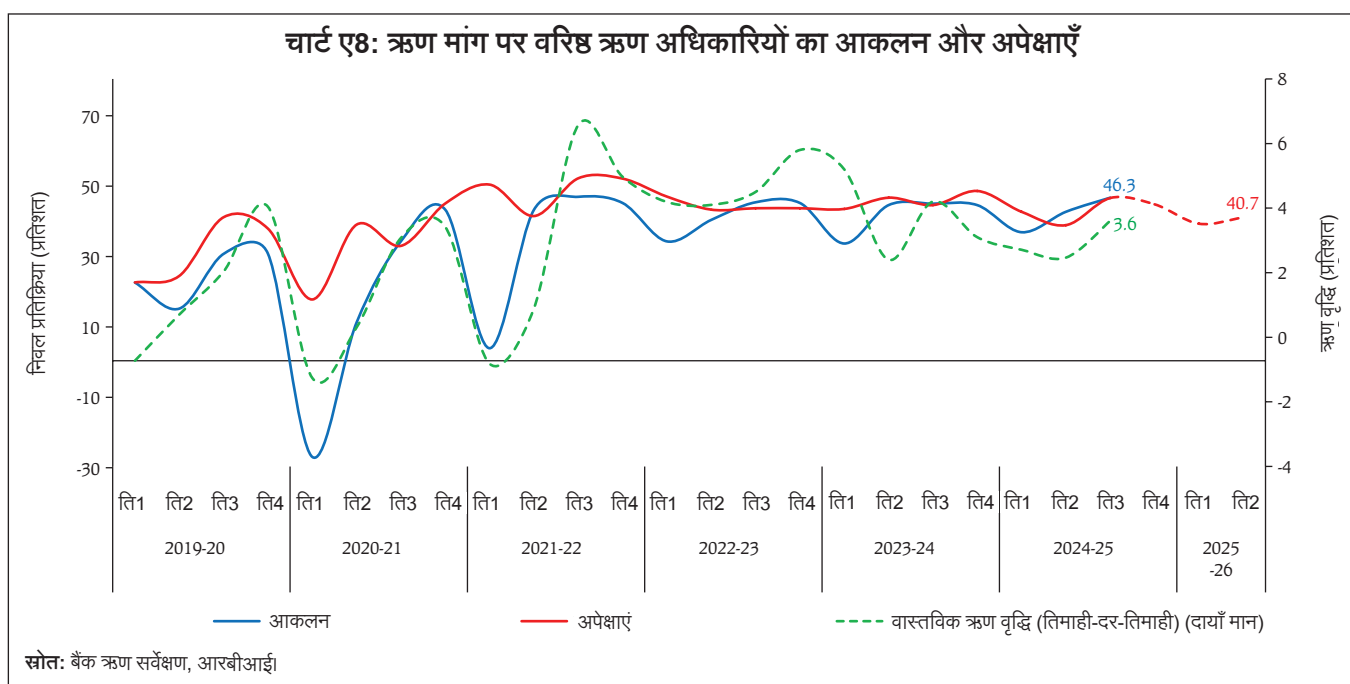




वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के लिए बिक्री मूल्य और लाभ मार्जिन में वृद्धि की गति धीमी होने की उम्मीद है। 2024-25 की चौथी तिमाही में सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बिक्री कीमत और लाभ मार्जिन में उच्च वृद्धि की उम्मीद है (चार्ट ए7)।



बैंकों को उम्मीद है कि ऋण की मांग बढ़ेगी तथा प्रमुख क्षेत्रों में ऋण की शर्तें आसान होंगी (चार्ट ए8)।



टिप्पणी: 'निवल प्रतिक्रिया' की गणना आशावाद की रिपोर्ट करने वाले और निराशावाद की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। वृद्धि विकल्प (I) सभी मापदंडों के लिए एक आशावादी प्रतिक्रिया है, जो लागत से संबंधित मापदंडों को छोड़कर, जैसे कि कच्चे माल की लागत, आदि जहाँ कमी विकल्प (D) उत्तरदाता कंपनी के दृष्टिकोण से आशावाद को दर्शाता है।